डिजिटल मुद्रा

Digital Currency

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा

(संयोजक: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा)

संयोजक: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

डिजिटल मुद्रा

Digital Currency

: संपादक :

पुनीत कुमार मिश्र

सदस्य सचिव - नराकास (बैंक), वडोदरा

एवं सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

: संपादन सहयोग :

सुधा मिश्रा, वरिष्ठ प्रबंधक

हिमानी पटेल, व्यवसाय सहयोगी

समिति सचिवालय
राजभाषा विभाग
प्रधान कार्यालय
"बड़ौदा भवन"
पांचवा तल
आर सी दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
फोन : 0265-2316581
ई-मेल: banknarakas.baroda@bankofbaroda.com

© नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा

प्रथम संस्करण
सन् 2022

इस पुस्तक में अभिव्यक्त विचार, शब्द चयन एवं भाषा संबंधी प्रयोग लेखकों के अपने हैं. नगर समिति अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

आमुख

प्राचीन काल से ही मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है। अर्थव्यवस्था और भुगतान प्रणाली के विकास के साथ-साथ धन के लेन-देन के तरीके और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। पहले जहां लेन-देन के लिए वस्तुओं के आदान-प्रदान का चलन था, समय के साथ उसकी जगह धातु की मुद्रा ने ले ली और सिक्के ढाले जाने लगे. इसके बाद कागजी मुद्रा चलन में आया। आज भी विश्व के अधिकांश देशों में व्यापार और लेन-देन के लिए कागजी मुद्रा का ही प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के बढ़ते दौर में विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से डिजिटल भुगतान/ लेन-देन में काफी वृद्धि हुई है. लोगों में डिजिटल लेन-देन को लेकर विश्वास भी बढ़ा है। आज छोटे-बड़े सभी प्रकार के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। 'डिजिटल मुद्रा' विषय पर प्रकाशित यह पुस्तक डिजिटल मुद्रा एवं इसके विविध आयामों को उजागर करेगी।

बदलते हुए बैंकिंग परिवेश में डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। यह कागजी या भौतिक मुद्रा के समान ही है और इसका कागजी मुद्रा के साथ विनिमय अर्थात् आदान-प्रदान संभव है। डिजिटल मुद्रा का मूल्य भी मौजूदा कागजी मुद्रा के बराबर ही होगा और यह उसी तरह स्वीकार्य होगी. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध इस रुपये को संपर्करहित लेन-देन के लिए उपयोग किया जा सकेगा. यह मुद्रा क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है जो ई-वाउचर के रूप में कार्य करती है। इस कारण **डिजिटल करेंसी** का उपयोग अधिकाधिक लोगों द्वारा किए जाने की संभावना है।

इसी को ध्यान में रखते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा ने 18 जुलाई, 2022 को केवड़िया में **'डिजिटल मुद्रा'** विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें से संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), मुंबई के अंतर्गत आने वाली नगर समितियों के विभिन्न सदस्य कार्यालयों/ शाखाओं के स्टाफ सदस्यों से कई महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट आलेख प्राप्त हुए हैं। इन आलेखों की उपयोगिता और महत्ता को समझते हुए इन्हें पुस्तक के रूप में संकलित किया जा रहा है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन को गति प्रदान करना है। अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नराकास (बैंक), वडोदरा द्वारा समय-समय पर नवोन्मेषी कार्यों/ गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ऐसे सेमिनारों का आयोजन भी इन्हीं जिम्मेदारियों का एक अहम् हिस्सा है।

मुझे विश्वास है कि 'डिजिटल मुद्रा' से संबंधित विविध आयामों पर आधारित आलेखों का यह पुस्तक के रूप में यह संकलन सभी पाठकों को अवश्य ही पसंद आएगा तथा नई संभावनाओं को नई दिशा देने में आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित,

- दिनेश पंत
अध्यक्ष, नराकास (बैंक), वडोदरा एवं
मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन)

अपनी बात

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा में राजभाषा कार्यान्वयन की 36 वर्षों की एक समृद्ध परंपरा रही है. अपनी इस गौरवशाली यात्रा के दौरान समिति ने कई नवोन्मेषी कार्य किए हैं तथा देश भर की विभिन्न समितियों की श्रेणी में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए समिति द्वारा नवोन्मेषी कार्यों की श्रृंखला में **18 जुलाई, 2022 को केवड़िया, गुजरात में 'डिजिटल मुद्रा'** विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस सेमिनार के लिए निर्धारित **02 उप-विषयों (1) डिजिटल मुद्रा का वर्तमान एवं भविष्य (2) डिजिटल मुद्रा का विनियमन: स्थिति एवं चुनौतियां** विषय पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), मुंबई के अंतर्गत कार्यरत सभी नगर समितियों के सदस्य कार्यालयों/ शाखाओं में कार्यरत स्टाफ सदस्यों से आलेख आमंत्रित किए गए थे। सेमिनार के लिए प्राप्त इन विविध आलेखों में से चयनित श्रेष्ठ आलेखों को सेमिनार में पीपीटी प्रस्तुति/ चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया और उन्हें संकलित/ संपादित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

इस संकलन में शामिल आलेख विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ उपक्रमों/ बीमा कंपनियों एवं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसरो, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में कार्यरत अनुभवी एवं कुशल स्टाफ सदस्यों द्वारा लिखे गए हैं जो सुधी पाठकों के लिए सूचनाप्रद सिद्ध होंगे। आलेखों का संकलन तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है और लेखकों की मूल भावना को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। तथापि, आलेखों को संक्षिप्त और प्रभावी बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार उन्हें संपादित भी किया गया है।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक मौजूदा समय में बेहद प्रासंगिक विषय 'डिजिटल मुद्रा' के अलग-अलग पहलुओं को उजागर करने में सफल होगी तथा इसमें प्रकाशित आलेख आप सभी के लिए रुचिकर एवं उपयोगी सिद्ध होंगे।

सादर,

- पुनीत कुमार मिश्र
सदस्य सचिव, नराकास (बैंक), वडोदरा एवं
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा एवं संसदीय समिति)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

अनुक्रमणिका

क्र.	लेखक का नाम	संस्था का नाम	पृष्ठ सं.
डिजिटल मुद्रा का वर्तमान एवं भविष्य			
1.	स्नेहा सिंह	पंजाब नैशनल बैंक	7
2.	अजीत कुमार भारती	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12
3.	अभिषेक बारहठ	पंजाब नैशनल बैंक	17
4.	करण संजय पाल	स्पेस अप्प्लिकेसंस सेंटर, इसरो	21
5.	ज्योति रंजन निधि	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	27
6.	डॉ. बी. एन. शर्मा	अन्तरिक्ष उपयोग केंद्र, इसरो	33
7.	डॉ. मनीष कुमार सोनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	40
8.	तपन कीर्तिकुमार बिलखिया	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	45
9.	दिनेश कुमार	सैक इसरो, अहमदाबाद	50
10.	ध्रुवी तैलवानी	दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड	57
11.	पंकज कुमार मिश्रा	गुजरात रिफ़ाइनरी, वड़ोदरा	63
12.	काशकुमार भलाला	गेल (इंडिया) लिमिटेड, वड़ोदरा	67
13.	प्रदीप कुमार गोयल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	74
14.	मिहिर जोषी	बैंक ऑफ़ इंडिया	81
15.	रुकमी दत्ता	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला	86
16.	विधि चंद्रकांत जटनिया	केनरा बैंक	91
17.	विलास वैष्णव	भारतीय स्टेट बैंक	96
18.	विवेक गुप्ता	गेल (इंडिया) लिमिटेड, वडोदरा	102
19.	विवेक चंद्रकांत जटनिया	न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड	106
20.	शक्तिवीर सिंह	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	111

क्र.	लेखक का नाम	बैंक का नाम	पृष्ठ सं.
डिजिटल मुद्रा का वर्तमान एवं भविष्य			
21.	गौतम कुमार	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	118
डिजिटल मुद्रा का विनियमन : स्थिति और चुनौतियाँ			
1.	बसंत कुमार	भारतीय स्टेट बैंक	125
2.	ममता वारके	पंजाब नैशनल बैंक	131
3.	शोकीन फोगाट	अंतरिक्ष उपयोग केंद्र	139
4.	सुरेश पटेलिया	भाकृअनुप, बोरीयावी, आणंद	145
5.	अमी कार्तिक पटेल	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला	151
6.	पूजा साव	गेल (इंडिया) लिमिटेड, वडोदरा	158
7.	प्रेम रामनाणी	भारतीय स्टेट बैंक	165
8.	सुमन्त कुमार	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	172
9.	चंदन सिंह	सैक, इसरो	174

स्नेहा सिंह

पदनाम:- वरिष्ठ प्रबंधक
संस्था का नाम:- पंजाब नैशनल बैंक
मोबाइल नं. :- 8826152345
ई-मेल:- zoahmraj.pnb.co.in

आज के दौर में आम से लेकर खास तक सबके लिए आवश्यक एवं जरूरी चीजों में से एक है रुपैया। आज के समय में पैसा कमाने के लिए इंसान हर संभव कोशिश करता है ताकि वह अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी एवं अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग बार्टर सिस्टम के जरिए वस्तुओं का लेनदेन किया करते थे लेकिन जैसे-जैसे प्रगति होती गई व्यापार के तरीकों में भी बदलाव आता गया।

पहली बार रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था और उनके राज्य में अर्थव्यवस्था एवं अच्छे शासनकाल को सुनिश्चित करने के लिए रुपए का उपयोग शुरू किया गया। सबसे पहले सिक्कों का उपयोग शुरू किया गया। उस समय सिक्के चांदी, सोने एवं तांबे की धातु के होते थे और उन्हीं सिक्कों से व्यापार भी किया जाता था। लेकिन बदलते समय के साथ आज हम वर्तमान करेंसी का प्रयोग व्यापार में करने लगे।

परंतु अब डिजिटल मुद्रा का चलन लगातार बढ़ रहा है और यह 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है।

प्रस्तावना:

डिजिटल मुद्रा को अगर आम लोगों की भाषा में समझा जाए तो यह वह मुद्रा है जिसे डिजिटल सिस्टम में स्टोर किया जाता है फिर उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाता है। यह देश के नागरिकों और बैंकिंग सेक्टर को ऐसा मौका देगा जिससे पैसे को लेकर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता हुआ नजर आएगा जैसे बैंकों में लंबी लाइन

नहीं लगानी पड़ेगी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ही उनका पैसा होगा। उपयोगकर्ता कुछ ही मिनटों में अपना पैसा कहीं पर भी इस्तेमाल कर करेंगे।

डिजिटल करेंसी के प्रकार:

- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी : यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होगी जो कि ब्लॉक चेन तथा अन्य तकनीकों पर आधारित होगी। अर्थात् यह भारतीय रुपयों का एक डिजिटल रूप होगा।
- वर्चुअल करेंसी : इसका मतलब है आभासी मुद्रा। यह काफी हद तक अनियमित है परन्तु फिर भी जारी की जाती हैं क्योंकि यह प्राकृतिक एवं कानूनी व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत है।
- क्रिप्टो करेंसी: यह क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक स्वतंत्र मुद्रा हैं जो किसी भी सरकार द्वारा लागू नहीं की जाती।

वर्तमान: भारत के वित्त मंत्री के नेतृत्व में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक में भारत सरकार ने सेंट्रल बैंक से डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने की बात रखी। वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल बैंक को डिजिटल करंसी लाने का सुझाव दिया जिससे लोग पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें। भारतीय लोगों का क्रिप्टोकरेंसी की तरफ झुकाव देखकर सरकार ने यह तय किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा तरीका लेकर आए जिससे भारत के लोग अपने पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें और डिजिटली कमा सकें। एक ऐसा तरीका जिससे लोगों का समय भी बचे और और उनके पैसे भी सुरक्षित रहें और साथ ही साथ देश डिजिटल उपकरणों को लेकर स्मार्ट बने।

डिजिटल मुद्रा की ओर अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नई पीढ़ी विशेषकर युवा डिजिटल मुद्रा की ओर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल मुद्रा में निवेश से पहले इसे अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है जिससे कि इसमें निवेश कर अच्छा लाभ कमाया जा सके। डिजिटल मुद्रा लगभग एक दशक पहले ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है पर उसे पहचानने में हमने थोड़ी देरी कर दी। अब डिजिटल मुद्रा को लेकर हमारा रुझान काफी बढ़ गया है या यूं कह लें कि देर आए दुरुस्त आए। अधिकांश केंद्रीय बैंकों को उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा लांच करने पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे न केवल हमारी सोसाइटी का लक्ष्य पूरा होगा बल्कि साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा की कमी भी दूर होगी।

वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन-देन की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया था। परंतु हाल ही में भारत सरकार के साथ हुई बैठक में रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया कि वह सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा विकसित करने की आवश्यकता का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व भर में आज तमाम ऐसे देश हैं जो सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं जिसमें चीन और अमेरिका भी शामिल हैं। ऐसे में भारत का डिजिटल मुद्रा विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा में पीछे रहना उचित नहीं है।

विदेशों में डिजिटल करेंसी की स्थिति

विश्व में 86% सेंट्रल बैंक ऐसे हैं जो अपने कन्वेंशनल पैसों को बदलना चाह रही हैं यानी उन्हें बदलकर इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल बनाना चाह रहे हैं। उदाहरण ब्रिटेन का बैंक, चाइना का बैंक, अमेरिका का बैंक। इस विषय पर अन्य देशों में चर्चा भी हो रही हैं तथा कुछ देशों में अभ्यास करते हुए पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार कई देशों ने डिजिटल करेंसी पर अपना काम करना शुरू कर दिया है जैसे कि चीन भी अपनी डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करके मुद्रा और भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

डिजिटल मुद्रा की विशेषताएं :

1) डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।
2) डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा।
3) डिजिटल करेंसी से लोगों को नगद रुपयों पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा।
4) रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग जाता है उसमें भी कमी आएगी।
5) पैसा जमा कराने और निकलवाने का तरीका आसान होगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा।
6) डिजिटल करेंसी से लोगो को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा महसूस होगी और उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे।
7) डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को देशांतर्गत तथा बाहरी देशों में पैसे के लेनदेन के लिए अधिक समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और धोखाधड़ी भी कम होने लगेगी।
8) डिजिटल मुद्रा भारत को अपने साझेदारों के साथ व्यापार हेतु लेन-देन की मुद्रा के रूप में रुपये का प्रभुत्त्व स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही कम हो जाएगी।

अधिकृत डिजिटल मुद्रा के लाभ :

- ✓ डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगा सकता है।
- ✓ केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को किसी संपत्ति अथवा पारंपरिक मुद्रा का समर्थन प्राप्त होगा, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे एथरियम और बिटकॉइन की तरह अस्थिर नहीं होगा।
- ✓ डिजिटल रुपए के उपयोग से रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष रुप से मुद्रा सृजन और आपूर्ति की शक्ति प्रदान होगी, जिससे नीतिगत बदलावों के प्रभावों को तत्काल प्रतिबिंबित किया जा सकेगा, क्योंकि अब तक रिज़र्व बैंक अपने नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर है।

भविष्य:

भविष्य में डिजिटल करेंसी को भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2022-23 को डिजिटल करेंसी के आगमन का समय माना जा रहा है। यदि भारत सरकार का डिजिटल मुद्रा लांच करने का फैसला अच्छा साबित हुआ तो यह भारत की डिजिटल क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित होगा। यह भारत की करेंसी को एक सस्ते और कुशल करेंसी सिस्टम की ओर ले जाता हुआ साबित होगा।

डिजिटल करेंसी से नुकसान :

- किसी भी सिक्के के दो पहलु होते हैं। फायदों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। यदि डिजिटल करेंसी देश के लिए काफी अच्छा बदलाव साबित होगी तो वह अपने साथ कुछ नुकसान भी लेकर आएगी।
- डिजिटल मुद्रा आने से हो सकता हैं कि बैंकों का कारोबार कम हो जाए क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक ही बन जाएगा।
- डिजिटल करेंसी के आने से बैंकों में कर्मचारियों को काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि इस मुद्रा के आने से बैंक मैनपावर कम कर सकते हैं और इससे बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जॉब की सुरक्षा को लेकर परेशानी महसूस हो सकती हैं।

डिजिटल मुद्रा की सुरक्षा

- अधिकांश डिजिटल मुद्रा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनायी जाती है, इसमें डेटा को ब्लॉक में दर्ज करके उसपर मुहर लगा दिया जाता है। हैकर्स का इस नेटवर्क के

साथ छेड़छाड़ करना अत्यधिक कठिन है। हालाँकि इसके भी कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद है, जहां न केवल इन खातों के साथ छेड़छाड़ की गई बल्कि उन्हें हैक भी कर लिया गया था।

निष्कर्ष:

डिजिटल मुद्रा की कानूनी स्थिति एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती है। कुछ देशों ने स्पष्ट रूप से उनके उपयोग और व्यापार की अनुमति दी है तो कुछ देशों ने इसे प्रतिबंधित किया हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेजी से उभरती वैश्विक डिजिटल व्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में मदद करेगा। साथ ही इससे भारतीय नागरिकों को देश की पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्ति मिलेगी और भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम जुड़ सकेगा। डिजिटल रुपया रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपकरण प्रदान कर और अधिक सशक्त बनाएगा।

अर्थव्यवस्था में तरलता, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ार आदि पर डिजिटल रुपए के प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत के नीति निर्माताओं द्वारा भारत में सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नियामकों को अर्थव्यवस्था में लेन-देन और ऋण प्रवाह की निगरानी में मदद करेगा, जिससे घोटालों और धोखाधड़ी की निगरानी करने में सहायता मिलेगी और जमाकर्ताओं के पैसे को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

इसके अलावा यह निवेशकों को मौजूदा अत्यधिक जोखिम वाली डिजिटल मुद्रा की तुलना में एक अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा।

बैंकिंग प्रणाली पर, डेटा गोपनीयता पर, मौद्रिक नीति पर इसके प्रभाव के संदर्भ में कौन सा मॉडल काम करेगा, कौन सा डिजाइन अच्छी तरह से काम करेगा, इस संदर्भ में भारी अनिश्चितताओं को देखते हुए, लगभग सभी केंद्रीय बैंक को इस दिशा में बहुत ही सावधानीपूर्वक और समन्वित तरीके से आगे बढ़ना होगा। इस तरह डिजिटल रुपया वित्तीय नवाचार की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण है।

*****

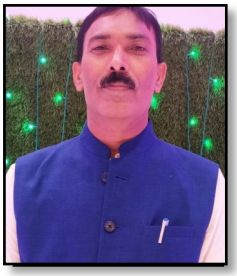

अजीत कुमार भारती

पदनाम:- विशेष सहायक
संस्था का नाम:- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मोबाइल नं. :- 9016496846/ 7226913980
ई-मेल:- bharatiajeet@yahoo.com

डिजिटल मुद्रा एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रोनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है। कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से डिजिटल मुद्रा को संस्थाओं या उपयोगकर्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है, यद्यपि यह भौतिक मुद्राओं के समान है डिजिटल धन स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ तात्कालिक लेन देन की अनुमति देता है। डिजिटल मुद्राओं का उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है।

जब किसी देश की मुद्रा को डिजिटल सिस्टम में स्टोर किया जाता है और उसे इलेक्ट्रोनिक रूप में उपयोग किया जाता है उसे हम डिजिटल मुद्रा कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे की आप के पैसों का एक इलेक्ट्रोनिक रूप का इलेक्ट्रोनिक टोकन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक प्लैटफ़ार्म में उपयोग किया जाने वाला। डिजिटल मुद्रा देश के नागरिकों और बैंकिंग सैक्टर को ऐसा मौका देगा जिससे पैसे को लेकर सब कुछ इलेक्ट्रोनिक होता हुआ नजर आए, जैसे बैंकों में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और बस इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर सैकंडों में उनका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा या फिर कुछ ही मिनटों में वे अपने पैसे का उपयोग कर सकेंगे।

भारत सरकार डिजिटल मुद्रा इसलिए लांच करना चाहती है कि आज कल डिजिटल मुद्रा का जमाना है और भारत अन्य देशों से पीछे नहीं रहना चाहता। हम सब की तरह सरकार ने भी मान लिया है कि इस मुद्रा को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार ने वर्चुअल करेंसी के वजूद को नकारने के बजाय अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लांच करने का फैसला किया है। नियमित करेंसी के विपरीत आपको डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए बैंक खातों की आवश्यकता नहीं होगी, चूंकि यह एक ब्लॉक चैन पर आधारित होगा, इसलिए आप इसे सीधे दूसरे व्यक्ति के डिजिटल रुपए वाले वालेट मे ट्रांसफर कर सकते हैं।

डिजिटल मुद्रा के कई लाभ हैं जैसे समय पर आसानी से भुगतान करने की क्षमता और कम लेनदेन लागत। एक अन्य तरीका जिसमे डिजिटल मुद्राएं संगठन की मदद कर सकती हैं वह परिवहन मुद्रा के रूप में जोखिम को समाप्त करना/कम करना है।

वर्तमान में डिजिटल मुद्राएं बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती हैं और परिणामस्वरूप, व्यक्तियों या संगठनों द्वारा उन पर ब्याज अर्जित नहीं किया सकता। सुरक्षा, मुद्रा अस्थिरता और भुगतान लाभार्थी पहचान जैसी डिजिटल मुद्राओं से जुड़े जोखिम भी हैं। अनिश्चितता के कुछ क्षेत्र जैसे नियमों का अनुपालन और जोखिम के साथ ग्राहक पहचान, भुगतान उद्योग में डिजिटल मुद्राओं की स्वीकृति को सीमित करते हैं।

डिजिटल मुद्रा का लेनदेन मूलतः इंटरनेट पर होता है। डिजिटल वॉलेट एक तरह का अकाउंट है जिसमें आप अपनी डिजिटल मुद्रा रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल मुद्रा का एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होता है। इस प्रक्रिया में हमे बैंक के माध्यम से जाने कि जरूरत नहीं पड़ती। डिजिटल वॉलेट को फोन, कम्प्यूटर या अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। आप डिजिटल मुद्रा को किसी भी अन्य मुद्रा जैसे रुपया, डॉलर आदि के बदले में डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं।

इस डिजिटल मुद्रा को मुद्रा के रूप में गिना जाएगा, इससे सरकार को कम नोट छापने और नकली मुद्रा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली बनाने में मदद करेगा। नियमित रुपए के विपरीत, डिजिटल रुपए के ऑनलाइन लेनदेन के लिए बैंक मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेषक और प्राप्तकर्ता ब्लॉक चेन का उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं।

डिजिटल मुद्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीक (टेक्नोलॉजी) है। तकनीक के कारण धोखाधड़ी और घोटालों के मामले बढ़ सकते हैं। खुद आरबीआई गवर्नर कई मौको पर कह चुके हैं की डिजिटल मुद्रा के साथ धोखाधड़ी सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर किसी देश में उन्नत तकनीक कम है तो वहां सीबीडीसी (CBDC) की पहुँच और उपयोगिता काफी कम हो जाएगी।

डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को अपने देश के बाहर या फिर देश के भीतर निधि अंतरण करने के लिए या फिर जमा करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी जिससे

बैंकिंग धोखाधड़ी में कमी आएगी। यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी नई चीज के आने से जितना फायदा होता है उतना ही वह अपने साथ कुछ नुकसान भी लेकर आती है। ठीक उसी तरह यदि डिजिटल मुद्रा देश के लिए काफी अच्छा बदलाव साबित होगी तो वह अपने साथ कुछ नुकसान भी लेकर आएगी, डिजिटल मुद्रा के कुछ नुकसान निम्न है:-

डिजिटल मुद्रा के आने से बैंकों में कर्मचारियो को काफी नुकसान हों सकता है क्योंकि इस मुद्रा के आने से बैंको में मैनपावर कम हो जाएगी।

ऐसा हो सकता है कि कितने ही सारे बैंको का कारोबार कम हो जाएगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रोनिक रूप से होगा और पैसा भी इलेक्ट्रोनिक ही बन जाएगा।

वर्तमान

भारतीयों के क्रिप्टो करेंसी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव को लेकर सरकार ने यह तय किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीका लेकर आए जिससे लोग पैसों को डिजिटली प्राप्त कर सकें, एक ऐसा तरीका जिसमें लोगो का समय भी बचे और उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और साथ ही साथ यह देश डिजिटल उपकरणों को लेकर स्मार्ट बने। वर्तमान में डिजिटल मुद्राएं बैंको द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है और परिणामस्वरूप, व्यक्तियों या संगठनों द्वारा उन पर ब्याज अर्जित नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा, मुद्रा स्थिरता और भुगतान लाभार्थी पहचान जैसे डिजिटल मुद्राओं से जुड़े जोखिम भी हैं। अनिश्चितता के कुछ क्षेत्र जैसे नियमों का अनुपालन और जोखिम के साथ ग्राहक पहचान, भुगतान उद्योग से डिजिटल मुद्राओं की स्वीकृति को सीमित करते है।

1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किए गए यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया कि वर्ष 2022-23 में डिजिटल मुद्रा कि शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो भारतीय क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं उन्हें 30% तक का भुगतान करना पड़ेगा। भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डिजिटल करेंसी को लॉंच करने की तैयारी कर रही है। डिजिटल मुद्रा से सरकार यह ट्रैक कर सकेगी की आप ने पैसे का उपयोग कहां और कैसे किया है। यह गोपनीयता की चिंताओ को जन्म देगा क्योंकि इसमें शामिल पक्षों के वित्तीय लेनदेन का दुरुपयोग किया जा सकता है।

कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह तभी होगा जब संसद क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का विनियमन पारित करेगी, जो आरबीआई को डिजिटल मुद्रा जारी करने का अधिकार देगा, हो सकता है कि इस बिल को अगले वर्ष के मानसून या शीतकालीन सत्र में पेश किया जाए।

भविष्य

अवैध गतिविधियों पर रोक- एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी के अराजक डिज़ाइन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें डिजिटल मुद्रा के सृजन और रख-रखाव की शक्तियां प्रयोगकर्ताओं अथवा उपभोगताओं के पास होती है।

बिना किसी सरकारी निगरानी और सीमा पार भुगतान में आसानी के कारण इस प्रकार की डिजिटल मुद्रा का उपयोग प्रायः चोरी, आतंकी फंडिंग, मनीलॉन्ड्रिंग आदि के लिए काफी आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित करके केन्द्रीय बैंक इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगा सकता है।

अस्थिरता- चूंकि डिजिटल मुद्रा किसी भी संपति अथवा मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं होती है और इसका मूल्य केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए बिटकॉइन जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में काफी अस्थिरता देखने को मिलती है।

केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को किसी संपति अथवा पारंपरिक मुद्रा का समर्थन प्राप्त होगा जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे एथरियम और बिटकॉइन की तरह स्थिर नहीं होगा।

राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण- अंतराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें शामिल होने वाले लगभग 80% केन्द्रीय बैंकों ने यह स्वीकार किया हैं कि वे किसी न किसी रूप में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा चीन भी अपनी डिजिटल मुद्रा (रेनमिनबी) को लॉंच करके मुद्रा और भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए डिजिटल करेंसी को लांच करना न केवल वित्तीय प्रणाली में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि यह राजनीतिक दृष्टि से काफी आवश्यक है।

डिजिटल मुद्रा छद्म युद्ध: - चीन अपनी डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देकर एक नए और उन्नत वैश्विक वित्तीय सिस्टम की स्थापना का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए बीते दिनों अमेरिका की सोशल कंपनी फेसबुक ने लिब्रा नामक क्रिप्टोकरेंसी लांच करने की घोषणा की थी, जिससे चीन की डिजिटल मुद्रा से मुक़ाबले के लिए अमेरिका की डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

इस तरह डिजिटल मुद्रा न केवल वित्तीय नवाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच इस छद्म युद्ध में भारत की स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।

डॉलर की निर्भरता को कम करना- यह भारत को अपने सामरिक साझेदारों के साथ व्यापार हेतु लेनदेन की मुद्रा के रूप में डिजिटल मुद्रा के प्रभुत्व को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही कम हो जाएगी।

डिजिटल मुद्रा का निर्माण भारत को नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप उपयोग करने तथा पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

माइक्रो इकॉनमी तरलता, बैंकिंग सिस्टम एव मुद्रा बाज़ारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति निर्माताओ के लिए भारत में डिजिटल मुद्रा की संभावनाओ पर विचार करना अनिवार्य हो गया है।

स्रोत- द हिन्दू, नव भारत टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स।

*****

अभिषेक बारहठ

पदनाम:- राजभाषा अधिकारी
संस्था का नाम:- पंजाब नैशनल बैंक
मोबाइल नं. :- 9079217385
ई-मेल:- abhishekbarhath0507@gmail.com

आज के समय में पूरा विश्व आधुनिकता की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसी दौर में कार्य व्यवहार को अधिकांश डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उच्च सार्वजनिक मांग के कारण हाल के दिनों में डिजिटल मुद्राओं के प्रति एक अप्रत्याशित सी रुचि देखने को मिल रही है। समय के साथ ही मुद्रा के स्वरूप मे भी परिवर्तन होता रहता हैं। वस्तु विनिमय से प्रारम्भ हुई मुद्रा प्रणाली की यात्रा मे अनेक मुद्राओं का आविर्भाव हुआ। आज के तकनीकी एवं डिजिटल के युग मे डिजिटल मुद्रा का महत्व बढ़ता जा रहा है। डिजिटल मुद्रा उस आभासी मुद्रा को कहा जाता है जिसमे कोई भी मुद्रा, पैसा या पैसे जैसी कोई भी संपत्ति जो डिजिटल प्रणाली पर विशेष रूप से इंटरनेट पर संग्रहीत, प्रबंधीत या उसकी अदला-बदली की जाती है, डिजिटल मुद्रा की श्रेणी मे रखी जाती है। इसे डेटाबेस या डिजिटल फाइलों एवं संग्रहीत मूल्य कार्डो के अंतर्गत संग्रहीत करके रखा जाता है। जिसके प्रकारो में क्रिप्टोकरेंसी, बिटकोइन डोगकोइन एवं लिब्रा प्रमुख है जो हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी रही।

वर्तमान स्वरूप: आज के इन डिजिटल मुद्राओं के दौर की वास्तविक शुरुआत आज से एक दशक पहले क्रिप्टोकरेंसी के आगमन के साथ हुइ थी और बहुत ही कम समय के अंतराल में इसने पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली है। मुद्रा के बदलाव की इस कड़ी मे हमारा भारत भी अछूता नही रहा है। अलग-अलग प्रकाशित हुए रिपोर्टों के आधार पर भारत में अलग अलग डिजिटल मुद्राओं में उपयोगकर्ताओं की संख्या एक करोड़ से भी अधिक हो गयी है। कम समय में अधिक धन अर्जित करने की लालसा ने इन मुद्राओं के प्रति लोगों में विशेषकर युवा पीढ़ियों में अत्याधिक आकर्षण देखने को मिलता है। इन मुद्राओं के निवेशकों मे दो तिहाई से अधिक संख्या की औसत उम्र 25 वर्ष है जो इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी इन मुद्राओं की तरफ

ज्यादा आकर्षित है। विश्व के अनेक देशों ने अपनी अपनी डिजिटल मुद्राओं को विधिवत मान्यता दी है जिसमे अल-साल्वाडोर ने सबसे पहले बिटकोइन नामक डिजिटल मुद्रा को मान्यता प्रदान की। हाल ही में भारत सरकार ने इन मुद्राओं के प्रयोग के परिणामों के अध्ययन के आधार पर अपने बजट में एक नई डिजिटल मुद्रा को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य (पक्ष और विपक्ष में तर्क)

कागजी मुद्रा के कम होते उपयोग के साथ मुद्रा के इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म को और अधिक लोकप्रिय और सशक्त बनाने की आवश्यकता है जिससे की भविष्य की मांगो को पूरा किया जा सके। तेजी से प्रचलित हो रही इन डिजिटल मुद्राओं मे भविष्य की अपार संभावना भी छुपी हुई हैं। इन्ही संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भविष्य में अपनी "डिजिटल रुपया" नामक डिजिटल मुद्रा को लॉच करने के संकेत भी दिये है। परंतु जिस तेजी से यह प्रचलित और प्रसारित हो रही है उतनी ही तेजी से इसके नुकसान एवं जोखिम भी बढ़ रहे है।

डिजिटल मुद्रा के पक्ष में तर्क :

- चूंकि डिजिटल मुद्राएँ "पीयर टू पीयर" नेटवर्क प्रणाली पर चलती हैं इसलिए यह धन के प्रवाह और उसके लेनदेन को आसानी से ट्रैक कर सकते है।
- डिजिटल मुद्रा से समय को प्रभावी ढंग से बचाया जा सकता है, यह इंटेरनेट आधारित है जिससे समय और अन्य लेनदेन के शुल्क भी बहुत कम लगते है।
- डिजिटल मुद्रा वाणिज्यिक बैंको के साथ लेनदेन के अंतगर्त होने वाले जमाकर्ताओं के जोखिम को कम करेगी।
- यह सीमा पार होने वाले भुगतानों के निपटान के लिए होने वाले कोरेस्पोंडेट बैंको के बहुत ख़र्चीले नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।
- भारत से बाहर काम करने वाले भारतीयों के लिए अपने घर पैसा भेजना और अधिक आसान हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिए एक बड़ी बचत का निर्माण होगा।
- उपभोक्ताओ के लिए डिजिटल मुद्रा एक सुरक्षित जमा का विकल्प बन सकती है।

डिजिटल मुद्रा के विपक्ष में तर्क

- मौजूदा समय में डिजिटल मुद्रा उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा करती है क्यूंकि अभी तक यह कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है। इसलिए यहां कोई सोवरेन गारंटी नहीं है।

- डिजिटल मुद्राओं की अभी की प्रकृति सट्टा प्रकार की है जो इन्हे अत्यधिक अस्थिर बना देती है। उदाहरणस्वरूप बिटकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा का मूल्य दिसम्बर 2017 मे 20000 अमेरिकी डॉलर था जो नवम्बर 2018 मे गिरकर 3800 अमेरिकी डॉलर हो गया। जो इन मुद्राओं की अस्थिरता को दर्शता है।
- इंटरनेट आधारित इन डिजिटल मुद्राओं पर हमेशा ही सुरक्षा और मैलवेयर से संबन्धित जोखिम रहता है,जो इनकी विश्वनीयता को कम करता है।
- एक केन्द्रीय बैंक अपनी सीमा के बाहर की डिजिटल मुद्राओं जैसे बिटकोइन की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके व्यापक उपयोग होने की स्थिति में वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

भारत सरकार और आरबीआई की डिजिटल मुद्रा पर भूमिका

भारत जैसे युवा मानव संसाधन से परिपूर्ण देश में ऐसी डिजिटल मुद्राओं की संभावना और अधिक बढ़ जाती हैं। डिजिटल मुद्रा के प्रचलन एवं व्यापकता में सरकार और उसके केंद्रीय बैंक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के शुरुआती नुकसान को देखते हुए वर्ष 2018 में आरबीआई ने एक परिपत्र जारी कर बैंको को ऐसे क्षेत्र में कार्य करने से प्रतिबंध लगाया था परंतु एस परिपत्र को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हल ही में सरकार ने अपनी एक स्वतंत्र डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए और अन्य सभी डिजिटल मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कृप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक पेश करने की घोषणा की है। अभी प्रचलित डिजिटल मुद्राओं पर 30 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा भी की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार में प्रचलित अन्य डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने के लिए अपनी एक डिजिटल मुद्रा "डिजिटल रुपया" लॉच करने की भी घोषणा की है।

विनियमित और सरकार द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा का प्रयोग और निर्माण,भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और निरंतर रूप से बढ़ रही हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने एवं पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने का अवसर प्रदान करेगा। आज पूरा विश्व डिजिटलिकरण की तरफ बढ़ रहा है तथा अपनी स्वयं की डिजिटल मुद्रा लॉच कर रहा है। भारत वर्तमान में डिजिटल क्रांति के चरण में अग्र पंक्ति में खड़ा है जहां वह इसमें अपनी मानव पूंजी, विशेषज्ञता, तकनीक और संसाधनों को शामिल करके विश्व में एक मज़बूत किरदार के रूप में

उभरने की क्षमता रखता है। डिजिटल मुद्रा के भविष्य की अपार संभावना एवं एक मजबूत विकल्प के रूप में देखकर इसके अनुरूप नीति निर्धारण की आवश्यकता है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी नियमों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित किया जाए एवं इसको विनियमित कर इसका उपयोग लिया जाए।

संदर्भ सूची

- दैनिक जागरण समाचार पत्र के लेख
- ईकोनोमिक्स टाइम्स समाचार पत्र के लेख
- भारत सरकार बजट 2022-2023
- आरबीआई वैबसाइट पर उपलब्ध भाषण
- द हिन्दू समाचार पत्र के लेख
- दृष्टि मासिक पत्रिका के लेख
- पीआईबी वैबसाइट पर उपलब्ध लेख
- नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के लेख
- जनसत्ता समाचार पत्र के लेख

*****

करण संजय पाल

पदनाम:- तकनीकी सहायक
संस्था का नाम:- स्पेस अप्प्लिकेसंस सेंटर, इसरो
मोबाइल नं. :- 7874593130
ई-मेल:- karan.102pal@gmail.com

आदि काल से विश्व भर में मुद्रा के रूप में अलग-अलग वस्तुओं एवं सामग्रियों का प्रयोग किया जाता रहा है। प्राचीन काल में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के बदले दिया जाता था। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी की सामग्री है लेकिन अनाज नहीं है तथा किसान के पास अनाज है परन्तु मिट्टी की सामग्री नहीं, इस स्थिति में वे दोनों आपस में अपने अतिरिक्त वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुएं प्राप्त किया करते थे। इस तरह के चलन को "वस्तु विनिमय पद्धति" कहते हैं। आगे चलकर इस चलन की भी कुछ कमियां उभरकर आईं जैसे यदि कुम्हार को अनाज की आवश्यकता है परन्तु किसान को मिट्टी की वस्तु की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में कुम्हार मिट्टी की अतिरिक्त वस्तुओं का स्वामी होकर भी अनाज पाने से वंचित रह जाता। ऐसी चुनौती ने ही भौतिक मुद्रा को जन्म दिया।

भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के समय के "पंच चिंहित मुद्रा" प्राप्त हुई है। हालांकि, इस बात पर कोई सर्वसम्मति नहीं है कि प्राप्त मुद्रा का प्रयोग दैनिक चलन में होता होगा। पहली प्रलेखित मुद्रा 6ठी - 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जारी किये गए "पंच चिह्न" मुद्राओं से शुरू मानी जाती है। इन मुद्राओं को इनके निर्माण तकनीक के कारण इन्हें "पंच चिह्न" मुद्रा कहा जाता है। अधिकतर मुद्राएं चांदी से बनी होती थीं, जिनमें अलग-अलग के पंच की सहायता से चिह्न अंकित किये गए थे। उसके बाद, भारतीय इतिहास में कई राजवंशों की याद में मुद्रा बनाई गई थी जेसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, आदि। आज स्वतंत्र भारत में मुद्रा निर्माण करने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। विभिन्न मूल्यवर्गों की मुद्राओं की डिजाईन, ढलाई एवं खनन भारत के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित भारत सरकार के चार टकसालो में किया जाता है। परंतु इस चलन में भी कुछ

कमियां दिखने लगी हैं। भारी मात्रा में मुद्रा को सुरक्षित रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बड़े सौदों में नगद पैसों में लेनदेन सुविधाजनक नहीं लगीं, फिर भारत में बैंकों का आगमन हुआ और नगद मुद्राओं की मूलभूत समस्याओं से निपटने का एक प्रभावी विकल्प मिला। बैंक एक वितीय संस्था है जो अपने ग्राहकों के वित्तीय लेन-देन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है।

आज अधिकतर वितीय सुविधाएं बैंक के जरिए ही आम लोगों तक पहुंचती है। बैंक ने आधुनिक वित्तीय व्यवस्था की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में हुई थी। सन् 1770 में देश के पहले बैंक, "बैंक ऑफ़ हिंदुस्तान" की स्थापना हुई। देश का सबसे पुराना बैंक "भारतीय स्टेट बैंक" है जो आज की तारीख में भी कार्यरत है तथा पूरे विश्व में बैंक शाखाओं के मामले में सबसे बड़ा है। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1806 के मध्य में बैंक ऑफ़ कोलकाता के नाम से हुई। वर्ष 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया। आज भारतवर्ष में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 11 लघु वित्त बैंक, 43 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, 46 विदेशी बैंक, आदि को मिलाकर कुल लगभग 145 बैंक कार्यरत हैं। परंतु अब प्रश्न यह है कि यदि बैंक से हमारे वित्तीय काम सहज और सुरक्षित रूप से पूर्ण हो जा रहे हैं तो डिजिटल मुद्रा का क्या काम?

इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अजय राशन खरीदने दुकान जाता है और ऑनलाइन बैंकिंग अथवा यूपीआई से भुगतान करता है। हालांकि आम तौर पर लेन-देन सटीकता से हो जाती है परन्तु तकनीकी कारणों से कभी-कभी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या नकद मुद्रा के चलन में नहीं थी क्यूंकि अजय और दुकानदार दोनों परस्पर हाथों-हाथ मुद्रा का उपयोग करते होते और इसमें कोई तृतीय पक्ष शामिल नहीं है। परंतु बैंक से भुगतान के मामले में अजय और दुकानदार के बीच बैंक भी शामिल रहता है जो इस पूरी प्रक्रिया में तृतीय पक्ष की भूमिका निभाता है। यदि बैंक का सर्वर बंद हो जाय और भुगतान संभव ना हो सके तो? यदि बैंक के सर्वर में तकनीकी समस्या के चलते अजय के खाते से पैसे कट गए और दुकानदार के खाते में जमा न हुए तो? यदि अजय के खाते से पैसे से बिना कटे दुकानदार के खाते में जमा हो गए तो ? जब मूल्य अजय को दुकानदार को चुकाने है तो बैंक को शुल्क क्यों दे? इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बैंक कटिबद्ध है परंतु बैंक तो तृतीय पक्ष की भूमिका में है। अन्य शब्दों में बैंक न तो सामान खरीद रहा है और न ही बेच रहा है। इसलिए

अजय और दुकानदार को स्वाभाविक रूप से बैंक पर विश्वास करने में सहजता नहीं होगी।

डिजिटल मुद्रा यहाँ एक कदम आगे है। डिजिटल मुद्रा वास्तव में एक डिजिटल संपत्ति है जिसे हम कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से व्यावहारिक चलन में उपयोग कर सकते हैं। यह कोई भौतिक मुद्रा नहीं बल्कि आभासी मुद्रा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि बैंको से परे किसी केन्द्रीय प्राधिकरण जैसे सरकार या बैंक पर निर्भर नहीं है। अब यह प्रश्नन स्वाभाविक तौर पर उठता है कि यदि डिजिटल मुद्रा कंप्यूटर में संगृहीत है तो किसी कंप्यूटर फाइल की तरह उसकी कोई अनेक नकल नहीं बना सकता ? तो इसका उत्तर है नहीं।

दरसल डिजिटल मुद्रा "ब्लॉकचैन" टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचैन डिजिटल मुद्रा की लेन-देन, अतिरिक्त मुद्राओं के निर्माण का नियंत्रण और मुद्राओं के स्वामित्व के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफ़ी का उपयोग करता है। क्रिप्टोग्राफ़ी एक एसी तकनीक है जो गणित के मूलभूत सिद्धांतों की सहायता से सन्देश को गुप्त रखते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर, डिजिटल हस्ताक्षर, गुप्त क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी साझा करना, संदेश की अखंडता को परखना, आदि अत्यंत जटिल कार्य संभव बनाती है। क्रिप्टोग्राफ़ी सही मायने में आज के डिजिटल जगत का ताला है जो हमें व हमारे डेटा को इंटरनेट की विशाल दुनिया में सुरक्षित रखता है। डिजिटल मुद्रा से की गई हर लेन-देन एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में अंकित की जाती है। इससे हम आम शब्दों में डिजिटल मुद्रा का बहीखाता भी कह सकते हैं। यह बहीखाता ब्लॉकचैन तकनीक से सुरक्षित रहता है।जैसे ही कोई लेन-देन होता है, इस बहीखाते में इसकी जानकारी अंकित होती है। परंतु सबसे आवश्यक बात यह है कि इस जानकारी के साथ एक कंप्यूटर कोड भी अंकित किया जाता है। यह कोड अत्यंत कठिन गणित की पहेली सुलझाने के बाद प्राप्त होता है जो कई ताकतवर कंप्यूटर साथ में मिलकर हल करते हैं। गणित की यह पहेली बहीखाते के पिछले लेन-देन से प्राप्त होती है। और इस लेन-देन की मदद से अगले लेन-देन की पहेली प्राप्त होगी। अब क्यूंकि प्रत्येक लेन-देन का एक ब्लॉक है जिसकी मदद से अगला ब्लॉक बनाया गया है, कोई भी ब्लॉक को बदल नहीं सकता, यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो उस ब्लॉक का कोड बदल जायेगा और अगले सारे ब्लॉक्स अमान्य हो जायेंगे। इसी कारण से इसे ब्लॉकचैन कहा जाता है।

डिजिटल मुद्रा को संचालित करने के लिए माइनर्स की आवश्यकता होती है जो ऊपर दी गयी पहेलियों को सुलझाने का काम करते हैं। सारे माइनर्स का एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें सारे निर्णय सभी माइनर्स की आपसी सहमति से लिए जाते हैं। यदि माइनर। ने पहेली को सुलझा लिया तो कम से कम 60% माइनर्स को भी इस बात से सहमत होने चाहिए तभी वह लेन-देन उचित माना जाएगा। इतनी कठिन पहेली को बुझाने में माइनर्स को काफी कंप्यूटिंग संपदा एवं उर्जा की जरूरत होती है। इस सेवा के फलस्वरूप माइनर्स को भी डिजिटल मुद्रा दी जाती है।

दुनिया का प्रथम डिजिटल मुद्रा, "बिटकॉइन" वर्ष 2009 में सातोशी नकामोटो ने बनाया। जून 2021 आते-आते साल्वाडोर(देश का नाम) बिट कॉइन को कानूनी मान्यता देनेवाला पहला देश बन गया। इसका सरल सब्दो में अर्थ है के साल्वाडोर की सरकार बिटकॉइन को कानूनी रूप से स्वीकार करती है। डिजिटल मुद्रा डिजिटल क्रिप्टो वॉलेट में से ख़रीदे और बेचे जाते हैं। आज विश्व की काफी दुकानों में डिजिटल मुद्रा स्वीकार्य है। यह बैंक की तरह ग्राहकों से शुल्क नहीं वसूलती, केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर नहीं बल्कि माइनर्स की वितरित प्राधिकरण से नियंत्रित होती है, और तकनीकी रूप से बेहतर भी है। जहां विदेश में मुद्रा भेजने में बैंक हफ्तों का समय और भारी शुल्क लेते हैं वहीं डिजिटल मुद्रा मामूली या बिना किसी शुल्क के पैसे विदेश भेज सकता है। अब हमारे उदाहरण अनुरूप यदि अजय को दुकानदार को भुगतान करना है तो वह डिजिटल मुद्रा से इसलिए करेगा क्यूंकि बीच में कोई तृतीय पक्ष शामिल नहीं है।

परन्तु आज के समय में डिजिटल मुद्रा मात्र एक डिजिटल संपत्ति बन कर रह गया है। लोग इसे खरीद कर ऊंचे मूल्य पर बेचने के लिए रख देते हैं न कि कोई चलन के लिए उपयोग करते हैं। दरसल डिजिटल मुद्रा का मूल्य भौतिक मुद्रा की भांति निर्धारित नहीं होता। भौतिक मुद्रा का मूल्य उस देश के खनिज संपत्ति, विदेशी मुद्रा भंडार, आदि कोई ठोस मूल्यवान वस्तु के ऊपर निर्धारित की जाती है अर्थात् जिस देश की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी उस देश के मुद्रा का मूल्य भी उतना ही अच्छा होगा। परन्तु डिजिटल मुद्रा के पीछे इस तरह की कोई भौतिक वस्तु नहीं होती इसलिए इसके मूल्य को नियंत्रित करने हेतु कठिन पहेलियों का उपयोग किया जाता है। यानी जितनी कठिन पहेली उतना अधिक मूल्य। परन्तु यह बात भी सत्य है कि डिजिटल मुद्रा भी असीमित नहीं है। एक समय सारे कठिन पहेलियां समाप्त हो जायेंगी और उस श्रेणी का

कोई नया मुद्रा नहीं निकाला जा सकेगा। डिजिटल मुद्रा का मूल्य काफी हद तक उसकी मांग पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका मूल्य काफी परिवर्तनशील रहता है।

हमें आज भले ही डिजिटल मुद्रा की प्रासंगिकता साफ़ तौर पर दिखाई न दे रही हो परन्तु भविष्य के गर्भ में डिजिटल मुद्रा के लिए असीमित अवसर निहित हैं। भविष्य में आभासी दुनिया एक नया आयाम खड़ा कर देगी। हाल ही में फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़कुर्बेर्गने अपनी फेसबुक की पैरेंट कंपनी का नाम "मेटा" रखकर आने वाले इंटरनेट क्रांति में मेटावर्स की भूमिका के बारे में संकेत दे दिया है। प्रस्तावित सूत्रों के अनुसार आभासी दुनिया, वास्तविक दुनिया से भिन्न नहीं दिखेगी। बल्कि वास्तविक दुनिया से काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। कंप्यूटर ग्राफ़िक्स की मदद से 3-डी दुनिया बनाई जायेगी जिसे हम खास तरह के ऐनक पहन कर देख पायेंगे। उस आभासी दुनिया में हम अपने अवतार के माध्यम से उस दुनिया में टहल पायेंगे, अपने दोस्तों के अवतारों के साथ बात कर पाएंगे, ऑनलाइन खरीदी कर पायेंगे, और तो और अपने स्वर्गीय स्वजनों को भी उनके अवतारों के माध्यम से मिल पायेंगे। इस दुनिया में सब कुछ आभासी होगा परन्तु मज़े की बात तो यह है कि उसको वास्तविक न मानना भी उतना ही कठिन होगा। इन आभासी दुनिया में जब सब कुछ आभासी है तो मुद्राएं भी स्वाभाविक रूप से आभासी ही रहेगी। डिजिटल मुद्राओं से हम अपने अवतार के लिए आभासी घर, वस्त्र, साधन, आदि खरीद पायेंगे। अभी भले ही यह बातें काल्पनिक लग रही होगी परन्तु इसके प्रोटोटाइप उपलब्ध हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं।

हालांकि इतिहास साक्षी है, हर चलन पद्धति के कुछ लाभ तो कुछ नुकसान भी रहे हैं। एक ओर जहां दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से संघर्ष कर रही है वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन जेसे अत्यंत उर्जा ज्वलंत मुद्राओं का निर्माण भी पर्यावरण के नज़रिये से अनुचित लगता है। वहीं जब क्रिप्टोग्राफ़ी और ब्लॉकचेन जेसे आधुनिक तकनीक को वास्तविक रूप से परीक्षित करना शेष है, क्या पता कल को कोई ऐसी तकनीकी समस्या सामने आए जिससे गुनाहगारों को पथ मिल जाय और कठिन गणित के कारण उन्हें पकड़ना भी नामुमकिन हो जाए। इंटरनेट के डार्क वेब जैसे स्थानों में डिजिटल मुद्राओं के गैरकानूनी कार्य के लिए उनके प्रयोग को भी नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता।

विज्ञान दोधारी तलवार की भांति है, जो क्रांति से शांति भी ला सकती है और भ्रान्ति से विनाश भी कर सकती है । इसका उपयोग मात्र मानव उद्धार के लिए ही हो यह सुनिश्चित करना हमारा उत्तरदायित्व है । जैसे कि मसहूर उद्योगपति रिक फल्कविंगे ने कहा है : "बिट कॉइन बैंकों के साथ वही करेगा जो ईमेल ने डाक उद्योग के साथ किया था ।"

संदर्भ :

- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (एतहासिक मुद्रए) – https://rbi.org.in/Scripts/mc_ancient.aspx
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (चलन में आनेवाले मुद्रए) – https://rbi.org.in/Scripts/ic_coins.aspx#:~:text=Coins%20are%20minted%20at%20the,terms%20of%20the%20RBI%20Act.
- विकिपीडिया (भारत में बैंकिंग) - https://en.wikipedia.org/wiki/Banking_in_India#:~:text=Modern%20banking%20in%20India%20originated,1786%20but%20failed%20in%201791.

*****

ज्योति रंजन निधि

पदनाम:- उप शाखा प्रबंधक
संस्था का नाम:- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मोबाइल नं. :- 8347770004
ई-मेल:- jrnidhi@live.in

मुद्रा क्या है

मुद्रा मतलब करेंसी, द्रव्य, धन । मुद्रा शब्द अंग्रेजी के शब्द **'Money'** का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के **Moneta** शब्द से लिया गया है।

मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय किया जाता है। इसमें सिक्के और काग़ज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है।

मुद्रा में सामान्य स्वीकृति के गुण का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी वस्तु में सामान्य स्वीकार होने की विशेषता नहीं है तो उस 'वस्तु' को मुद्रा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु है जो सामान्य रुप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, धन के संचय, स्थगित भुगतानों के मान तथा ऋणों के भुगतान के रुप में स्वीकार की जा सकती है। मुद्रा को राजकीय मान्यता तथा संरक्षण भी प्राप्त होता है।

यूँ तो हमारे देश मे मुद्रा का प्रचलन आदिकाल से है और तभी से व्यापार भी है और विनिमय की प्रथा भी चली आ रही है। पहले व्यापार सामान्यतया वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था। एक सामान या सेवा के बदले दूसरा सामान या सेवा। इसमे मूल्यांकन के बजाय जरूरत अधिक मायने रखती थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसी प्रणाली नहीं थी जो हर वस्तु या सेवा को एक आदर्श मौद्रिक मूल्य मे माप सके। सामान या स्वीकृति वाली कोई मौद्रिक व्यवस्था थी ही नहीं।

बाद मे सिक्कों का दौर आया। वैसे भारत मे रुपए का इतिहास काफ़ी पुराना है, लगभग छठी सदी ईसा पूर्व से। भारत विश्व मे उन प्राचीनतम देशों में शुमार है जिन्होंने

अपनी मुद्रा सिक्कों के रूप मे चलाया। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल में सीसे के सिक्के को सीसारूपा, तांबे के सिक्के को ताम्ररूपा, सोने के सिक्के को सुवर्णरूपा और चांदी के सिक्के को रूप्यरूपा कहा जाता था। उससे भी पहले कहते हैं कि अशर्फियों का प्रचलन था। सन 1850 के आसपास चांदी के सिक्के को रुपए का दर्जा दिया गया और 1861 मे भारत सरकार द्वारा पहला कागज़ी नोट इशू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1938 से कागज़ के नोट इशू करना प्रारंभ किया। समय के हिसाब से मौद्रिक नीतियाँ भी बदलती रही और मुद्रा का मान और रूप भी। इस प्रकार से मुद्रा एक साधन है जिसके मूल्य से आप और हम सामान और सेवाओं को खरीद सकते हैं। रुपया एक कागज़ी मुद्रा है जो भारतीय रिज़र्व बैंक छापता है जिससे हम रोजमर्रे की चीजें इत्यादि खरीदते हैं। रुपये का मूल्य रिज़र्व बैंक द्वारा तय होता है।

डिजिटल मुद्रा क्या है

जब किसी देश के नगदी रुपयों को डिजिटल सिस्टम में स्टोर किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है उसे हम डिजिटल मुद्रा कहते हैं। यह हमारे आपके पैसों का ही एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। यह इलेक्ट्रॉनिक टोकन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल मुद्राएं केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी नहीं की जाती हैं। ये मुद्राएं हालांकि लोगों द्वारा दुनिया भर में सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए स्वीकार की जा रही हैं। डिजिटल मुद्रा का लेनदेन मूलतः इंटरनेट पर होता है। डिजिटल वॉलेट एक तरह का अकाउंट है जिसमे आप अपनी डिजिटल मुद्रा रखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल मुद्रा का एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होता है। इस प्रक्रिया में हमें बैंक के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल वॉलेट को फोन, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डिजिटल मुद्रा को किसी भी अन्य मुद्रा जैसे रुपया, डॉलर आदि के बदले में डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों पर खरीद सकते हैं।

डिजिटल मुद्रा के तीन प्रकार हो सकते हैं जैसे:

- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
- वर्चुअल करेंसी
- क्रिप्टो करेंसी

लाइटकोइन, जैकैश, एथ्यूरम, बिटकॉइन आदि सभी डिजिटल मुद्राओं का उदाहरण हैं जिनमें से बिटकॉइन सबसे लोकप्रिय है।

कोई भी मुद्रा व मौद्रिक नीति, लोगों के आम जनमानस के जीवन शैली व आम स्वीकार्यता से सीधे जुड़ा होता है क्योंकि ये रोजमर्रा के विनिमयन, लेन-देन, क्रय विक्रय, व्यवसाय, व्यापार से, बाज़ार से जुड़ा हुआ है। और बाज़ार मे, व्यवसाय में, व्यापार में, समाज में युवाओं का योगदान व भागीदारी अधिक है। वर्तमान में सिर्फ युवा ही नहीं वरन पूरा समाज ही डिजिटल युग, डिजिटल दुनिया की तरफ तेजी से अग्रसर होता दिख रहा है। सामान्य लेन-देन, विनिमयन, क्रय विक्रय सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन मोड मे अधिक होने लगा है। वस्तु, सामान, सेवा, व्यवस्था, शिक्षा, सब कुछ। ऐसे में पैसों का भुगतान भी ऑनलाइन मोड, डिजिटल मोड से अधिक होने लगा है। ऐसे में लोगों को डिजिटल मुद्रा की जरूरत और फिलहाल ये मुद्रा जिस किसी भी स्वरूप में बाज़ार में विद्यमान है, उसके प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है।

हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतानों और फिनटेक स्टार्टअप का देश में तेज गति से विकास हुआ है। 2015 मे डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद से ही हर क्षेत्र मे डिजिटल तकनीक के अधिकाधिक प्रयोग व उपयोग पर बल दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को सीधे तौर पर जनता तक पहुँचाने के लिए डिजिटल व्यवस्था का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोरोना कल मे भी, आरोग्य सेतु एप, cowin site इत्यादि के माध्यम से लोगों को सतर्कता व टीकाकरण अभियान को सफल बनाया गया।

लेकिन डिजिटल मुद्रा के ऊपर अभी तक सरकार का रुख कुछ साफ नहीं था। हालांकि नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल करेंसी को लागू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि डिजिटल करेंसी लागू होने के बाद काफी फायदा होंगे। जहां एक ओर नोटों की अपेक्षा ये सुरक्षित होगी वहीं डिजिटल रुपये के बाद लेन-देन भी काफी आसान होगा। नोटों की चोरी और लूट की घटनाओं में भी कमी आएगी।

वर्तमान में तमाम कंपनियों की ओर से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्लेटफार्म के तहत कंपनी बैंक से पैसे का लेनदेन कर ग्राहकों को

डिजिटल करेंसी की लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराती है। युवा निवेशक बड़ी तादाद में इसकी तरफ आकर्षित होते रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक देश में दो करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर चुके थे। इसमें और भी वृद्धि की ही ज्यादा संभावना नजर आ रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों को भारी मात्रा में लाभ कमाने की खबरें आती रही हैं। विश्वभर में ज्यादातर केंद्रीय बैंक अब अपनी राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं को पेश करने के मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। पूरे विश्व में 86% सेंट्रल बैंक जैसे ब्रिटेन की बैंक, चाइना की बैंक, अमेरिका की बैंक आदि ऐसे बैंक हैं जो अपने कन्वेंशनल पैसों को बदलना चाह रही हैं यानी उन्हें बदलकर इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल बनाना चाह रही हैं। इस विषय पर कई देश काफी चर्चा कर रही है और इस पर काफी खोजबीन भी कर रही हैं। पूरे विश्व में अब तक 14% सेंट्रल बैंक ने तो पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिया है। उन देशों के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी पर अपना काम करना भी शुरू कर दिया है।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका में भी अमीर युवा इसी क्षेत्र में निवेश करना अधिक पसंद कर रहे हैं। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित क्रिप्टोकरेंसी में भविष्य की दृष्टि से बड़ी संभावनाएं देखी जा रही है। इसके आधार पर आने वाले समय में आर्थिक दुनिया में बुनियादी बदलाव हो सकते हैं।

2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजीटल मुद्रा (Digital Currency) के बारे में बात की। सरकार ने वर्चुअल करेंसी के वजूद को नकारने के बजाय अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया वित्त वर्ष 2022-23 में डिजीटल करेंसी को लॉन्च करेगा और ये भारत सरकार की आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगीं। इसके अलावा, उन्होंने बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से होने वाले मुनाफे पर फ्लैट 30% टैक्स की भी घोषणा की थी। तब से ये दोनों चीजें चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वो करेंसी होगी जो केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा होगी। यह "ब्लॉकचैन और अन्य तकनीकों" पर आधारित होगी। सरल शब्दों में कहें तो सीबीडीसी भारतीय रुपये का एक डिजिटल रूप होगा। एक बार जब आरबीआई डिजिटल करेंसी को जारी करना शुरू कर देगा तो हम और आप जैसे आम लोग नियमित रुपये की तरह ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। डिजिटल रुपया आपके एनईएफटी, आईएमपीएस या डिजिटल

वॉलेट की तरह होगा। आप इसका उपयोग थोक लेनदेन या खुदरा भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। आप इसे विदेश भेज सकते हैं। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। यह डिजिटल करेंसी मूल रूप से बिटकॉइन और एथेरियम जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी से अलग होगी क्योंकि यह राज्य द्वारा समर्थित होगी और इसका आंतरिक मूल्य होगा। सरकार ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल एसेट्स कहा है यानी वे लीगल टेंडर नहीं होंगे।

इस डिजिटल करेंसी को मुद्रा के रूप में गिना जाएगा। इससे सरकार को कम नोट छापने और नकली मुद्रा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह "अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली" बनाने में मदद करेगा। नियमित रुपये के विपरीत, डिजिटल रुपये को ऑनलाइन लेनदेन के लिए बैंक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेषक और प्राप्तकर्ता ब्लॉकचेन का उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं और आरबीआई गारंटर होगा। यह तभी होगा जब संसद क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का विनियमन पारित करेगी जो आरबीआई को डिजिटल रुपया जारी करने का अधिकार देगा। वित्तीय सेवाओं में नवाचार के रूप में डिजिटल मुद्रा 'भविष्य के मूल्य हस्तांतरण' को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सीबीडीसी अपने उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल धन तक पहुंच सुनिश्चित करके भुगतान प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है।

डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल में आने से लाभ

- डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा
- डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी मूल्य हस्तांतरण के तरीके को बदलने की अपनी क्षमता के कारण घरों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक लचीली, नई और प्रतिस्पर्धी भुगतान प्रणाली बन सकती है। डिजिटल रुपया की शुरुआत के साथ लेनदेन की दक्षता में अच्छी वृद्धि होगी।
- डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नकदी रुपयों पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा। लोगों को अक्सर नकदी रुपयों को रखने में और इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। कभी-कभी वे सही समय पर नकदी रुपयों को निकाल या जमा भी नहीं करा सकते हैं। इसलिए इस मुद्रा के आने से लोगों को नकदी रुपए के ऊपर निर्भर होने से छुटकारा मिल सकेगा।

- डिजिटल करेंसी को रिटेलर और होलसेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने का भी विचार किया जा रहा है।
- रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग जाता है उसमें भी कमी आएगी।
- यह पैसा जमा कराने और निकलवाने के तरीके को काफी आसान कर देगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक होगा तो लोगों को काफी समय तक लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पैसों को स्टोर कर सकेंगे।
- डिजिटल करेंसी सेल लोगों को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा महसूस होगी और उनके पैसे ज्यादा सिक्योर रहेंगे।
- डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को अपने देश के बाहर या फिर देश में ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर जमा करने के लिए अलग-अलग समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिससे बैंकिंग फ्रॉड जैसे कामों में भी कमी आएगी।

डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल में आने से नुकसान

यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी नई चीज के आने से जितना उस चीज का फायदा होता है उतना ही वह अपने साथ कुछ नुकसान भी लेकर आती है। डिजिटल मुद्रा के कुछ नुकसान इस प्रकार से हो सकते हैं:

- चूंकि पैसा भी एलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा तो नकदी लेन देन और उसके रख रखाव के लिए जीतने लोगों की जरूरत पड़ती है उसमें कमी आएगी। लिहाजा बैंक में स्टाफ की कटौती होगी, रोजगार व रोजगार के संभावनाओं में कमी आएगी।
- डिजिटल दुनिया अभी भी बहुत सुरक्षित नहीं है। ये प्रणाली भी साइबर अपराध व अपराधियों के जद में आ जाएगा।

*****

डॉ. बी. एन. शर्मा

पदनाम:- वैज्ञानिक/अभियंता - एसजी
संस्था का नाम:- अन्तरिक्ष उपयोग केंद्र, इसरो
मोबाइल नं. :- 9687596277
ई-मेल:- bns@sac.isro.gov.in

प्रस्तावना:

वर्ष 2008 में सातोशी नाकामोतो के क्षद्म नाम से जब पहली बार डिजिटल क्रिप्टो-मुद्रा पर एक श्वेत-पत्र "बिट क्वाइन: एक पियर टू पियर इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली" प्रकाशित हुआ था, तब संभवतः लोगों को यही लगा था कि यह कुछ कंप्यूटर इंजिनियरों का दिमागी फितूर है और यह महज एक गणित, विज्ञान और सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन मात्र है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बिटकॉइन आज की सबसे प्रचलित क्रिप्टो-करेंसी बन जाएगी तथा अन्य क्रिप्टो-करेंसियों के साथ इनका वैश्विक बाजार करीब 961 अरब डॉलर का हो जायेगा। आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब 15 लाख रूपए के बराबर है जो यह दर्शाता है कि बिटकॉइन की वैश्विक बाजार में कितनी गहरी पैठ बन गई है।

बिटकॉइन जैसे डिजिटल मुद्रा की खोज और उसके अप्रत्याशित प्रसार ने न केवल मुद्रा के मुद्रित होने की अनिवार्यता को चुनौती दे रही है, बल्कि मुद्रा को एक संघीय ढांचे के अंतर्गत विनियमन होने की आवश्यकता पर भी सवाल खड़े कर रही है। पूरी तरह तकनीक पर आधारित इस डिजिटल मुद्रा को लेकर वर्तमान में उपजे उत्साह, भ्रांतियों एवं आशंकाओं के बीच संभवतः डिजिटल मुद्रा भविष्य में विनिमय और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कई देश इस आभासी मुद्रा की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इस मुद्रा को संघीय प्रणाली के अंदर लाकर इसे संवैधानिक और व्यावहारिक विनियमन के तहत अपनाने की संभावनाएं तलाशते नजर आ रहे हैं।

डिजिटल मुद्रा: पृष्टभूमि

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ, वैश्विक स्तर पर मुद्रा के भी स्वरुप बदलते रहे हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में रुपया भी रूप बदलता रहा है। मानव समाज की आवश्यकताएं बढ़ने के साथ-साथ उनकी समाजिक प्रवृत्ति का भी विकास हुआ और वे एक-दूसरे पर आश्रित होने लगे। दूसरों से प्राप्त वस्तुओं, पदार्थो और सेवाओं के लिए उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता पड़ने लगी और संभवतः यहीं से वस्तु-विनिमय प्रणाली (बार्टर सिस्टम) की शुरआत हुई। किन्तु बार्टर सिस्टम की अपनी एक सीमा थी, अत: शीघ्र ही एक मानकीकृत मुद्रा का जन्म हुआ। मानव सभ्यता के साथ मुद्रा ने एक लम्बा सफ़र तय किया और उसका रूप हमेशा मानव के विकास के साथ बदलता रहा। मुद्रा मानव सभ्यता की शुरुआत से अब तक अपने कई रूपों, जैसे- समुद्री कौड़ियों, मिट्टी, धातु, सोने-चांदी के सिक्के, कागज के नोट आदि और अब, डिजिटल मुद्रा के रूप में विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। यह दर्शाता है कि मुद्रा की मानव समाज में हमेशा आवश्यकता रहेगी और इसका स्वरूप मानव विकास के साथ बदलता ही रहेगा। इसलिए डिजिटल मुद्रा के प्रादुर्भाव को सिरे से नकारना एक भूल होगी, पर इस अत्याधुनिक और विकसित मानव समाज में इसके दुरूपयोग की चिंता भी उतनी ही स्वाभाविक एवं आवश्यक है। इसका विश्लेषण करने हेतु, सर्वप्रथम आधुनिक युग के इस डिजिटल मुद्रा को उसकी तकनीकी एवं व्यवहारिक परिदृश्यों में समझाना अति आवश्यक है।

डिजिटल मुद्रा क्या है ?

डिजिटल मुद्रा, मुद्रा का एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता पर उसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय, बैंकिंग, निवेश, व्यापार और मुद्रा विनिमय संबंधी सभी उदेश्यों के लिए किया जा सकता है। इसे डिजिटल पैसा, डिजिटल करेंसी, साइबर कैश आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मुद्रा का उपयोग सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा के निम्नलिखित फायदे हैं:-

1. डिजिटल मुद्रा विनिमय का सबसे तेज और निर्बाध माध्यम है और यह दो व्यक्तियों, संस्थानों के बीच बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप और शुल्क के हो सकता है। यह विनिमय का सबसे तेज एवं सस्ता माध्यम है।
2. इनका उत्पादन भौतिक रूप में नहीं होता है, इसलिए इनके ख़राब होने की संभावना नहीं होती है।
3. यह मुद्रा केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है और इसकी यही खूबी इस मुद्रा को लोकतांत्रिक दर्जा देती है।

4. यह मुद्रा एक अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक मौद्रिक नीति के कार्यान्वन को बढ़ावा देती है।

डिजिटल मुद्रा जहां एक ओर फायदेमंद प्रतीत होती है, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि:

1. डिजिटल मुद्रा के सुगम कार्यान्वन के लिए उच्च गति एवं अच्छी गुणवत्ता वाली इंटरनेट की आधारभूत सुविधा चाहिए जो कई विकासशील एवं पिछड़े देशों में अभी भी उपलब्ध नहीं है।
2. चूंकि डिजिटल मुद्रा इंटरनेट पर आधारित है, इसमें हैकिंग की बहुत संभावनाएं है।
3. वर्तमान में प्रचलित डिजिटल मुद्रा में स्थायित्व की कमी है और उसका मूल्य बहुत ही परिवर्तनशील है।

डिजिटल मुद्रा के प्रमुख तीन प्रकार हैं:

1. क्रिप्टो-मुद्रा: क्रिप्टो-मुद्रा डिजिटल मुद्रा का एक अहम् प्रकार है जिस पर आधारित कई मुद्राएं चलन में हैं। इनमें मुख्य रूप से बिटकॉइन, अथेरियम, आदि प्रमुख हैं। इस मुद्रा के उत्पादन में क्रिप्टोग्राफ़ी का उपयोग किया गया है जो इसे बहुत अधिक सुरक्षित बनाती है। इस मुद्रा का विनियमन किया भी जा सकता है और नहीं भी।
2. आभासी मुद्रा: यह पूर्ण रूप से अविनियमित मुद्रा है और यह इसको जारी करने वाले व्यक्ति या संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है। कुछ क्रिप्टो मुद्राएं इसी के भाग हैं।
3. केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा (CBDC): इस प्रकार की मुद्रा को किसी देश के विनियामक संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह उस देश के पारंपरिक वैध मुद्रा के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकती है।

डिजिटल मुद्रा का तकनीकी आयाम

डिजिटल मुद्रा के तकनीकी आयाम को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें इसके असुरक्षित होने जैसी आशंकाओं को दूर करने में सहायता करती है। डिजिटल मुद्रा, खासकर क्रिप्टो-मुद्रा, ब्लॉकचेन पर आधारित एक मुद्रा है जिसका मुख्य उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच विनिमय को एक सुरक्षित माध्यम से क्रियान्वित करना है। इस विधा में दोनों व्यक्तियों की पहचान को प्रकट करना आवश्यक नहीं है और होने वाले लेन-देन को किसी तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना भी जरुरी नहीं है। डिजिटल

मुद्रा की रीढ़ ब्लॉक चेन तकनीक है। डॉन और अलेक्स टैपस्कॉट ने अपनी किताब "ब्लॉकचेन क्रांति" में ब्लॉकचेन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खता है जिसमें मुद्रा का सभी लेन-देन संरक्षित होता है। जब दो लोग स्वेच्छा से मुद्रा का विनिमय करना चाहते हैं तो इस तिजोरी को खोलने के लिए सबसे पहले दोनों को दो चाबियों [एक सार्वजानिक (पब्लिक) और एक निजी (प्राइवेट)] का इस्तेमाल करना होगा। यही सुरक्षित चाबियाँ ही क्रिप्टो-चाबियाँ कहलाती हैं। इन चाबियों का सत्यापन कोई भी केंद्रीकृत नियामक कर सकती है या इसे एक वितिरित नेटवर्क के माध्यम से बिना किसी हस्तक्षेप के भी किया जा सकता है। इन वितिरित नेटवर्क पर कुछ गणितीय विधियों से इन चाबियों का सत्यापन किया जा सकता है। जैसे-जैसे डिजिटल बही खाता में प्रविष्टियां बढती हैं, डेटा संग्रहण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। एक अनुमान के हिसाब से बिटकॉइन में उसकी स्थापना के बाद से अब तक उसकी हैश टैग दर 35 लाख TH/s हो गई है। इस बदलते हुए डेटा का प्रबंधन करने एवं वितरित नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने के लिए क्रिप्टो-मुद्रा बिटकॉइन अपने ग्राहकों के कंप्यूटरों का भी इस्तेमाल करती हैं। इससे चाबियां भी सुरक्षित रहती हैं। बढ़ती हुई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आसानी से ज्यादा डेटा संग्रहण किया जा सकता है।

डिजिटल मुद्रा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मुद्रा माइनिंग की जाती है। मुद्रा माइनिंग के लिए लेन-देन संबंधी सैंकड़ों ब्लॉकचेन को खंगाला जाता है और गणितीय विधि से इसके लिए एक नया ब्लॉक जोड़ा जाता है। जो नेटवर्क में सबसे पहले इस नए ब्लॉक को बना पाता है उसे इनाम मिलता है। बहुत हद तक यह तकनीक सुरक्षित भी है और थोड़ी असुरक्षित भी।

डिजिटल मुद्रा का वर्तमान एवं भविष्य

कुछ वर्षों की अवधि में ही क्रिप्टो-मुद्रा का बाजार डिजिटल तकनीक के सहारे ट्रिलियन-डॉलर तक बढ़ गया है। कुछ अनुमानों के आधार पर कुल वैश्विक क्रिप्टो बाजार का मूल्य अब 2.12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है जिसमें दैनिक वैश्विक ट्रेडिंग राशि 100 बिलियन डॉलर से अधिक है। वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन और इसके जैसी कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी निवेश के रूप में लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं और इनका उपयोग सॉफ्टवेयर से लेकर, ऑनलाइन खरीदारी, रियल एस्टेट, जुआ, अवैध ड्रग्स आदि सब कुछ खरीदने के लिए किया जाने लगा है।

क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ने "विकेंद्रीकृत वित्त" (डेफी) व्यवसायों और परियोजनाओं के एक नए समूह को जन्म दिया है। डेफी का उद्देश्य लोगों को ऐसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है जो उधार लेने, उधार देने, व्यापार करने के प्रचलित माध्यमों जैसे बैंक और ब्रोकरेज आदि से रहित हो, आदि शामिल हैं। इससे लोग अक्सर बड़े कमीशन और अन्य प्रकार के शुल्क देने से बच जाते हैं। इस व्यवस्था में शुल्क की जगह "स्मार्ट अनुबंध" के तहत स्वचालित रूप से लेनदेन निष्पादित करते हैं। डिजिटल मुद्रा आधारित डेफी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और निवेशकों ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

टेसला जैसी कम्पनियाँ भी अब क्रिप्टो-करेंसी जैसी डिजिटल मुद्रा को अपने कारों के विनिमय के लिए स्वीकार करने लगी हैं और क्रिप्टो-मुद्रा में करीब 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश भी कर रही है। पे-पेल जैसी अमेरिकी कंपनी जो ऑनलाइन भुगतान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने भी क्रिप्टो-करेंसी को विनिमय के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा उबेर, मास्टर-कार्ड ने भी डिजिटल मुद्रा का उपयोग करना चालू कर दिया है। वैश्विक जनमानस के अलावा, डिजिटल मुद्रा ने कई विकसित, विकासशील एवं पिछड़े देशों को भी आकर्षित किया है और कई देशों ने क्रिप्टो-करेंसी एवं अन्य डिजिटल मुद्राओं के स्वरुप को मान्यता देना और अपनाना शुरू कर दिया है। अटलांटिक काउंसिल के वेबसाइट के अनुसार पूरे विश्व में अब तक 10 देशों ने डिजिटल मुद्रा के केंद्रीकृत प्रणाली (CBDC) को लागू कर दिया है जिसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यस्था वाला देश नाइजीरिया भी शामिल है। विश्व के करीब 105 देश जो 95% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, वे भी इस मुद्रा प्रणाली को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे है।

वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्रा की बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय एवं एशिया क्षेत्र के निवेशकों को भी आकर्षित किया है। भारत क्रिप्टो-करेंसी बाजार में विशेष रूप से सक्रिय रहा है। कई शोध विश्लेषकों के अनुसार भारत में सबसे अधिक क्रिप्टो-करेंसी के मालिक हैं और इस मुद्रा को अपनाने की दर के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में 60 प्रतिशत से अधिक राज्य क्रिप्टोटेक को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें 15 मिलियन से अधिक खुदरा निवेशक हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में लगभग 230 स्टार्ट-अप के साथ देश में एक मजबूत संस्थागत उपस्थिति दर्ज हुई है जो विकास की भरपूर संभावनाएं और अवसर पेश कर रही हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से भी, भारतीय

तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र कुशल उद्यमियों और उच्च स्तरीय प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। यदि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पिछले कुछ वर्षों की तरह उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो भारत इस क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत सरकार ने भी डिजिटल मुद्रा की उपस्थिति को समझा है और 2022-23 के बजट में कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक 'डिजिटल रुपी' नाम से एक डिजिटल मुद्रा लाएगी।

डिजिटल मुद्रा की चुनौतियाँ

वर्तमान में डिजिटल मुद्रा को लेकर मुख्य चिंता यह है कि यह मुद्रा बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील है। उतार-चढ़ाव वाले इस आधुनिक युग के मुद्रा पर आम लोगों खासकर जो मध्यम से ज्यादा आयु वर्ग के हैं, की बहुत आशंकाएँ हैं। डिजिटल मुद्रा ने संभावनाओं के साथ नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। क्रिप्टो-करेंसी में निहित गुमनामी और पोर्टेबिलिटी इन्हें आपराधिक समूहों, आतंकवादी संगठनों और दुष्ट व्यक्तिओं, संगठनों एवं राज्यों के लिए आकर्षक बनाती है। उभरती हुई वित्तीय प्रौद्योगिकियों के संवैधानिक एवं व्यवहारिक नियमों के बारे में भी कई अनिश्चितताएं हैं। इसके अलावा, क्रिप्टो-माइनिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में डेटा प्रसंस्करण हेतु कंप्यूटर और उनके चलने के लिए बिजली की आवश्यकता हो सकती है जिससे इसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। इन सब के उपर साइबर सुरक्षा, लोगों का भरोसा, अनैतिक शोषण, उपभोक्ता संरक्षण, बाजार की अस्थिरता, मुद्रा की अस्थिरता और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति को लागू करने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल मुद्रा एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकती है जो किसी भी देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर उस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। साइबर अपराध दिनों-दिन बढ़ रहे हैं और इसको नियंत्रित करना अभी भी चुनौती पूर्ण बना हुआ है। परन्तु इन सभी बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता, केन्द्रीय विनियमन, वित्तीय अपराधों के लिए कठोर कानून, उच्चतम टेक्नोलॉजी आदि का सहारा लिया जा सकता है।

डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है और क्षेत्र में भी व्यापक चुनौतियां हैं। एक मुख्य चुनौती इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट की उपलब्धि है। भारत जैसे देशों में भी इंटरनेट की पंहुच अभी भी काफी सीमित है, ऐसे में इंटरनेट का आधारभूत ढांचा पूरे देश में खड़ा करना काफी चुनौतीपूर्ण है। इन चुनौतियों को टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत हद तक हल किया जा सकता है। अंतरिक्ष आधारित

उपग्रहों से इंटरनेट के ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा की पहुँच दूर-दराज के इलाकों में भी हो सकती है। आज के इस क्वांटम युग में क्वांटम कुंजी टेक्नोलॉजी की मदद से अभेद्य क्रिप्टो चाभियां बनायी जा सकती है।

उपसंहार

मुद्रा अपने प्रादुर्भाव से ही अपने रूप बदलती रही है। टेक्नोलॉजी एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में फिर से मुद्रा अपने रूप बदलती दिख रही है। क्रिप्टो-करेंसी पूरी दुनिया में विनियमन, वित्त एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है। डिजिटल मुद्रा ने लोगों को निर्बाध रूप से बिना किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप के विनियमन की सुविधा प्रदान की है। पूरे विश्व में व्यक्तियों, उद्योगपतियों, संस्थानों और यहाँ तक की कई देशों की सरकारों ने डिजिटल मुद्रा को उनके अलग रूपों में अपनाया है और कई देश इस दिशा में अग्रसर है। कई ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय क्षमता वाला यह डिजिटल मुद्रा वर्तमान में अपने प्रारंभिक अवस्था में है और आगे भविष्य में कई संभावनाएं लेकर आये हैं। हालांकि, इसके स्थायी एवं सर्व स्वीकार्य होने में अभी कई आशंकाएं तथा तकनीकी चुनौतियाँ भी है। मुद्रा के इस बदले स्वरुप में काफी संभावनाएं हैं और आज का युवा वर्ग किसी भी तकनीकी बाधा को हल करने में सक्षम है। भविष्य में डिजिटल मुद्रा के विकास में उपग्रह आधारित समाधान का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान होगा।

सन्दर्भ:

- विकिपीडिया
- स्वेत-पत्र "बिटकॉइन: एक पियर टू पियर इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली"
- डॉन और अलेक्स रचित पुस्तक "ब्लॉकचेन क्रांति"
- https://online.stanford.edu
- https://www.bankofbaroda.in/hi-in/banking-mantra/digital/articles/internet-of-value-internet-2-0
- नैस्डेक वेबसाइट
- अटलान्टिक काउंसिल वेबसाइट
- इन्वेसटोपेडिया
- इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ़ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस आदि न्यूज़ पेपर्स

*****

डॉ. मनीष कुमार सोनी

पदनाम:- प्रबंधक - राजभाषा
संस्था का नाम:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मोबाइल नं. :- 9082764238
ई-मेल:- hindiboraro@centralbank.co.in

"कुछ लोग ऐसे है जो स्वप्न की दुनिया में जीते है, कुछ ऐसे है जो वास्तविक दुनिया का सामना करते है और कुछ ऐसे भी है जो स्वप्न की दुनिया को वास्तविक दुनिया में बदलते है।"

- डगलस इवरेट

"There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality; and then there are those who turn one into the other."

- Douglas Everette

एक समय था जब साइकिल, टेलीफोन, तार, ट्रेन, कार, हवाई जहाज, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि सभी यंत्र काल्पनिक से लगते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में दिनों, महीनों और वर्षों का समय लग जाता था, लेकिन स्वप्नदर्शियों के इन स्वप्नों को कुछ महान आविष्कारकों ने हकीकत में बदल दिया, सारे यंत्र बनते गए और जिंदगी आसान होती गई। यात्राएं सुगम होने लगी, सभी से आसानी से संपर्क करना आसान होने लगा। लोगों के घरों में टेलीविजन और कंप्यूटर आ गए तथा मनोरंजन की एक नई दुनिया बस गयी।

हर युग अपने पिछले युग की तुलना में ज्यादा विकसित होता है। यही धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाने की प्रक्रिया है। यह विकसित होते जाने की प्रक्रिया का एक अंग है। पहिए का आविष्कार उतना ही क्रांतिकारी था, जितना आज के समय में इंटरनेट का है। हर युग वैज्ञानिक चेतना से लैस है, किसी युग को पिछड़ा कहना या उस युग में वैज्ञानिक सोच का न होना, यह कहना निरर्थक है। अतः जरूरी है कि जिन स्वप्नों को हमने देखा है, उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करें। हवाई जहाज का काल्पनिक चित्र

लिओनार्डो द विंची ने 500 वर्ष पूर्व देखा था लेकिन उसे हकीकत में बदलते हुए 300 वर्षों का समय लग गया।

आज का युग पिछले युग की तुलना में अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा सजग है। आज का युग वैज्ञानिक चेतना को ज्यादा महत्त्व दे रहा है जिससे आविष्कार भी ज्यादा हो रहे हैं। आज हमारी दुनिया प्रौद्योगिकी की दुनिया है। इंटरनेट के जमाने में भी जो कार्य अभी पिछले 20 वर्ष पूर्व तक असंभव लग रहे थे, आज वे सभी कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। अब, हमारे हाथ में विभिन्न डिजिटल सेवाओं से युक्त फोन आ चुके है जो हमें पूरे विश्व से हर समय जोड़े रहते है। ये सर्वर इतने सक्षम हैं कि इंटरनेट संबंधी सेवाओं को निर्बाध रूप से लगातार संचालित करते रहते हैं। यही कारण है कि हम अपने व्यापार एवं अन्य सभी सेवाओं से संबंधित कार्य 24X7 कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए डिजिटल मुद्रा को भी जोड़ दिया है। अब, हम व्यापार से लेकर अपने दैनिक जीवन संबंधी सभी लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अब, किसी भी प्रकार के भौतिक मुद्रा को साथ लेकर चलने की जरूरत ख़त्म हो गयी है।

डिजिटल करेंसी (मुद्रा) क्या है: जब कोई देश अपने नकदी रुपयों को डिजिटल सिस्टम में स्टोर कर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करे, उसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें कि आपका धन बैंक में जमा हो गया, अब वह एक डिजिट (आकड़े) के रूप में है अर्थात् आप उतने पैसे के मालिक है और अब उसे किसी के भी खाते में अंतरित कर वस्तुओं/ सेवाओं आदि की खरीद करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का खाता नंबर डालकर जितनी राशि उसे देने हैं, उस राशि का अंतरण कर सकते हैं। व्यक्ति के संबंधित खाते में राशि अंतरित होते ही आप के खाते से उतनी राशि कट जाएगी और दूसरे खाते में उतनी राशि जुड़ जाएगी। इसमें आपको किसी नकदी रुपए के लेनदेन की आवश्यकता भी नहीं होती है तथा इस प्रकार के अंतरण का रिकॉर्ड भी बन जाता है, इसे ही हम डिजिटल मुद्रा अंतरण कहते हैं। अब, यही कार्य विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने लगे हैं। आप स्वयं अपनी दुकान ऑनलाइन खोल सकते हैं और अपना व्यापार ऑनलाइन चला सकते है। यह बेहद आसान है और नकद की बाधा से मुक्त भी है। इसके पहले सारे व्यापार नकदी रुपए पर होते थे जिससे इसे लगातार साथ रखने का जोखिम बना रहता था लेकिन आज के समय में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के कारण यह जोखिम खत्म हो गया है।

भारत में वर्ष 2015 में डिजिटल भारत की संकल्पना की गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, आरआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी आदि जैसे दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में दिनांक 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गयी। देश को डिजिटल रूप से विकसित करने और देश के आईटी संस्थानों को बेहतर बनाने हेतु 'डिजिटल इंडिया' एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी क्रम में, डिजिटल इंडिया अभियान की विभिन्न योजनाओं जैसे डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-साइन आदि को शुरु करके इस कार्यक्रम का अनावरण किया गया। अपने इसी डिजिटल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया है।

डिजिटल करेंसी के प्रकार: डिजिटल करेंसी तीन प्रकार की हो सकती है:

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी : यह करेंसी हमारे देश भर में प्रचलित मुद्रा का डिजिटल रूप होगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी केंद्रीय बैंक से जुड़ा होगा और हमारे बैंकों में भारत की मुद्रा का ही लेनदेन होता है। यह मुद्रा आधिकारिक मुद्रा है। इस मुद्रा का संग्रहण बैंक में ही होता है अतः ऐसे में सभी केंद्रीय बैंक सभी ग्राहकों को अपनी मुद्रा का कहीं भी इस्तेमाल करने हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे जो सीधे बैंक से जुड़ा होगा। ऐसे में व्यक्ति अपने बैंक से 24X7 ग्राहक सेवाएं एवं सहायता प्राप्त कर सकेगा। यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहकों को सभी संभव सेवाएं डिजिटली प्रदान करें। आज के समय में ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कहीं भी अपना खाता खोल सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं और बैंक की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

वर्चुअल करेंसी : यह एक ऐसी मुद्रा है जो ऑनलाइन कार्य करती है। इस मुद्रा का इस्तेमाल सभी उत्पादों के स्टोर पर किया जा सकता है। यह कई रूपों में कार्य करता है। इसकी कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप होता है और यह सरकार द्वारा समर्थित वर्चुअल करेंसी होती है। वर्ष 2022 के यूनियन बजट को संसद में 1 फरवरी, 2022 को पेश किया गया। भारत की वर्तमान वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान यह एलान किया कि वर्ष 2022-2023 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो भारतीय क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं उन्हें 30 फ़ीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

क्रिप्टो करेंसी: यह किसी केंद्रीकृत प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है। आमतौर पर यह ब्लॉक चेन है जो एक सार्वजनिक वित्तीय लेनदेन डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। इसकी कल्पना 1983 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउम ने की थी जिसे एक्श कहा जाता है। 1995 में उन्होंने इसे डिजिकैश के रूप में लागू किया। इस क्रम में, बिट्क्वाइन का नाम भी प्रमुख है जिसे पहली बार 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। यह पहला विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है। इसके बाद से अभी तक बहुत सारी क्रिप्टों करेंसी आ चुकी हैं।

डिजिटल मुद्रा का वर्तमान : वर्तमान समय डिजिटल मुद्रा का समय है। वर्ष 2015 से डिजिटल भारत का जो सपना देखा गया, वह वास्तव में वर्ष 2019 में आई वैश्विक महामारी कोरोना में, इस डिजिटल भारत के जरूरत को रेखांकित करता है। यदि हमारा देश अपने पूर्व निर्णय में अपने देश को डिजिटल बनाने पर जोर नहीं देता तो शायद महामारी के दौरान लगातार किए गए लॉकडाउन में देश को गम्भीर आर्थिक संकटों से जूझना पड़ता लेकिन बैंकों के अथक श्रम ने देश की अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा दिया और सम्पूर्ण भारत में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया। अब जबकि कोरोना महामारी पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है तब हमारी सरकार और नागरिकों दोनों ने इस डिजिटल भारत के महत्व को ज्यादा समझा है। आज के समय में यह जरूरी है कि डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्य किया जाए और डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में शामिल किया जाए। डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नकदी रुपयों पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा और व्यापार एवं सभी प्रकार का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा। अधिकांश लोगों को नकदी रुपयों को रखने में और इस्तेमाल करने में बहुत परेशानी होती थी। अब रुपए ढोने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कभी-कभी वे सही समय पर नकदी रुपयों को निकाल या जमा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, इस मुद्रा के आने से लोगों को नकदी रुपए पर निर्भर होने से छुटकारा मिल सकेगा। डिजिटल करेंसी को रिटेल, होलसेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी विचार किया जा रहा है। रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग जाता है, उस बजट में भी कमी आएगी। साथ ही, पैसा जमा करने और निकालने में भी आसानी

होगी, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक होगा तो लोगों को काफी समय तक लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पैसों को स्टोर कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी से लोगों को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा महसूस होगी और उनके पैसे ज्यादा सिक्योर रहेंगे। सरकार का नोटों को छापने के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा। डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को अपने देश के बाहर या फिर देश में ही निधि अंतरित करने या जमा करने के लिए अलग-अलग समयावधि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी घटनाओं में भी कमी आएगी।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य : 20 वर्ष पूर्व तक जब डिजिटल फोन उपलब्ध नहीं था तो इस आशय की कल्पना करना भी मुश्किल था कि फोन के माध्यम से सारे भुगतान संभव हैं। किंतु विज्ञान ने इसे संभव कर दिखाया। आज जब डिजिटल करेंसी की बात हो रही है तो यह कल्पना भी शायद असंभव लगे लेकिन कुछ समय बाद यह आपके पहचान से जुड़ जाएगी और हो सकता है कि आपको किसी भी तरह की मुद्रा का लेनदेन करना ही न पड़े बल्कि आपकी रीडिंग के माध्यम से ही सब कुछ होने लगे अर्थात् बिना किसी डिवाइस के उपयोग के ही सब कार्य संभव होने लगे। वास्तव में दुनिया काफी तेजी से बदल रही है और समय के साथ सभी को इस नई दुनिया में जीना होगा जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही होंगे। अत: यह कहना कि आने वाला वक्त विज्ञान और डिजिटल मुद्रा का ही है, अतिश्योक्ति नहीं होगी।

*****

तपन कीर्तिकुमार बिलखिया

पदनाम:- विशेष सहायक
संस्था का नाम:- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मोबाइल नं. :- 9033530595
ई-मेल:- bioinfotapan@gmail.com

डिजिटल मुद्रा जिसे ई-मुद्रा भी कहते हैं । यह डिजिटल मुद्रा नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। फिलहाल भारत में इसे मान्यता नहीं प्राप्त है। इसे देश की सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी। इस मुद्रा को केवल देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इस डिजिटल मुद्रा की खास बात यह होगी कि इसे सॉवरेन करेंसी में भी बदला जा सकेगा तथा यह भारत का डिजिटल रुपया होगा। यह डिजिटल मुद्रा दो प्रकार की होगी - पहला रिटेल और दूसरा होलसेल। रिटेल डिजिटल मुद्रा को आम नागरिक तथा कंपनियों द्वारा प्रयोग में लाया जायेगा, जबकि होलसेल डिजिटल मुद्रा को वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें किसी तरह का वॉलेट नहीं होगा और न ही बैंक खाते की जरूरत होगी। यह बिलकुल नकदी की तरह ही उपयोग में लायी जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यह टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल रूप में कार्य करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वयं का डिजिटल रुपया प्रस्तुत करने की तैयारी में है। यह भारत के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिलने की उम्मीद है।

एक जमाना था जब निवेश करने वाले अक्सर शेयर बाजार की खबरों पर नजर रखते थे। आज भी ऐसे ही लोग इंटरनेट पर शेयर बाजार के उठते-गिरते भाव यानी ग्राफ पर नजर टिकाए रहते हैं। यूं तो लंबे समय से शेयर बाजार के अलावा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड और ईटीएफ में भी निवेश किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अब एक नया विकल्प मिल गया है, जहाँ युवा निवेश के मामले में सबसे आगे हैं। यह डिजिटल दुनिया की डिजिटल करेंसी यानि क्रिप्टोकरेंसी है। यह एक ऐसी दुनिया है, जो किसी एक देश के दायरे तक सीमित नहीं है । क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्रा का ही एक रूप है। यह किसी सिक्के या नोट के रूप में आपकी जेब में न होकर पूरी तरह ऑनलाइन होती है। यह एक गैर कानूनी करेंसी है जिसे किसी तरह

की सरकारी मान्यता नहीं प्राप्त है और न ही इसे किसी सरकारी या विनियामक अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बिना किसी नियम के व्यापार किया जाता है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है इसलिए यह पूरी तरह से जोखिमों के अधीन होती है। यह जारी किये गए देश में खरीदारी या लेन-देन के रूप में प्रयोग में लायी जाती है। इस करेंसी को सॉवरेन मुद्रा यानी उस देश की करेंसी में बदला जा सकता है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी में इस तरह की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। क्रिप्टोकरेंसी की तरह डिजिटल करेंसी की वैल्यू में किसी तरह का उतार-चढाव नहीं होता है जबकि क्रिप्टोकरेंसी में उतार-चढ़ाव होते हैं। इसका एक उदाहरण बिटकॉइन है। बिटकॉइन की वैल्यू में आपको कई तरह के उतार-चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल करेंसी को देश की केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वहीं क्रिप्टोकरेंसी में ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है । क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। जहाँ दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वहीं भारत में भी इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2021 में क्रिप्टोकरेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 अरब डॉलर था जो वर्ष 2022 तक लगभग तीन गुना बढ़कर 2.25 खरब डॉलर तक पहुँच गया है । लगभग 16,000 डिजिटल कॉइन अब प्रचलन में हैं । क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। किसी भी देश की करेंसी के लेन-देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है जैसे भारत में केंद्रीय बैंक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता है और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है।

वर्तमान समय में डिजिटल मुद्रा ने युवाओं को काफी तेजी से अपनी ओर आकर्षित किया है जिससे युवाओं का एक बड़ा तबका निवेश के लिए क्रिप्टोकरेंसी को अपना रहा है। ऐसे युवाओं को फाइनेंशियल मार्केट में लाने के लिए एंट्री पॉइंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक दिन भविष्य की करेंसी साबित होगी, क्योंकि युवाओं को इस पर भरोसा है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इससे होने वाली आपराधिक गतिविधियों को कैसे रोका जाए? अब बात क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे की है। युवाओं के इसकी ओर आकर्षित होने की वजह साफ है, कम दाम

और कम समय में होने वाले ज्यादा मुनाफे की उम्मीद। हालांकि, क्रिप्टो करेंसी के भाव गिरने पर लगाई गई रकम कम हो सकती है या डूब सकती है, लेकिन धैर्य और थोड़ा इंतजार किया तो क्रिप्टो का भाव कभी भी आसमान छू सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में दिन-रात उतार-चढ़ाव होता रहता है। हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसका इरादा निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने का है। इस बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के चेयरमैन श्री नंदन नीलेकणि ने क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में बयान देते हुए कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल देश में और ज्यादा वित्तीय समावेशन के लिए किया जा सकता है। श्री नीलेकणि ने रॉयटर्स नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में भविष्य में एसेट्स के रूप में क्रिप्टो की भूमिका को अहम बताया। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी की बात करें तो नाम आता है इथेरियम का। वहीं टॉप 10 डिजिटल मुद्राओं की बात करें तो इनमें पोल्काडॉट, टेथर, लाइटक्वाइन, डॉजक्वाइन समेत अन्य शामिल हैं। सबसे पहले साल 2009 में क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत हुई थी, जो बिटकॉइन थी। जापान के इंजीनियर सतोषी नाकमोतो ने इसे बनाया था। शुरुआत में इसे कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे-धीरे इसकी कीमत आसमान छूने लगी और ये पूरी दुनिया में छा गया। शुरुआत में बिटकॉइन का ही क्रिप्टो बाजार में दबदबा था, लेकिन समय के साथ ये बाजार बढ़ता गया और हजारों की संख्या में डिजिटल मुद्राएं चलन में आ गईं। आज क्रिप्टो के कारोबार का दायरा लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में फैल चुका है। क्रिप्टो करेंसी का लेन-देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन -देन का डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी की मदद से नियंत्रित होता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर वजीरएक्स, जेबपे, क्वाइनस्विच कुबेर, क्वाइन डीसीएक्स गो समेत कई एक्सचेंज संचालित है। इसके अलावा क्वाइन बेस और बिनान्से जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जहाँ से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और डॉजक्वाइन समेत दुनिया भर की डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती हैं।

सरकार की हमेशा से सोच रही है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। नियामक न होने

की वजह से क्रिप्टो में निवेश करते हुए लोगों में डर बना रहता है। ऐसे में सरकार यह सोच रही है कि इसे रेगुलेट करने से इस तरह का डर खत्म हो जाएगा। जागरुकता बढ़ने से भारत में इसके भविष्य को गति मिलेगी। नियामक आने पर निवेशक अच्छे से इससे जुड़ पाएंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि लोग निवेश करने का मन बना चुके हैं, सिर्फ इसके रेगुलेट होने का इंतजार कर रहे हैं। बजट 2022 में वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं क्रिप्टो करेंसी की हर एक लेन-देन पर अलग से 1% कर सरकार को देना होगा। बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए होंगे और इसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए होंगे। खुशी इसलिए क्योंकि, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब क्रिप्टोकरेंसी देश में लीगल हो गई है। सबसे पहले तो ये समझिए सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो डिजिटल एसेट या यूं कहें क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन पर लगा है जो फिलहाल गैर-कानूनी है। गौर करने की बात यह है कि सरकार इसे करेंसी नहीं मान रही है। तो अब भारत में डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल मुद्रा में निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। अब अगर खरीदने वाला इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसे अलग से उसकी कुल कीमत पर 1% के हिसाब से कर चुकाना होगा। कर किसी आय पर लगाया जाता है। जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार कर लेती है। कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक आय का ज़रिया मान रही है। वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स का एलान होते ही कई लोगों ने यह मान लिया कि जो चीज टैक्स के दायरे में आ गई वो तो लीगल हो गई। जबकि ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपकी आय कहीं से भी हो, सरकार उस पर टैक्स वसूलती है। इससे आपके आय के लीगल होने की गारंटी नहीं मिल जाती। सरकार सिर्फ उस डिजिटल मुद्रा को वैध मानती है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है या करेगा। मतलब अभी जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी हैं, वो वैध नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्चुअल करेंसी पर वहाँ की सरकारें टैक्स लगाती हैं। सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि हमारे देश में जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वो देश की आबादी का लगभग 8% हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपए इस समय ऐसी वर्चुअल

करेंसी में लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए। सरकार अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में अपनी डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने अपने भाषण में किया है। जाहिर है ये करेंसी पूरी तरह लीगल होगी।

अगर बात की जाए फिजिकल करेंसी की तो उसके चोरी होने, खराब होने आदि का काफी डर रहता है। इसका रख-रखाव भी काफी अधिक करना पड़ता है। वहीं अगर ये पैसे डिजिटल फॉर्म में होंगे तो उसके रख-रखाव पर कम खर्च होगा और उसे ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं बात अब वैल्यू की करें तो जितनी वैल्यू 10 रुपये के नोट की है, उतनी ही 10 रुपये की डिजिटल करेंसी की होगी। जिस तरह आप अभी तमाम तरह के मोबाइल वॉलेट में पैसे रखते हैं। वैसे ही बाद में आप पैसे रख पाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा डिजिटल करेंसी आने के बाद हो सकता है कि धीरे-धीरे सिस्टम से नोट खत्म हो जाएं। अगर अभी की बात करें तो कैश कहाँ जाता है, इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। कोई भी शख्स किसी को कैश देता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन डिजिटल करेंसी में इसकी ट्रैकिंग बेहद आसान हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि कालेधन पर लगाम लग सकेगी और टैक्स चोरी की वजह से सरकार को आय में जो नुकसान होता है, वह भी कम होगा या धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। फिजिकल करेंसी के मुकाबले डिजिटल करेंसी के सिर्फ फायदे ही नहीं हैं, बल्कि कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो इसे साइबर चोरों से सुरक्षा देना होगा। जिस तरह अभी नोटों की सिक्योरिटी करनी पड़ती है, वैसे ही बाद में डिजिटल करेंसी की सुरक्षा के लिए तकनीकी रूप से तैयार रहना होगा। वहीं लेन-देन में अगर कोई तकनीकी दिक्कत आई तो सारा ट्रांजेक्शन सिस्टम रुक जाएगा जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। खैर, अभी ये सिर्फ अनुमान ही हैं और हकीकत में डिजिटल करेंसी आने के बाद क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और क्या चुनौतियाँ झेलनी होंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा।

*****

दिनेश कुमार अग्रवाल

पदनाम:- वैज्ञानिक / अभियंता एस जी
संस्था का नाम:- सैक इसरो, अहमदाबाद
मोबाइल नं. :- 09427458508
ई-मेल:- dinp2812@gmail.com

1.0 प्रस्तावना

2015 से लेकर 2022 तक के सफर में डिजिटल प्लेटफार्म में शॉपिंग करने, बिल भरने से लेकर बिजनेस करने तक सभी कार्यों के लिए भारत डिजिटल बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत डिजिटली बहुत प्रगति कर चुका है। मौजूदा वास्तविक मुद्रा के डिजिटलीकरण की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और इंटरनेट बैंक पेमेंट सिस्टम के साथ हुई थी। इसकी सहायता से बैंक अधिक कुशल और स्वतंत्र तरीके से ऋण के प्रवाह को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी होती है हालांकि इससे देश की बुनियादी मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भारत बैंकिंग के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। यह बदलाव भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा को लाकर करना चाहती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा देश की बुनियादी मुद्रा को प्रभावित करती है जिससे देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा सृजन और आपूर्ति के लिये मौजूदा बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं डिजिटल करेंसी का सृजन कर इसे सीधे उपभोक्ता तक पहुँचा सकेगा।

2.0 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी वैध मुद्रा सीबीडीसी है। यह आधिकारिक या वैध मुद्रा जैसी है और एक के बदले दूसरे के रुप में इसका विनिमय किया जा सकता है। केवल उसका रूप भिन्न है। एक प्रवृत्ति जो मौजूदा कोविड 19 महामारी से और मजबूत हुई है वो है भौतिक नकदी के उपयोग में गिरावट। घटनाक्रमों के कारण कई केन्द्रीय बैंकों और सरकारों ने वैध मुद्रा के डिजिटल संस्करण की खोज के प्रयास तेज किए हैं। केन्द्रीय बैंकों के बीच इसको लेकर कुछ रुचि स्थानीय कारणों से भी रही है कि इसके द्वारा नीतिगत उद्देश्यों को आगे बढ़ा सकें - उदाहरण के लिए ऋणात्मक

ब्याज दर, मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाना। डिजिटल करेंसी का फायदा ये होगा कि इससे डिजिटली लेन-देन कर सकेंगे।

3.0 डिजिटल करेंसी / मुद्रा क्या है:

प्रतिनिधि धन का हमेशा जारीकर्ता होता है। वह जारीकर्ता एक संप्रभु के रूप में विकसित हुआ है। अतीत में भी पैसे के निजी जारीकर्ता रहे हैं, लेकिन निजी मुद्रा में स्वाभाविक रूप से कई जारीकर्ता शामिल हो जाते हैं, जो इसे अस्थिर बना देते हैं। ऐसी निजी मुद्राओं के अधिक हानिकारक परिणामों से बचने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को कानूनी निविदा (legal tender) बनाने पर विचार कर रहे हैं।

जब किसी देश के नकदी रुपयों को डिजिटल सिस्टम में स्टोर किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है उसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। डिजिटल मुद्रा देश के नागरिकों और बैंकिंग सेक्टर को ऐसा मौका देगा जिससे पैसों को लेकर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता हुआ नजर आएगा जैसे बैंकों में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर वह कुछ ही मिनटों में अपना पैसा कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आमतौर पर एक वर्चुअल करेंसी है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा टेंडर के रूप में जारी किया जाता है। डिजिटल करेंसी उन सभी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जहाँ पर केंद्रीय बैंक इस करेंसी को जारी करता है। इस करेंसी का उपयोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए किया जाता है जैसे आप अपने बैंक खाते से अपने परिवार के किसी व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं।

सरकार ने यह तय किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक एक ऐसा तरीका लेकर आए जिससे भारत के लोग अपने पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें और डिजिटली कमा सकें। एक ऐसा तरीका जिससे लोगों का समय भी बचे और उनका पैसा सलामत भी रहे और साथ ही साथ यह देश डिजिटल उपकरणों को लेकर स्मार्ट बनें।

3.1 डिजिटल करेंसी की खासियत:

भारत की उच्च मुद्रा जीडीपी अनुपात में सीबीडीसी का एक और लाभ है। बड़े पैमाने पर हो रहे नकदी के उपयोग के स्थान पर सीबीडीसी को जितना लाया जा सकेगा,

मुद्रा की छपाई, परिवहन में बचत की जा सकेगी, भंडारण और वितरण की लागत को उतना ही कम किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी के तीन प्रकार हो सकते हैं जैसे: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी।

आभासी मुद्रा में सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी वह है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत ही बिटकॉइन करेंसी भी आती है, यह करेंसी फिजिकल नहीं होती है। आप इस करेंसी को छू नहीं सकते हैं। इस तरह की करेंसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है और न ही किसी डिजिटल वॉलेट में रखी जाती है। क्रिप्टो करेंसी में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते हैं जबकि डिजिटल करेंसी में किसी भी तरह का उतार-चढ़ाव नहीं होता है। एक ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से लेन-देन का एक डिजिटल खाताबही है जिसे ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में डुप्लिकेट और वितरित किया जाता है। ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में कई लेन-देन होते हैं और हर बार जब ब्लॉकचेन पर कोई नया लेन-देन होता है तो इस लेन-देन का रिकॉर्ड प्रत्येक प्रतिभागी की खाता बही में जोड़ दिया जाता है। डिजिटल मुद्रा से दो पार्टियों के बीच संपर्क रहित लेन-देन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपके बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी और को भुगतान किया जाता है। सभी ऑनलाइन लेन-देन में डिजिटल मुद्रा शामिल होती हैं, एक बार जब आप उस पैसे को बैंक या एटीएम से निकाल लेते हैं तो वह डिजिटल मुद्रा तरल नकदी में बदल जाती है।

क्रिप्टोकरेंसी जो एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित है, ये डिजिटल सिक्के सभी निजी स्वामित्व में हैं और बनाए गए हैं तथा अभी तक अधिकांश देशों में नियमित नहीं किए गए हैं।

डिजिटल मुद्रा को एन्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है लेकिन हैकिंग और चोरी की संभावना को कम करने के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को अपने डिजिटल वॉलेट और बैंकिंग ऐप को मजबूत पासवर्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

क्रिप्टो करेंसी को मजबूत एन्क्रिप्शन द्वारा संरक्षित किया जाता है और क्रिप्टो में व्यापार करने में सक्षम होने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास पैसे के साथ एक बैंक खाता होना चाहिए और इस डिजिटल मुद्रा का आदान-प्रदान एक ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से किया जा सकता है ताकि संबंधित मूल्य की क्रिप्टो करेंसी प्राप्त की जा सके।

जब विनियमन की बात आती है तो डिजिटल मुद्राओं को भारत में एक केंद्रीय प्राधिकरण आरबीआई द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी के मामले में, यह एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली है और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं है। हालांकि, सभी क्रिप्टो लेन-देन एक विकेन्द्रीकृत खाता बही में दर्ज किए जाते हैं जो सभी के लिए उपलब्ध हैं।

स्थिरता के मोर्चे पर डिजिटल मुद्राएं स्थिर और प्रबंधन में आसान होती हैं क्योंकि उन्हें वैश्विक बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर क्रिप्टो बहुत अस्थिर है और दरें लगभग नियमित रूप से बढ़ती और गिरती हैं।

डिजिटल मुद्रा लेन-देन का विवरण केवल इसमें शामिल लोगों, प्रेषक एवं रिसीवर और बैंक के लिए उपलब्ध है। क्रिप्टो लेन-देन का विवरण विकेन्द्रीकृत खाता बही के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है।

3.2 डिजिटल करेंसी की विशेषताएं एवं लाभ:

- डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्य किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नकदी रुपयों पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा। लोगों को अकसर नकदी रुपयों को रखने में और इस्तेमाल करने में परेशानी होती है इसलिए इस मुद्रा के आने से लोगों को नकदी रुपए के ऊपर निर्भर होने से छुटकारा मिल सकेगा।
- डिजिटल करेंसी को रिटेलर होलसेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी विचार किया जा रहा है।
- यह पैसा जमा कराने और निकलवाने के तरीके को काफी आसान कर देगा, पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक होगा तो लोगों को काफी समय तक लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पैसों को स्टोर कर सकेंगे।
- डिजिटल करेंसी से लोगों को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा महसूस होगी और उनके पैसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
- डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को अपने देश के बाहर या फिर देश में ही पैसे ट्रांसफर करने या जमा करने के लिए अलग-अलग समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिससे बैंकिंग फ्रॉड जैसे कामों में भी कमी आएगी।

- समय प्रभावी: क्रिप्टो करेंसी धनप्रेषक और रिसीवर के लिए पर्याप्त समय बचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से इंटरनेट पर संचालित होता है तथा यह लगभग तात्कालिक होता है।
- यह अन्य ऑनलाइन लेन-देन की तुलना में एक सस्ता विकल्प है। फंड ट्रांसफर न्यूनतम प्रोसेसिंग फीस के साथ पूरा किया जाता है। दूसरी तरफ बैंक, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे जैसे मध्यस्थ अपनी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में $100 ट्रिलियन से अधिक के कुल वैश्विक आर्थिक उत्पादन से लगभग 3% आकर्षित करते हैं। यह फीस इन माध्यमों को महंगा बनाती है।
- भुगतान सुरक्षित हैं और गुमनामी का एक अभूतपूर्व स्तर प्रदान करते हैं।
- भ्रष्टाचार की जाँच: चूंकि ब्लॉक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर चलते हैं, यह धन के प्रवाह और लेन-देन को ट्रैक करके भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।

यह "अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली" बनाने में मदद करेगा। नियमित रुपये के विपरीत, डिजिटल रुपये को ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेषक और प्राप्तकर्ता ब्लॉकचेन का उपयोग करके लेन-देन कर सकते हैं और आरबीआई इसका गारंटर होगा।

3.3 हानियाँ:

हालाँकि, अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकती है:

- इस तकनीक से कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों (जैसे नार्को-टेररिज्म फंडिंग) को बढ़ावा मिल सकता है जिससे अंततः सरकार को राजस्व की हानि होगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा।
- चूंकि हमारे पास उचित वित्तीय और डिजिटल साक्षरता नहीं है इसलिए यह डिजिटल डिवाइड को बढ़ा सकती है:
- बिचौलियों को बढ़ावा दे सकती है।
- लोगों की मेहनत की कमाई को नष्ट कर सकती है क्योंकि इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। इसके कारण सरकार के "डिजिटल इंडिया", " जन धन योजना" जैसे प्रयासों पर से लोगों का विश्वास उठ सकता है जो देश के वित्तीय समावेशन के लिए बहुत हानिकारक होगा।

- पर्यावरण के लिए हानिकारक: जैसे-जैसे अधिक शहरी भारतीय क्रिप्टोकरेंसी को अपनाना शुरू करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप की मांग बढ़ती है, अंततः ई-कचरे में वृद्धि होती है। पिछले साल, बिटकॉइन माइनिंग सुपर कंप्यूटर द्वारा बिजली के अति प्रयोग के कारण ईरान में ब्लैक आउट हुआ था। यह मानवता के समग्र कार्बन पदचिह्न को बढ़ाता है।
- क्रिप्टो करेंसी में जालसाजी और धोखाधड़ी लेन-देन को रोकने के लिए यह क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर करता है। यह आमतौर पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसका दुनिया भर में समान मूल्य है। वर्तमान समय में लगभग 13000 से भी ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी प्रचलन में है, उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं- बिटकॉइन, क्रैडानो, लाइटकोइन, एथेरियम, रिपल, डॉगकोइन इत्यादि।

अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। कनाडा, जापान और थाईलैंड जैसे देशों ने भुगतान पद्धति के रूप में आभासी मुद्राओं के उपयोग की अनुमति दी है। नाइजीरिया अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा (ई-नायरा) पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीयों द्वारा बनाई गई क्रिप्टो करेंसी का नाम पॉलीगॉन (Polygon) है।

4.0 भारत में लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी का भविष्य:

रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष में डिजिटल रूपी को लॉन्च करेगा। यह कहा गया था कि यह चरणवार तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अंतिम चरण में है। शुरुआत में इसे होलसेल ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में इसे रिटेल सेगमेंट के लिए भी शुरू किया जाएगा। सीबीडीसी कैश को रिप्लेस नहीं करेगा, जो लोग कैश का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग कैश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वे डिजिटल रूपी का इस्तेमाल करेंगे।

माना जा रहा है कि भारत में लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी दुनियाभर में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की तरह ही उपयोग की जाएगी। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिजिटल करेंसी सरकारी करेंसी होगी। इस पर सरकारी यानी कानून की मोहर होगी। डिजिटल करेंसी को कैसे उपयोग करें, इसकी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी की जाएगी। डिजिटल रुपये का उपयोग हमेशा पैसे का निशान छोड़ देगा। इसका मतलब है कि सरकार यह ट्रैक कर सकेगी कि आपने पैसे का

इस्तेमाल कहां और कैसे किया। इसमें शामिल पक्षों के वित्तीय लेन-देन को लीक और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सीबीडीसी रखने वाले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है।

5.0 उपसंहार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में मदद करेगा। साथ ही, इससे भारतीय नागरिकों को देश की पुरानी बैंकिंग प्रणाली से भी मुक्ति मिलेगी और भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम जुड़ सकेगा। अत्यधिक मानव पूंजी की क्षमता वाला प्रत्येक देश वर्तमान समय में डिजिटल क्रान्ति के शिखर पर पहुंचने को प्रयत्नशील है। यदि भारत अपने मानव पूंजी, संसाधनों तथा विशेषज्ञता का सही तरीके से इस क्रांति में इस्तेमाल करता है तो यह इस क्रांति के शिखर पर पहुंचने के साथ – साथ इसका नेतृत्व भी कर सकता है।

6.0 संदर्भ:

इन्टरनेट की वेबसाइट, आरबीआई बुलेटिन अगस्त 2021

*****

ध्रुवी तैलवानी

पदनाम:- सहायक प्रबंधक

संस्था का नाम:- दी न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

मोबाइल नं. :- 8320500353

ई-मेल:- dhruvi.tailwani@newindia.co.in

सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डिजिटल मुद्रा क्या है? यह एक प्रकार की मुद्रा है जो केवल डिजिटल रूप में उपलब्ध है भौतिक रूप में नहीं। यह भौतिक मुद्राओं के समान गुण वाली ही होती है लेकिन तत्काल लेन-देन एवं सीमाहीन स्थानांतरण स्वामित्व के लिए अनुमति देती है।

डिजिटल रूपी कानूनी मुद्रा होगी। यह रुपए का डिजिटल रूप होगा। इसे किसी भी करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी आने से आरबीआई को भारी बचत हो सकती है।

आम मुद्रा की तरह लेन-देन में इसका चलन होगा, लेकिन इसे भौतिक रूप में नहीं, डिजिटल रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इसे डिजिटल बटुए में रखा जा सकेगा और वहीं से भुगतान और ऑनलाइन खरीदारी संभव होगी। इस तरह डिजिटल रुपया कागज के नोट की जगह बदला जा सकेगा। तो कुल मिलाकर यह डिजिटल रुपया एक तरह से कागज के नोट का डिजिटल संस्करण होगा।

हर दूसरे क्षेत्र की तरह तकनीकी नवाचारों ने सामाजिक व्यवहार में भारी बदलाव किया है - व्यवसायों और उपभोक्ताओं ने सक्रिय रूप से भुगतान करने या भुगतान करने के लिए संपर्क रहित भुगतान, डिजिटल वॉलेट एवं आभासी भुगतान समाधान और सुविधा की मांग की है, विशेष रूप से जब से महामारी का प्रकोप बढ़ा हैं। लेकिन यह तभी होगा जब संसद क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का विनियमन पारित करेगी जो आरबीआई को डिजिटल रुपया जारी करने का अधिकार देगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जहाँ आज से पहले हमारे देश में किसी चीज को खरीदने के लिए अधिकतर नकदी मुद्रा का

इस्तेमाल होता रहा है, वहीं अब देश की मोदी सरकार द्वारा भारत में डिजिटल करेंसी को शुरू कर लेन-देन के तरीके को डिजिटल रूप दे दिया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर का कहना है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल मुद्रा को जारी करने वाली है।

वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा और ये भारत सरकार की आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगी। इसके अलावा उन्होंने बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से होने वाले मुनाफे पर फ्लैट 30% टैक्स की भी घोषणा की थी।

क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की ओर आज लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नई पीढ़ी विशेषकर युवा डिजिटल मुद्रा की ओर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल मुद्रा में निवेश से पहले इसे अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है ताकि इसमें निवेश करने वाले लोग अच्छा लाभ कमा सकें।

डिजिटल मुद्रा लगभग एक दशक पहले बाजार में आई। लेकिन उस समय लोगों का इसकी ओर रुझान नहीं था। अब लोग इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। यह तो साफ है कि ब्लॉकचेन आने वाले कल का भविष्य है। जिस तरह से नई पीढ़ी डिजिटल मुद्रा के रूप में पैसे को समझती है। क्रिप्टो मुद्रा की स्थापना के बाद से कई टोकन या सिक्के उत्पन्न और निवेश किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में लकी ब्लॉक यानी एल-ब्लॉक निवेशकों के बीच में जगह बना रहा है। लकी ब्लॉक एक टोकन है जो बढ़ते टोकन के सभी रंग दिखाता है। वैश्विक लॉटरी ब्लॉकचेन एल-ब्लॉक के आधार पर जिसे एक्सचेंजों पर पसंद किया जाता है। यह वर्ष 2022 की बढ़ती क्रिप्टो मुद्राओं में से एक है।

टोकन के पहले पूर्व-बिक्री प्रस्ताव में, एल-ब्लॉक का मूल्यांकन केवल 3 सप्ताह में 5.7 मिलियन डॉलर से 700 मिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। विश्व स्तर पर 32000 धारकों के साथ शिखर पर चढ़ने वाले सदस्य एक समूह पर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एल-ब्लॉक का कारोबार 4 प्रमुख एक्सचेंजों पर होता है और भी बहुत कुछ आने वाला है। प्रीसेल का दूसरा चरण भी जल्द ही होने वाला है। उन्होंने बताया कि लकी ब्लॉक अपना ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है।

भारत सरकार डिजिटल करेंसी इसलिए लॉन्च कर रही है क्योंकि आज कल डिजिटल करेंसी का जमाना है और भारत किसी भी मायने में दूसरे देशों से पीछे नहीं रहना चाहता है । हम सब की तरह सरकार ने भी ये मान लिया है कि इस करेंसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार ने वर्चुअल करेंसी के वजूद को नकारने के बजाय अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया है । नियमित करेंसी के विपरीत आपको डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, इसलिए आप इसे सीधे दूसरे व्यक्ति के डिजिटल रुपये वाले वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

एक डिजिटल करेंसी मूल रूप से बिटकॉइन और एथेरियम जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी से अलग होगी क्योंकि यह राज्य द्वारा समर्थित होगी और इसका आंतरिक मूल्य होगा। सरकार ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल एसेट्स कहा है। यानी वो लीगल टेंडर नहीं होंगे।

इस डिजिटल करेंसी को मुद्रा के रूप में गिना जाएगा। इससे सरकार को कम नोट छापने और नकली मुद्रा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह "अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली" बनाने में मदद करेगा । नियमित रुपये के विपरीत, डिजिटल रुपये को ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेषक और प्राप्तकर्ता ब्लॉकचेन का उपयोग करके लेन-देन कर सकते हैं और गारंटी आरबीआई द्वारा दी जाएगी।

रिजर्व बैंक का डिजिटल रूपी कानूनी मुद्रा होगी। इसे आरबीआई की तरफ से कानूनी मान्यता मिली होगी । यह रुपए का डिजिटल रूप होगा । इसे किसी भी करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकता है । क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण दुनियाभर के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की दिशा में काम कर रहे हैं। 2021 में एक सर्वे आया था, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने पाया कि दुनिया के 86 फीसदी सेंट्रल बैंक सीबीडीसी की दिशा में काम कर रहे हैं। 60 फीसदी बैंक डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहीं 14 फीसदी बैंक पायलट प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वो करेंसी होगी जो केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा होगी। यह "ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों" पर आधारित होगी । सरल शब्दों में कहें तो सीबीडीसी भारतीय रुपये का एक डिजिटल रूप होगा। एक बार जब आरबीआई डिजिटल करेंसी को जारी करना शुरू

कर देगा तो हम और आप जैसे आम लोग नियमित रुपये की तरह ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल रुपया आपके एनईएफटी, आईएमपीएस या डिजिटल वॉलेट की तरह होगा। आप इसका उपयोग थोक लेन-देन या खुदरा भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। आप इसे विदेशों में भी भेज सकते हैं। आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जहां आज से पहले हमारे देश में किसी चीज को खरीदने के लिए अधिकतर नकदी मुद्रा का इस्तेमाल होता रहा है, वहीं अब देश की मोदी सरकार ने भारत में डिजिटल करेंसी को शुरू कर लेन-देन के तरीके को डिजिटल रूप दे दिया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कहना है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल मुद्रा को जारी करने वाली है।

यह डिजिटल करेंसी नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप होगा, जिसे देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। इस करेंसी को केवल देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंसशीट में भी इसे शामिल किया जायेगा। इस डिजिटल मुद्रा की खास बात यह होगी कि इसे सॉवरेन करेंसी में भी बदला जा सकेगा तथा यह भारत का डिजिटल रुपया होगा।

इस डिजिटल करेंसी की सबसे खास बात यह होगी की इसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जायेगा जिससे लोगों को उनके पैसों के डूबने का खतरा भी नहीं होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी हैं। यह एक लीगल टेंडर होगा। आरबीआई के मुताबिक यह सेंट्रल बैंक द्वारा इश्यू की गई करेंसी होगी लेकिन पेपर या पॉलिमर से अलग होगी। यह एक सॉवरेन करेंसी है और सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में इसे लायबलिटी के तौर पर दिखाया जाएगा। सीबीडीसी को बराबर मूल्य पर कैश में एक्सचेंज किया जा सकेगा।

डिजिटल करेंसी को जलाया या डैमेज नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बार जारी किए जाने के बाद ये हमेशा रहेंगे जबकि नोट के साथ ऐसा नहीं होता है। किफायती होने की वजह से सीबीडीसी को लेकर दुनियाभर में काफी अधिक दिलचस्पी देखने को मिली है। हालांकि, अब तक कुछ ही देश इस मामले में पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ पाएं हैं। सीबीडीसी किसी भी देश की ऑफिशियल करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन होता है।

डिजिटल रुपये वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी होगी। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है-रिटेल और होलसेल। होलसेल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वहीं रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती हैं।

वास्तव में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विकेंद्रित होती है। इसका मतलब है कि सभी तरह की सूचनाएं एक नेटवर्क के सभी कंप्यूटर पर होती है। हालांकि, डिजिटल रुपया इससे अलग होगा। इसकी वजह यह है कि इसे आरबीआई रेगुलेट करेगा। यह वास्तव में विकेंद्रित नहीं होगा। इसे आसानी से आप मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और आप हर तरह के सामान खरीद पाएंगे और सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे।

जब आप कोई सर्विस या गुड्स खरीदते हैं और कैश पेमेंट करते हैं। यह पेमेंट का फाइनल रूप है। डिजिटल रूपी लॉन्च होने के बाद कैश की जगह डिजिटल रूपी से पेमेंट किया जा सकेगा। यह भी पूरी तरह फाइनल पेमेंट माना जाएगा। डिजिटल रूपी लॉन्च होने के बाद भारत में बैठा व्यापारी अमेरिका और यूरोप के व्यापारियों को डिजिटल डॉलर या डिजिटल पॉन्ड में पेमेंट कर सकता है। यह रियल टाइम पेमेंट होगा और ऐसे ट्रांजैक्शन में किसी इंटरमिडयरी की जरूरत नहीं होगी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। यह भारत सरकार की आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगी। डिजिटल रूपी को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के काट के रूप में देख रहे हैं। डिजिटल रूपी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसे वर्तमान मुद्रा के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। यह वर्चुअल करेंसी जरूर है, लेकिन इसकी तुलना प्राइवेट करेंसी से नहीं की जा सकती है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की चर्चा लंबे समय से हो रही है। रिजर्व बैंक प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी का लगातार विरोध करता रहा है। उसका कहना है कि यह फाइनेंशियल सिस्टम और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि डिजिटल रूपी की अच्छी और बुरी बातें क्या हो सकती हैं।

अगर डिजिटल रूपी से पेमेंट किया जाता है तो यह फाइनल सेटलमेंट की तरह होगा। इसमें सेटलमेंट रिस्क नहीं शामिल होता है। आसान शब्दों में जब आप कोई सर्विस या गुड्स खरीदते हैं और कैश पेमेंट करते हैं, यह पेमेंट का फाइनल रूप है। डिजिटल रूपी लॉन्च होने के बाद कैश की जगह डिजिटल रूपी से पेमेंट किया जा सकेगा। यह

भी पूरी तरह फाइनल पेमेंट माना जाएगा। डिजिटल रूपी लॉन्च होने के बाद भारत में बैठा व्यापारी अमेरिका और यूरोप के व्यापारियों को डिजिटल डॉलर या डिजिटल पाउंड में पेमेंट कर सकता है। यह रियल टाइम पेमेंट होगा और ऐसे ट्रांजैक्शन में किसी इंटरमिडयरी की जरूरत नहीं होगी।

डिजिटल करेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के कारण फ्रॉड और स्कैम के मामले बढ़ सकते हैं। खुद गवर्नर शक्तिकांत दास कई मौकों पर कह चुके हैं कि डिजिटल करेंसी के साथ फ्रॉड सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस करेंसी के इस्तेमाल और प्रचलन के लिए पूरे देश में इंटरनेट की अच्छी स्पीड जरूरी है। हाई स्पीड इंटरनेट का इन्फ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं हो जाता है, डिजिटल करेंसी की सफलता की आशा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी देश में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कम है तो वहां सीबीडीसी की पहुंच और उपयोगिता काफी कम हो जाएगी।

एक वर्ष में देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन आज, भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव की आशाजनक संभावनाओं के साथ डिजिटल मुद्राओं जैसे नए नवाचारों का भी इंतजार है।

क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की ओर आज लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नई पीढ़ी विशेषकर युवा डिजिटल मुद्रा की ओर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटल मुद्रा में निवेश से पहले इसे अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है जिससे कि इसमें निवेश करने वाले लोग अच्छा लाभ कमा सकें।

*****

पंकज कुमार मिश्रा

पदनाम:- प्रबंधक (टीपीएम)

संस्था का नाम:- गुजरात रिफ़ाइनरी, वड़ोदरा

मोबाइल नं. :- 9408707153

ई-मेल:- PKMISHRA@INDIANOIL.IN

क्यों खबर में ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अपनी **डिजिटल मुद्रा** के लिए चरणबद्ध **कार्यान्वयन रणनीति** पर काम कर रहा है और **निकट भविष्य में इसे थोक और खुदरा क्षेत्रों में** आरंभ करने की प्रक्रिया में है।

वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक **उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति** ने **आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढांचे में बदलाव** के साथ **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)** की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोटों को जारी करने को विनियमित करने का अधिकार देता है।

मुख्य बिंदु

- ✓ यह एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है।
- ✓ इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।
- ✓ हालांकि यह भौतिक मुद्राओं के समान है, डिजिटल धन स्वामित्व के साथ-साथ तात्कालिक लेन-देन के सीमारहित हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- ✓ डिजिटल मुद्रा को डिजिटल मनी और साइबर कैश के रूप में भी जाना जाता है।

उदाहरण के लिए **क्रिप्टोकरेंसी**

ज़रूरत:

1. **कदाचार को इंगित करना:**

- ✓ एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी के अराजक डिजाइन से उत्पन्न होती है, जिसमें उनके निर्माण, साथ ही रखरखाव, जनता के

हाथों में है।

- ✓ बिना किसी सरकारी पर्यवेक्षण और सीमा पार भुगतान में आसानी के साथ, उन्हें कर चोरी, आतंक वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे कदाचारों के लिए कमजोर बनाता है।
- ✓ डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करके केंद्रीय बैंक उनके कदाचार पर लगाम लगा सकता है।

2. अस्थिरता को इंगित करना:

- ✓ चूंकि क्रिप्टोकरेंसी किसी भी संपत्ति या मुद्रा के लिए आंकी नहीं जाती है, इसलिए इसका मूल्य पूरी तरह से अटकलों (मांग और आपूर्ति) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- ✓ इस वजह से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की वैल्यू में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
- ✓ जैसा कि सीबीडीसी को किसी भी संपत्ति (जैसे सोने या फिएट मुद्रा) के लिए आंका जाएगा और इसलिए क्रिप्टोकरेंसी में देखी जा रही अस्थिरता का गवाह नहीं होगा।

3. डिजिटल मुद्रा प्रोक्सी युद्ध:

- ✓ भारत एक प्रॉक्सी डिजिटल मुद्रा युद्ध के बवंडर में फंसने का जोखिम उठाता है क्योंकि अमेरिका और चीन नए युग के वित्तीय उत्पादों को पेश करके अन्य बाजारों में वर्चस्व हासिल करने के लिए लड़ते हैं।
- ✓ आज, एक संप्रभु डिजिटल रुपया केवल वित्तीय नवाचार का मामला नहीं है, बल्कि अपरिहार्य छद्म युद्ध के खिलाफ वापस धकेलने की आवश्यकता है जो हमारी राष्ट्रीय और वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

4. डॉलर पर निर्भरता को कम करना:

- ✓ डिजिटल रुपया भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार हेतु एक बेहतर मुद्रा के रूप में डिजिटल रुपये के प्रभुत्व को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती है।

महत्व

- ✓ यह किसी भी अंतर-बैंक निपटान के बिना वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा।

- ✓ भारत के काफी उच्च मुद्रा-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का एक और लाभ है - इस हद तक बड़े नकदी उपयोग को (CBDC) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कागज मुद्रा को मुद्रित करने, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- ✓ यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता के नुकसान को कम से कम करेगा।

मुद्दे:

- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक की परीक्षा के अंतर्गत कुछ प्रमुख मुद्दों में सीबीडीसी का दायरा, अंतर्निहित प्रौद्योगिकी, सत्यापन तंत्र और वितरण संरचना शामिल हैं।
- ✓ इसके अलावा, कानूनी परिवर्तन आवश्यक होंगे क्योंकि वर्तमान प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत भौतिक रूप में मुद्रा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
- ✓ सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिणामी संशोधनों की भी आवश्यकता होगी।
- ✓ तनाव के तहत एक बैंक से पैसे की अचानक उड़ान चिंता का एक और मुद्दा है।

हाल के घटनाक्रम:

- ✓ अल साल्वाडोर, मध्य अमेरिका में एक छोटा तटीय देश, कानूनी निविदा के रूप में बिटकॉइन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- ✓ ब्रिटेन भी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना की तलाश कर रहा है।
- ✓ 2020 में, चीन ने अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करना शुरू कर दिया, जिसे अनौपचारिक रूप से "डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डीसी/ ईपी" कहा जाता है।
- ✓ अप्रैल 2018 में, RBI ने धोखाधड़ी के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग किए जाने के बाद बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो लेन-देन का समर्थन करने से प्रतिबंधित कर दिया । मार्च 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया था।

आगे बढ़ने का रास्ता

- ✓ डिजिटल रुपये का निर्माण भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें हमारी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग करने और पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा।
- ✓ मैक्रोइकोनॉमी और तरलता, बैंकिंग प्रणालियों और मुद्रा बाजारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, नीति निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे भारत में डिजिटल रुपये की संभावनाओं पर पूरी तरह से विचार करें।

*****

प्रकाश कुमार भालाला

पदनाम:- सीनियर फोरमैन

संस्था का नाम:- गेल (इंडिया) लिमिटेड, वड़ोदरा

मोबाइल नं. :- 8866312177

ई-मेल:- Bhalala.babubhai@gail.co.in

ऐसा कहा जाता है कि भारत उन चुनिंदा प्राचीन सभ्यताओं (चीन और ग्रीस) में शुमार है, जिसने सबसे पहले मुद्रा का चलन आरंभ किया। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तु विनिमय चलता था, लेकिन बाद में लोगों की जरूरतें बढ़ीं और वस्तु विनिमय में कठिनाइयां पैदा होने लगीं जिसके कारण कौड़ियों से व्यापार आरंभ हुआ, जो कि बाद में सिक्कों में बदल गया। भारत के मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल (1540-1545) में चाँदी के सिक्के से लेकर बाद में तांबे, सीसे, पोटिन, कांसे, निकल, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, कागज की नोट और अंततः डिजिटल मुद्रा के स्वरुप में परिवर्तन हुआ।

जैसा कि श्रीमद् भगवद्गीता के नौवें अध्याय के दसवें श्लोक में कहा गया है कि

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥

अर्थात् सृष्टि में आने वाले बदलाव चिरंतन और अपरिवर्तनशील है. भगवान श्री कृष्ण

प्रकृति के नियमों और उनके संचालन के बारे में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि विश्व में सतत् परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन समय के आधीन होते रहते हैं।

डिजिटल मुद्रा क्या है ?:

डिजिटल मुद्राओं में भौतिक विशेषताएं नहीं होती हैं और ये केवल डिजिटल रूप में उपलब्ध होती हैं। डिजिटल मुद्राओं से जुड़े लेन-देन कंप्यूटर या इंटरनेट या निर्दिष्ट नेटवर्क से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का उपयोग करके किए जाते हैं। इसके विपरीत, भौतिक मुद्राएं जैसे कि बैंक नोट और ढाले हुए सिक्के, मूर्त हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास निश्चित भौतिक गुण और विशेषताएं हैं। ऐसी मुद्राओं से जुड़े लेन-देन तभी संभव होते हैं जब उनके धारकों के पास इन मुद्राओं का भौतिक अधिकार हो, डिजिटल मुद्राओं की उपयोगिता भौतिक मुद्राओं के समान होती है।

वर्चुअल मुद्रा बनाम डिजिटल मुद्रा:

किसी विशेष मुद्रा (पारंपरिक अर्थ में धन) में अंकित धन में भौतिक स्वरूप में धन शामिल होता है (नोट और सिक्के, आमतौर पर कानूनी निविदा स्थिति के साथ) और धन के विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व, जैसे केंद्रीय बैंक धन (केंद्रीय बैंक में जमा) जिसका उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है या वाणिज्यिक बैंक धन।

1969 में आईबीएम इंजीनियर फॉरेस्ट बैरी के पास प्लास्टिक कार्ड के पीछे एक चुंबकीय पट्टी चिपकाने का क्रांतिकारी विचार था। इस आविष्कार के साथ, क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ और इसने मौद्रिक लेन-देन की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। यू.पी.आई, कार्ड या नेट बैंकिंग लेन-देन में आप एक व्यापारी को अपने खाते से भुगतान "**खींचने**" के लिए अधिकृत कर रहे हैं, यह प्रक्रिया वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से गुजर रहा है। उदाहरण के लिए एक ग्राहक शॉपिंग करने जाता है और उस व्यापारी के साथ डिजिटल लेन-देन में आम तौर पर पांच पक्ष शामिल होते हैं: व्यक्तिगत कार्डधारक, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, व्यापारी, अधिग्रहणकर्ता (वित्तीय संस्थान जो व्यापारी के भुगतान को सक्षम करता है) और जारीकर्ता (कार्ड धारक का बैंक)। कभी-कभी, एक छठा पक्ष होता है- भुगतान प्रोसेसर, हालांकि कई अधिग्रहण करने वाले बैंक भी होते हैं।

वर्तमान समय में यू.पी.आई, कार्ड या नेट बैंकिंग से कुछ इसी तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन होता हैं यह नीचे दिए गए चार्ट से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं।

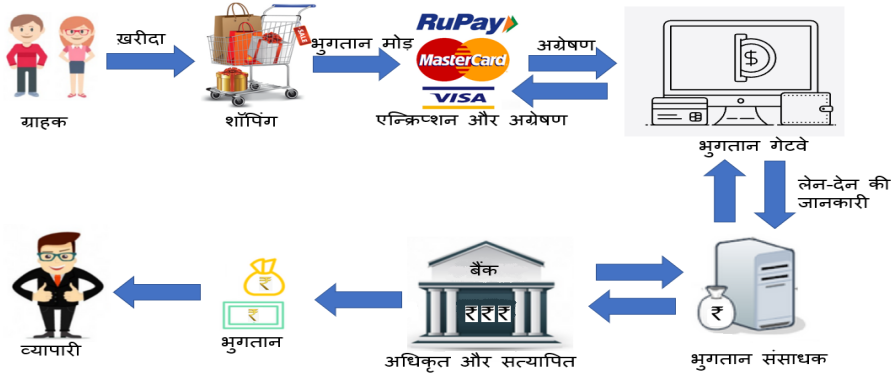

पारंपरिक ई-मनी के विपरीत वे किसी व्यक्ति या संस्था की देनदारी नहीं हैं, न ही वे किसी प्राधिकरण द्वारा समर्थित हैं। परिणामतः उनका मूल्य केवल इस विश्वास पर निर्भर करता है कि बाद में समय पर अन्य वस्तुओं या सेवाओं या एक निश्चित मात्रा में संप्रभु मुद्रा के लिए उनका आदान-प्रदान किया जा सकता है।

डिजिटल मुद्रा का स्वयं कोई मूल्य नहीं होता है। यह फिएट मुद्रा की तरह है जो भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है। डिजिटल मुद्रा का स्वरुप मूल्य आपूर्ति और मांग से निर्मित होता है, न कि इसके पीछे की भौतिक सामग्री से। कोई चीज तभी मूल्यवान है जब सभी सहमत हों कि वह मूल्यवान है। इससे पहले कि लोग इसका उपयोग करना शुरू करें, डिजिटल मुद्रा का एक मूल्य होना चाहिए। आपूर्ति और मांग के कारण अन्य मुद्राओं के संबंध में मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता हैं। मांग का अर्थ है सिस्टम के अधिक उपयोगकर्ता और सिस्टम के अधिक उपयोगकर्ता का अर्थ है अधिक लेन-देन और सिक्का परिचालित हो जाना। अधिक उपयोगकर्ता का अर्थ है मुद्रा का उच्च मूल्य।

डिजिटल मुद्रा एक ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है जो एक डिजिटल लेज़र है जिसमें डिजिटल मुद्रा में किए गए लेन-देन कालानुक्रमिक और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक एक रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है, जिसे ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके जुड़े और सुरक्षित होते हैं, जो डिजिटल मुद्रा मोड में क्रिप्टो मुद्रा की वैधता प्रदान करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में आम तौर पर पिछले ब्लॉक, टाइमस्टैम्प और लेन-देन डेटा के लिंक के रूप में हैश पॉइंटर होता है। डिज़ाइन द्वारा ब्लॉकचेन डेटा के संशोधन के लिए स्वाभाविक रूप से

प्रतिरोधी हैं, जो उच्च सुरक्षा पैदा करते हैं। बिना किसी अपवाद के सभी डिजिटल मुद्रा लेन-देन यहां दर्ज किया जाता है। एक बार इसे दर्ज करने के बाद इसे वापस नहीं किया जा सकता है। सभी के पास एक ही ब्लॉकचेन होगा और इसलिए रिकॉर्ड किए गए पिछले लेन-देन तक पहुंचना आसान है। जिसको नीचे दिए गए उदाहरण से हम बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं।

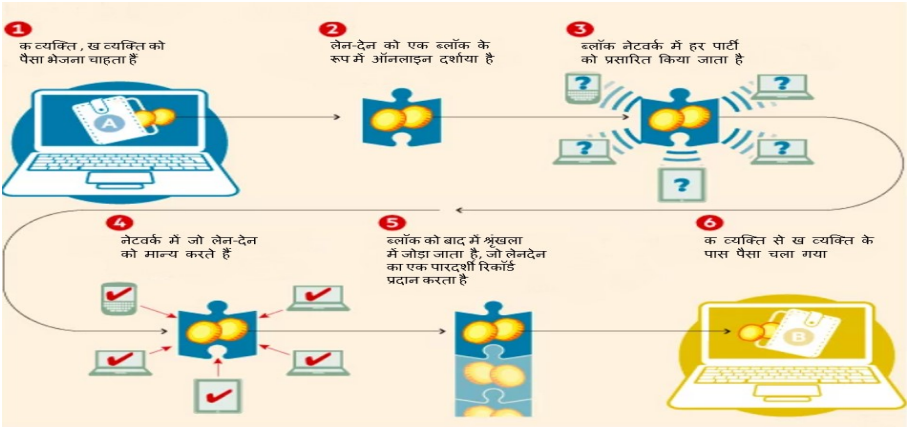

डिजिटल मुद्रा का वर्तमान:

ऐसा माना जाता है कि पहली बार 2008 में सतोशी नाकामोतो द्वारा प्रकाशित पत्र में डिजिटल मुद्रा को उल्लिखित किया गया था। 2009 की शुरुआत में सतोशी नाकामोटो ने जनता के लिए बिटकॉइन जारी किया और उत्साही समर्थकों के एक समूह ने मुद्रा का आदान-प्रदान और खनन शुरू किया। डिजिटल मुद्रा का एक अमूर्त रूप है जिसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने और इसे अपने बैंक खाते से जोड़ने की आवश्यकता होती है। जब भी आप कैब का भुगतान करने के लिए अपना फोन निकालते हैं या **ई-वॉलेट** से अपने बिलों का भुगतान करते हैं, तो आप इस डिजिटल मुद्रा आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ऐसा माना जा सकता हैं। आज बाजार में विभिन्न नवीन मुद्रा भुगतान प्रणालियां हैं, जिनमें से कई मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल स्टोरेज कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर निर्मित हैं। डिजिटल मुद्रा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया और रखा जाता है। डिजिटल मुद्राओं की प्रकृति को देखते हुए जो आम तौर पर ऑनलाइन होती हैं और इसलिए राष्ट्र तक सीमित नहीं होती हैं।

वर्तमान में डिजिटल मुद्रा योजनाओं का व्यापक रूप से उपयोग या स्वीकार नहीं किया

जाता है और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके भविष्य के विकास को सीमित कर सकते हैं । हालांकि, वित्तीय सेवाओं और व्यापक अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव आज नगण्य है और यह संभव है कि लंबी अवधि में वे मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं के दायरे में सीमित उपयोगकर्ता आधार के लिए एक उत्पाद बने रहें। ये डिजिटल मुद्रा एक मोबाइल ऐप, कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर या सेवा प्रदाता का उपयोग करके भेजे और प्राप्त किए जाते हैं जो एक वॉलेट प्रदान करता है। वॉलेट एक बैंक खाता संख्या के समान एक पता उत्पन्न करता है, जो एक अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक अनुक्रम हैं जहां उपयोगकर्ता भुगतान प्राप्त करना शुरू कर सकता है।

हालांकि हाल के वर्षों में कुछ डिजिटल मुद्रा योजनाओं का संचालन एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष की अनुपस्थिति में पीयर-टू-पीयर वैल्यू ट्रांसफर के लिए वितरित लेजर का उपयोग करने की व्यवहार्यता को अर्जित करता है । इन मुद्राओं को आमतौर पर डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत किया जाता है । इन पर्स में विशिष्ट सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जो उनकी रक्षा करती हैं, जैसे कि क्रिप्टोग्राफ़ी का उपयोग, जिसके लिए वॉलेट में मूल्य की इकाइयों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट कोड की आवश्यकता होती है। यदि ये कोड चोरी हो जाते हैं, तो मूल्य की इकाइयों को पर्स से चुराया जा सकता है । तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता अंतिम उपयोगकर्ता वॉलेट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

वर्तमान में डिजिटल मुद्राओं के भुगतान तंत्र इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि दुनिया भर के कई कंप्यूटरों पर लेन-देन और वॉलेट बैलेंस के रिकॉर्ड की एक सटीक प्रति संग्रहीत की जाती है। ये विभिन्न भुगतान तंत्र कुछ प्रकार के परिचालन जोखिम को कम कर सकते हैं। डिजिटल मुद्राओं और उनके भुगतान तंत्र में कानूनी जोखिम भी मौजूद हो सकते हैं। डिजिटल मुद्राएं नकदी की नकल करने के लिए होती हैं, इसलिए भुगतान की पुष्टि होते ही भुगतान आम तौर पर अंतिम और अपरिवर्तनीय होते हैं। लेन -देन में शामिल विभिन्न पक्षों के अधिकारों और दायित्वों की कोई कानूनी संरचना या स्पष्टता नहीं हो सकती है।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य :

भविष्य में डिजिटल मुद्रा फोरम की डिजिटल मौद्रिक बुनियादी ढांचे की उपयोगिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं । भविष्य में डिजिटल मौद्रिक प्रणाली को समाज द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से डेटा के उपयोग की सुविधा प्रदान करनी चाहिए । डिजिटल इनोवेशन सिस्टम के लिए कई नई चुनौतियां लेकर आया है और इन चुनौतियों में क्रिप्टो-एसेट्स, बिग टेक का भुगतान सेवाओं में प्रवेश और फेसबुक के नेतृत्व जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं । निजी संस्थाओं द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा विभिन्न भुगतान प्लेटफार्मों की अंतर-संचालन को सुरक्षित करते हुए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके आर्थिक लेन-देन की दक्षता बढ़ाने में योगदान कर सकती हैं। भविष्य में वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा के साथ ग्राहक डेटा के संचय और उपयोग में तेजी, एक दूसरे के साथ अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि कई बड़ी तकनीकी कंपनियां डिजिटल भुगतान सेवाओं में प्रवेश कर रही हैं।

भविष्य में इस डिजिटल करेंसी को मुद्रा के रूप में गिना जाएगा। इससे सरकार को कम नोट छापने और नकली मुद्रा पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी यह "अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली" बनाने में मदद करेगा । नियमित रुपये के विपरीत, डिजिटल रुपये को ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल करेंसी होने के कारण धोखाधड़ी की गुंजाइश न के बराबर है। दूसरा यह है कि इसकी कोई नियामक संस्था नहीं है, अतः नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का असर इस पर नही पड़ेगा।

भविष्य में डिजिटल मुद्रा किसी भी कारण से अपनी लोकप्रियता खो देता है, तो इसे बेहतर सुविधाओं के साथ बदलने के लिए एक नई क्रिप्टोकरेंसी सामने आएगी। भारी कर्ज वाले देशों में अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी बनाने के लिए प्रोत्साहन होता है और जो लोग वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे भी क्रिप्टोकरेंसी में बदल सकते हैं, क्योंकि विकेंद्रीकृत आंशिक रूप से वितरित प्रणाली बनाने में लागत कम है।

ब्लॉकचेन तकनीक के कारण क्रिप्टोकरेंसी के विकास का दृष्टिकोण बहुत अधिक आशावादी है । हमें इसके उपयोग में एक बड़ी छलांग देखने की संभावना है, एन.एफ.सी ।(गैर-वित्तीय प्रतिपक्ष) और संबंधित मोबाइल प्रौद्योगिकी इसके उछाल के पीछे चालक है। साथ ही भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि क्रिप्टोकरेंसी अगली बड़ी चीज है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी दुनिया में अभी भी बहुत अनिश्चितता है। लेकिन यह एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय संस्थान नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

संक्षेप में कहें तो दुनिया की हर चीज की तरह यहां भी सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ इससे सहमत हो सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डिजिटल मुद्रा भविष्य का मार्ग है। यह इंटरनेट की मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा के सफल होने के लिए अधिक से अधिक लोगों को होने की आवश्यकता है। डिजिटल मुद्रा वही देश अमल में ला सकते हैं जहां साक्षरता दर ज्यादा है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति पढ़ा-लिखा होना बहुत जरुरी है और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना जानता हो। पारंपरिक ई-मनी के विपरीत, डिजिटल मुद्राएं किसी व्यक्ति या संस्था की देनदारी नहीं है, न ही वे किसी प्राधिकरण द्वारा समर्थित हैं । इसके अलावा, उनके पास शून्य आंतरिक मूल्य है और परिणामस्वरूप वे केवल इस विश्वास से मूल्य प्राप्त करते हैं। अंत में डिजिटल मुद्राएं भुगतान और विकेंद्रीकृत नेटवर्क के मामले में एक सफलता है जिसे हम आज जानते हैं । यह अपने साथ विभिन्न लाभ और जोखिम लाता है जिसके प्रति उपयोगकर्ताओं को जागरूक होना चाहिए और वास्तव में इससे परिचित होना चाहिए।

*****

प्रदीप कुमार गोयल

पदनाम:- मुख्य प्रबंधक
संस्था का नाम:- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मोबाइल नं. :- 022-40345830
ई-मेल:- hindimmzo@centralbank.co.in

प्रस्तावना

यह हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में हमारे देश की केंद्र सरकार की वित्त मंत्री माननीया सुश्री निर्मला सीतारमण महोदया ने अपने पिछले बजट भाषण में डिजिटल मुद्रा के संबंध में विचार प्रकट किए थे, उन्होंने इसके लेन-देन पर अपने मंतव्य व्यक्त किए थे दूसरे दिन ही देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को अपने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया और वित्तीय बाजार में इसके लेन-देन संबंधी चर्चा जोरों से होने लगी थी। इस डिजिटल मुद्रा को आर्थिक बाजार में **'आभासी मुद्रा'**, **'डिजिटल करंसी**, **वर्चुअल करंसी**, **क्रिप्टो करंसी**, **डिजिटल मनी** और **साइबरकैश** आदि अनेक नामों से जाना जाता है यदि हम डिजिटल मुद्रा की हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो देश की 95 प्रतिशत आबादी वर्तमान में इस मुद्रा से अनभिज्ञ हैं।

आइए, हम जानते हैं कि आखिर यह डिजिटल मुद्रा क्या है; यह एक ऐसी मुद्रा है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध मूल्य का एक डिजिटल प्रतिनिधित्व करती है। इसे खास तौर से डिजाइन किए गए सॉफ़्टवेयर, मोबाइल या कंप्यूटर ऐप्लिकेशन के माध्यम से संग्रहित किया जाता है और इसका लेन-देन किया जाता है। डिजिटल मुद्राओं से जुड़े लेन-देन खास एवं सुरक्षित नेटवर्क या इंटरनेट पर होते हैं। डिजिटल मुद्राएं निजी पार्टियों या डेवलपर्स के समूहों द्वारा जारी किए जाते हैं और ज्यादातर अनियमित होते हैं। कहने का आशय यह है कि यह मुद्रा न तो केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है और न ही इसे नियंत्रित किया जाता है। डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक आभासी मुद्रा अथवा ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर-टू-पीयर कैश सिस्टम है। डिजिटल मुद्रा को डिजिटल वालेट में ही रखा जा सकता है। दरअसल, डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल के लिए बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान की ज़रूरत नहीं होती।

वित्तीय बाजार में यह बिटकॉइन, लिटेकॉइन और एक्सआरपी डिजिटल मुद्रा के रूप में शामिल है। डिजिटल मुद्राएं केन्द्रीकृत भी हो सकती है और विकेन्द्रीकृत भी। डिजिटल मुद्राएं डिजिटल मुद्राओं का एक सबसेट हैं और इसमें अन्य प्रकार की डिजिटल मुद्राएं शामिल हैं जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी और निजी संगठनों द्वारा जारी टोकन आदि।

वर्तमान में डिजिटल मुद्रा का स्वरूप: वर्तमान में डिजिटल मुद्राओं का लेन-देन काफी तेज गति से किया जा रहा है यानि इसका प्रचलन बढ़ रहा है। इसका उपयोग भी काफी आसान है। जबकि इन डिजिटल मुद्राओं का नुकसान यह है कि उन्हें हैक किया जा सकता है और इसके निवेशकों को कानूनी सहारा नहीं मिलता है क्योंकि ये डिजिटल मुद्राएं विनियमित नहीं होती हैं।

जब से हमारी भारत की सरकार ने इस डिजिटल मुद्रा पर ध्यान दिया है तब से हमारे देश का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और संभावित है कि निकट भविष्य में इसे थोक एवं खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करने की प्रक्रिया में रहेगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढाँचे में बदलाव के साथ केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की सिफारिश की थी, जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने के विनियमन का अधिकार देता है।

यहां यह जानना भी जरूरी है कि सभी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है, जबकि सभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हैं, बिटकॉइन एथेरियम और रिप्पल कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है।

वर्तमान वित्तीय बाजार में हर प्रकार की जटिलताओं के बावजूद बिटकॉइन और एप्रॉम जैसी क्रिप्टो करेंसी लगातार लोकप्रिय होती जा रही हैं और सरकारें चाहकर भी इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं।

इस डिजिटल मुद्रा के चलन के कारण विश्व के अनेक देशों के शीर्ष केंद्रीय बैंक का अनुभव है कि डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित करने की कोशिश निरर्थक है और इसलिए वे स्वयं के डिजिटल मुद्रा जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ऐसी खबरें है कि भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा होगी और इसका नाम "लक्ष्मी" होगा तथा इसे अपनी क्रिप्टो करेंसी फिएट के नाम से जाना जाएगा।

डिजिटल मुद्रा की उपलब्धता: आइए, हम जानते हैं कि इस प्रकार के डिजिटल मुद्रा कहां पाई जाती है ?

यह एक भुगतान विधि है, जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और इस मुद्रा का कोई मूर्त रूप नहीं है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्त्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। यद्यपि यह भौतिक मुद्राओं के समान•डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ-साथ तात्कालिक लेन-देन की अनुमति देती है। डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी और साइबरकेश के नाम से भी जाना जाता है।

डिजिटल मुद्रा की अस्थिरता :

चूंकि डिजिटल मुद्रा किसी संपत्ति या मुद्रा से जुड़ी हुई नहीं हैं, इसका मूल्य पूरी तरह से सट्टेबाज़ी (मांग और आपूर्ति) द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके कारण बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव आया है। निवेशकों को इसमें निवेश करने में जोखिम नजर आता है।

डिजिटल मुद्रा से भारत की डॉलर पर निर्भरता में कमी होगी:

डिजिटल रूपया भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार के लिए एक बेहतर मुद्रा के रूप में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक की जांच के अंतर्गत कुछ प्रमुख मुद्दों में सीबीडीसी का दायरा, अंतर्निहित तकनीक, सत्यापन तंत्र आदि शामिल हैं। इसके साथ ही कानूनी परिवर्तन आवश्यक होंगे; क्योंकि वर्तमान प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत भौतिक रूप में मुद्रा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

डिजिटल मुद्रा का निर्माण भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने तथा पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

मैक्रोइकॉनमी, तरलता, बैंकिंग सिस्टम एवं मुद्रा बाज़ारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति निर्माताओं के लिए भारत में डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर विचार करना अनिवार्य हो गया है।

गुजरे जमाने में मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग बार्टर सिस्टम के जरिए वस्तुओं का लेन-देन किया करते थे लेकिन जैसे-जैसे तकनीक उन्नत होती गई व्यापार के तरीकों में भी बदलाव आता गया। डिजिटल मुद्रा का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक है। डिजिटल मुद्रा को लेकर हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने यह आदेश पारित किया है कि लोग बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से बचें।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य इसलिए भी उज्जवल दिखाई पड़ता है; क्योंकि डिजिटल मुद्रा के माध्यम से लेन-देन के दौरान छद्म नाम एवं पहचान बताए जाते हैं। ऐसे में अपनी निजता को लेकर अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों को यह माध्यम उपयुक्त प्रतीत होता है।

डिजिटल मुद्रा में लेन-देन संबंधी लागत अत्यंत ही कम है। घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी लेन-देन की लागत एक समान ही होती है। डिजिटल मुद्रा के माध्यम से होने वाले लेन-देन में 'तृतीय पक्ष के प्रमाणन' की आवश्यकता नहीं होती। अतः धन एवं समय दोनों की बचत होती है।

डिजिटल मुद्रा में लेन-देन आदि बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि भौतिक मुद्रा में बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर लगभग सभी लेन- देन के लिए कई तरह के प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ती है, जबकि डिजिटल मुद्रा के मामले में ऐसा नहीं है वहीं भौतिक मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन के लिए भी कई तरह की औपचारिकताओं से गुजरना होता है, जबकि डिजिटल मुद्रा से होने वाले लेन-देन में इन बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

बैंकिंग प्रणालियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लेन-देन पर सरकार का सख्त नियंत्रण होता है वहीं डिजिटल मुद्रा उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर धन के आदान-प्रदान का एक विश्वसनीय और सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश डिजिटल मुद्रा प्लेटफार्म ओपन सोर्स पद्धति पर आधारित होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के सॉफ्टवेयर कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि डिजिटल मुद्रा प्लेटफार्म में लगातार सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं।

डिजिटल मुद्रा में यह भी गौरतलब है कि सरकारों के पास बैंक खाते को फ्रीज या जब्त करने का अधिकार है,लेकिन डिजिटल मुद्रा के मामले में वे ऐसा नहीं कर सकती है। अतः सरकार के नियंत्रण से बचाव के एक प्रभावकारी विकल्प के रूप में भी डिजिटल मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है इसलिए डिजिटल मुद्रा का चलन वर्तमान में तेजी से बढ़ता जा रहा है और इन सब कारणों से इसका भविष्य सुदृढ़ दिखाई देता है।

डिजिटल मुद्रा का प्रचलन जोखिम भरा हो सकता है।

डिजिटल मुद्रा एक असुरक्षित मुद्रा के रूप में जानी जाती है क्योंकि डिजिटल मुद्रा की सम्पूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है और इसके हैक होने का खतरा बना रहता है।

चूंकि डिजिटल मुद्रा प्रमुख वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहकर काम करती है, यही कारण है कि इसके स्त्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं। इससे देश की सुरक्षा संबंधी खतरे की आशंका बनी रहती है।

डिजिटल मुद्रा को फ्रॉड, हवाला मनी और आतंकी गतिविधियों को पोषित करने वाली मुद्रा के रूप में संदर्भित किया जाता रहा है। इसलिए यह मुद्रा राष्ट्रहित में नहीं मानी जा सकती है।

भारत जैसे विश्व के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसे अधिकृत मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा से संबंधित एक बड़ी समस्या इसके नियंत्रण एवं प्रबंधन की भी है।

आर्थिक बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी तकनीकी जानकारी रखे बिना इसमें निवेश करने के भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं यानी निवेश जोखिम भरा हो सकता है।

सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक बिटकॉइन लेन-देन के लिए लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है और इससे प्रतिघंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है। इससे पर्यावरण दूषित होने का खतरा बना रहता है।

हमारे देश भारत में डिजिटल मुद्रा के संबंध में सरकार के प्रयासों की जानकारी

वित्त मंत्रालय ने देश में बिटकॉइन की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक अंतर अनुशासनात्मक समिति गठित की है, जो भारत में बिटकॉइन के भविष्य की दशा-

दिशा पर सुझाव देगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयकर विभाग ने देश के बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में टैक्स चोरी की संभावनाओं के मद्देनज़र सर्वे किए थे और इसके मद्देनजर सरकार द्वारा बिटकॉइन पर एक अन्य समिति का गठन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री बी ।पी। कानूनगो और सेबी के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी,वित्त मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति में शामिल हैं। हालांकि, इससे पहले मार्च 2017 में बिटकॉइन पर एक समिति बनाई गई थी, जो कोई ठोस सुझाव देने में असफल रही थी।

यदि हमारे देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वयं की डिजिटल मुद्रा जारी की जाती है तो सबसे पहले डबल स्पेंडिंग की समस्या से निपटना होगा। यद्यपि डबल स्पेंडिंग की समस्या से निपटने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी इसे हैक-प्रूफ बनाने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे ताकि इसको आसानी से कॉपी न किया जा सके।

यदि डिजिटल मुद्रा को एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के रूप में अधिकृत कर वैधानिकता प्रदान की गई तो इसके विनियमन का दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक को निभाना होगा। डिजिटल मुद्रा के लेन-देन से पूंजी लाभ और व्यापारिक लेन-देन पर टैक्स की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही, विदेशों में होने वाले भुगतान को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के दायरे में लाना होगा।

उपसंहार

उपर्युक्त सभी प्रकार की जटिलताओं और कठिनाइयों के बाद भी डिजिटल मुद्रा को अधिकृत रूप से जारी करने के लिए अनेक एहतियाती कदम उठाए जाने स्वाभाविक है क्योंकि इस डिजिटल मुद्रा के कारण कहीं ऐसा न हो कि इसके चलन से आतंक के वित्तपोषण, मनी लॉन्डिंग और कर चोरी जैसी भयावह परेशानियां उत्पन्न हो जाएं। इसलिए डिजिटल मुद्रा के संभावित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक नीतियां बनानी होंगी, जिन कुछ देशों ने डिजिटल मुद्रा जारी करने का प्रयास किया है उन्हें शीघ्र ही इस पर प्रतिबंध लगाने पड़े। इसका एक उदाहरण वेनेजुएला का सभी के सामने है, वेनेजुएला ने पेट्रो नामक क्रिप्टो करेंसी का प्रचालन आरंभ किया था, लेकिन हाल ही में वहां की संसद ने पैट्रो को अवैध घोषित कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कहा था कि वह एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के तहत केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योग क्षेत्र के हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए कुछ बयानों ने बिटकॉइन, ईथर और डॉगकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं के भविष्य के बारे में भी चिंता जताई है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण उदाहरणों से यह कहा जा सकता है कि डिजिटल मुद्रा का भविष्य प्रगतिशीत दिखाई देता है क्योंकि वर्तमान में इसका चलन दिनोंदिन बढ़ रहा है और हमारे देश की सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सहित विश्व के देशों के केन्द्रीय बैंक भी इस उद्देश्य हेतु एक सशक्त प्रणाली विकसित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लग रहे हैं।

(यह स्पष्ट किया जाता है कि **'डिजिटल मुद्रा का वर्तमान एवं भविष्य'** विषय पर लेखक ने इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी गहनतापूर्वक अध्ययन किया है तथा इससे सम्बंधित आवश्यक जानकारी को इस आलेख में शामिल किया गया है और साथ ही लेखक ने समाचार-पत्रों के अध्ययन से मिली जानकारी से इस आलेख को ज्ञानवर्द्धक एवं रुचिकर बनाने का संपूर्ण प्रयास किया है। पूरी कोशिश रही है कि इसे अन्यों के लिए लाभप्रद बनाया जा सके। यद्यपि इस आलेख का सही मूल्यांकन तो माननीय मूल्यांकनकर्ता ही कर सकेंगे तथापि लेखक ने इसे शब्दों की निर्धारित सीमा में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है)

*****

मिहिर जोषी

पदनाम:- अधिकारी

संस्था का नाम:- बैंक ऑफ़ इंडिया

मोबाइल नं. :- 9998217480

ई-मेल:- mihir.joshi17@gmail.com

डिजिटल मुद्रा क्या है?

डिजिटल मुद्रा, मुद्रा का एक रूप है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या साइबरकैश भी कहा जाता है। डिजिटल मुद्राएं ऐसी मुद्राएं हैं जो केवल कंप्यूटर या मोबाइल फोन से ही पहुंच योग्य होती हैं। इन मुद्राओं का उपयोग सामान खरीदने और सेवाओं के लिए भुगतान करने में किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा तत्काल लेनदेन में भी सहायक होती है।

डिजिटल मुद्रा की उत्पत्ति या इतिहास :

ई-गोल्ड व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पहला इंटरनेट पैसा था, जिसे 1996 में शुरू किया गया था और इसे "डिजिटल मुद्रा" नाम दिया गया था। 1997 में कोका-कोला ने मोबाइल भुगतान का उपयोग करके वेंडिंग मशीनों से खरीदारी की पेशकश की। पे पाल(PayPal) ने 1998 में अपनी यूएसडी-डिनोमिनेटेड सेवा शुरू की। "क्यू सिक्के या क्यूक्यू सिक्के", टेनसेंट क्यूक्यू के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रकार की कमोडिटी-आधारित डिजिटल मुद्रा के रूप में उपयोग किए गए थे और 2005 की शुरुआत में सामने आए। एक अन्य ज्ञात डिजिटल मुद्रा सेवा "लिबर्टी रिज़र्व" थी, जिसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को डॉलर या यूरो को लिबर्टी रिज़र्व डॉलर या यूरो में बदलने देता था और 1% शुल्क पर उन्हें एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमय करने देता था। वर्ष 2009 में बिटकॉइन लॉन्च किया गया जिससे विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल मुद्राओं की शुरुआत हुई और इस प्रकार यह व्यापक रूप से इस्तेमाल और स्वीकृत डिजिटल मुद्रा बन गया।

डिजिटल मुद्राओं के लक्षण :

- डिजिटल मुद्राओं को बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती है।

- डिजिटल मुद्रा लेन-देन की लागत को सस्ता कर सकते हैं।
- डिजिटल मुद्रा को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- डिजिटल मुद्रा की दरें स्थिर और विश्व स्तर पर स्वीकृत हैं।
- डिजिटल मुद्रा लेन-देन में केवल प्रेषक, प्राप्तकर्ता और बैंक शामिल हैं।
- डिजिटल मुद्रा को बैंक वॉलेट, बैंकिंग ऐप, डिजिटल कार्ड आदि की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड की आवश्यकता होती है।

डिजिटल मुद्राओं के प्रकार :

डिजिटल मुद्रा एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। मोटे तौर पर, तीन अलग-अलग प्रकार की मुद्राएं निम्नलिखित हैं:

1. क्रिप्टोकरेंसी :

क्रिप्टोकरेंसी ऐसी डिजिटल मुद्राएं हैं जो एक नेटवर्क में लेन-देन को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती हैं। क्रिप्टोग्राफ़ी का उपयोग ऐसी मुद्राओं के निर्माण को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। बिटकॉइन और एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी के उदाहरण हैं। अधिकार क्षेत्र के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित किया भी जा सकता है या नहीं भी।

2. आभासी मुद्राएं :

आभासी मुद्राएं, डेवलपर्स या प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों सहित किसी संस्थापक संगठन द्वारा नियंत्रित अनियमित डिजिटल मुद्राएं हैं। आभासी मुद्राओं को भी एक परिभाषित नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा एल्गोरिथम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। आभासी मुद्रा का एक उदाहरण गेमिंग नेटवर्क टोकन है।

3. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं :

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं (सीबीडीसी) किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई विनियमित डिजिटल मुद्राएं होती हैं। सीबीडीसी पारंपरिक फिएट (FIAT) मुद्रा का पूरक या प्रतिस्थापन हो सकता है। 2022 की बजट में केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) "डिजिटल रूपी" की शुरुआत की, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

डिजिटल मुद्रा से लाभ :

- डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्य किया जाएगा
- लेन-देन पर शुल्क कम होगी
- सरकार का नोटों को छापने के ऊपर खर्चा कम हो जाएगा
- कोई मुद्रास्फीति नहीं
- अपने ग्राहकों के साथ अधिक विश्वास
- अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए व्यापार करना आसान

डिजिटल मुद्रा से नुकसान:

- मूल्य बहुत जल्दी खो सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं।
- सुरक्षा का मसला
- विनियमन का अभाव
- अपराधियों के लिए अधिक सुलभ
- लोगों में डिजिटल साक्षरता का अभाव
- डिजिटल करेंसी के आने से देश के कई बैंकों को अपना मैन पावर कम करना पड़ सकता है।
- यदि ई-कैश (e-cash) लोकप्रिय हो जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक, मोबाइल वॉलेट में रखी जाने वाली राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है, तो इस स्थिति में कमजोर बैंक को अपने पास कम लागत वाली जमा राशि (Low-Cost Deposits) को बनाए रखने हेतु बड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में अन्य देशों की मौजूदा स्थिति:

कुछ देशों ने पहले ही किसी न किसी रूप में सीबीडीसी जारी कर रखा है। वर्ष 2020 में बहामास के केंद्रीय बैंक ने एक डिजिटल मुद्रा जारी की थी। दुनिया भर के अधिकतर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं की व्यवहार्यता, उपयोगिता और मूल्य पर विचार कर रहे हैं। चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सीबीडीसी का परीक्षण किया जा रहा है। स्वीडन में बैंक नोट मुद्रा आपूर्ति का महज 1% हैं फिर भी रिक्सबैंक (स्वीडिश सेंट्रल बैंक) द्वारा सीबीडीसी को अपनाने की कोई जल्दबाज़ी नहीं की जा रही है। पाँच वर्षों के मूल्यांकन के बाद भी स्वीडिश मौद्रिक प्राधिकरण ई-क्रोना (e-krona) जारी करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सका है। यू.एस. फ़ेडरल रिज़र्व विश्व की सबसे लोकप्रिय लेखा इकाई के रूप में डॉलर पर आधारित

निजी 'स्टेबलकॉइन्स' से प्रतिस्पर्द्धा हेतु आधिकारिक मुद्रा जारी करने के बारे में सार्वजनिक परामर्श कर रहा है। डिजिटल यूरो 24 माह लंबे टेस्ट से गुज़र रहा है। यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक वर्ष 2025 तक इसकी शुरुआत कर सकता है। जापान अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने में वर्ष 2026 तक का समय ले सकता है।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में भारत की मौजूदा स्थिति:

डिजिटल क्षेत्र में आज भारत किसी भी देश से कम नहीं है। 2015 वह साल था जब भारत ने पहली बार "डिजिटल इंडिया" अभियान की शुरुआत की थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले तब और अब के भारत में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। 2015 से लेकर 2022 तक के सफर में भारत ने डिजिटल प्लेटफार्म में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। शॉपिंग बिल भरने से लेकर व्यवसाय करने तक भारत डिजिटल बन चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत डिजिटल रूप से बहुत प्रगति कर चुका है। बहुत सारी योजनाएं जैसे भीम यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, आधार, जेम्स इत्यादि डिजिटल हो चुकी हैं। इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत के नागरिकों के कार्यों को काफी आसान कर दिया है। अब भारत बैंकिंग के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। यह बदलाव भारत की सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा को लाकर करना चाहती है।

डिजिटल मुद्रा को पूर्ण रूप से स्वीकार करने से पूर्व सावधानियां:

- बेहतर मूल्यांकन सहित कार्यान्वयन: काग़ज़ी मुद्रा के घटते उपयोग के साथ मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। हालांकि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण निर्णय का उचित रूप से क्रियान्वयन और मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाज़ी में किये गए क्रियान्वयन से लाभ की अपेक्षा अधिक हानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- केवाईसी के कड़े मानदंड: डिजिटल रुपया वरदान साबित हो सकता है। आवश्यकता है 'अपने ग्राहक को जानें' (Know Your Customer) संबंधी मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने की ताकि आतंकी वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुद्रा के दुरूपयोग को रोका जा सके।
- देश की केंद्रीय बैंक की भूमिका: केंद्रीय बैंक को अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखना होगा। डिजिटल मुद्रा के परिचालन हेतु ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी या किसी भी अन्य तरीके को गति, मापनीयता, लेखा परीक्षण, सुरक्षा और गोपनीयता जैसे परस्पर विरोधी लक्ष्यों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य :

दूसरे क्षेत्रों की तरह, भुगतान के क्षेत्र में भी तकनीकी नवाचारों ने सामाजिक व्यवहार में भारी बदलाव किया है। विशेष रूप से महामारी के समय उपभोक्ताओं ने संपर्क रहित भुगतान, डिजिटल वॉलेट और आभासी भुगतान समाधान जैसी सुविधाओं की मांग की। भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार, दिसंबर 2021 तक एक वर्ष की अवधि में देश भर में ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या यहां तक कि कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सामान्य भुगतान लेन-देन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार, 80 प्रतिशत केंद्रीय बैंक किसी न किसी तरह से सीबीडीसी के काम में लगे हुए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत पहले से ही प्रायोगिक चरण में हैं। डिजिटल मुद्रा वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सिबिलिटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी तथा यह सस्ता, आसान और निपटान में तीव्रता भी लाएगी। डिजिटल मुद्राएं व्यापार को बढ़ावा दे सकती हैं और देशों के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कई नए अवसर खोल सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारा भविष्य डिजिटल मुद्राओं में निहित है।

नोट : (मेरे द्वारा लिखित इस आलेख में उल्लिखित कुछ आंकड़े और सूचनाएं गुगल, इंटरनेट तथा विभिन्न स्रोतों से ली गयी हैं)

*****

रुमकी दत्ता

पदनाम:- सहायक निदेशक (रा.भा.)
संस्था का नाम:- भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला
मोबाइल नं. :- 9724051654
ई-मेल:- rumkee@prl.res.in

परिचय:

कोई भी मुद्रा, पैसा या पैसे जैसी संपत्ति जो मुख्य रूप से डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम पर, विशेष रूप से इंटरनेट या ई-माध्यमों पर प्रबंधित, संग्रहीत या एक्सचेंज की जाती है, उसे **डिजिटल करेंसी** (**डिजिटल मुद्रा** या **इलेक्ट्रॉनिक करेंसी**) के रूप में जाना जाता है. इसमें डिजिटल मुद्रा, आभासी मुद्रा और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा शामिल हैं। डिजिटल मुद्रा को इंटरनेट पर उपलब्ध डेटाबेस, किसी कंपनी या बैंक के स्वामित्व वाले केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेटाबेस, डिजिटल फ़ाइलों के भीतर या यहां तक कि एक संग्रहीत-मूल्य कार्ड पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।

विवरण: क्या है डिजिटल करेंसी?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा है । यह "ब्लॉकचैन और अन्य तकनीकों" पर आधारित है। डिजिटल रुपया किसी एनईएफटी, आईएमपीएस या डिजिटल वॉलेट की तरह है। इसका उपयोग थोक लेन-देन या खुदरा भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। यह प्रणाली मुख्यतः इसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है।

- ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो-करेंसी का संचालन होता है। यह एक डिजिटल 'सार्वजनिक बही खाता' है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन अथवा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज़ किया जाता है।
- ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन-देन को दर्ज कर लेने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों (मुख्यतः कंप्यूटर, जिन्हें नोड्स कहा जाता है) के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन-देन के विवरण को बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है।

क्या यह मुद्रा पारंपरिक रुपए की जगह लेगी?

डिजिटल करेंसी की गणना मुद्रा के रूप में की जाएगी। इससे सरकार को कम नोट छापने और नकली मुद्रा, काला धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह "अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली" तैयार करने में मदद करेगा। डिजिटल रुपए के ऑनलाइन लेन-देन हेतु मध्यस्थ के रूप में बैंक की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेषक और प्राप्तकर्ता ब्लॉकचेन का उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं और बैंक इसमें गारंटर होगा।

डिजिटल मुद्राएं पारंपरिक मुद्राओं के समान गुण प्रदर्शित करती हैं, लेकिन आम तौर पर मुद्रित बैंक नोटों या सिक्कों वाली मुद्राओं की तरह उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यह मुद्रा इंटरनेट पर तात्कालिक लेन-देन की अनुमति देती है तथा नोटों और सिक्कों के वितरण से जुड़ी लागत को कम करती है। इस प्रकार की मुद्राओं का उपयोग भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कुछ समुदायों तक सीमित भी हो सकता है जैसे कि ऑनलाइन गेम आदि में इसका उपयोग।

जहां मुद्रा आपूर्ति (उदाहरण के लिए, एक बैंक) पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय संस्था होती है वहां डिजिटल मुद्रा को केंद्रीकृत किया जा सकता है और जहां मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण पूर्व निर्धारित होता है या लोकतांत्रिक रूप से होता है वहां इसे विकेंद्रीकृत किया जा सकता है।

ई-गोल्ड व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पहला इंटरनेट पैसा था जिसे 1996 में पेश किया गया था और 2008 में अमेरिकी सरकार द्वारा इसे बंद करने से पहले यह कई मिलियन उपयोगकर्ताओं तक प्रसारित हुआ। ई-गोल्ड को अमेरिकी अधिकारियों और शिक्षाविदों दोनों द्वारा "डिजिटल मुद्रा" के रूप में संदर्भित किया गया है। 1997 में कोका-कोला ने मोबाइल भुगतान का उपयोग करके वेंडिंग मशीनों से खरीदारी की पेशकश की। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च किया गया था जिसने विकेन्द्रीकृत ब्लॉकचैन आधारित डिजिटल मुद्राओं की शुरुआत की। इसमें कोई केंद्रीय सर्वर नहीं था और कोई ठोस संपत्ति आरक्षित भी नहीं थी। डिजिटल मुद्रा के रूप में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्राएं सरकार द्वारा विनियमित करने के प्रयासों में प्रतिरोधी साबित हुईं, क्योंकि ऐसा कोई केंद्रीय संगठन या व्यक्ति नहीं था जिसके पास उन्हें संग्रहीत करने की शक्ति थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल, 2018 को जारी किये गए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र को रद्द करके देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस परिपत्र ने व्यापारियों और एक्सचेंजों की बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच को बाधित कर दिया था। व्यापार का संचालन करने में असमर्थ कई एक्सचेंज अन्य देशों में स्थानांतरित हो गए या उन्होंने यहाँ अपना कारोबार बंद कर दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से कुछ एक्सचेंज वापस आ गए हैं।

विदित है कि मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के ज़रिये वस्तुओं का लेन-देन किया करते थे, लेकिन जैसे-जैसे तकनीक उन्नत होती गई, व्यापार के तरीकों में भी बदलाव आता गया। आभासी मुद्रा का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक है, परंतु विकेंद्रीकृत प्रकृति और विनियमन की कमी, उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता और केंद्रीय प्राधिकरण की कमी, आभासी मुद्रा के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती है।

वर्तमान और भविष्य:

आज, लगभग 18,142 डिजिटल मुद्रा, 460 क्रिप्टो-एक्सचेंज हैं और डिजिटल मुद्रा का मार्केट कैप 117 ट्रिलियन डॉलर है। हर 24 घंटे में, $91 बिलियन मूल्य की क्रिप्टो का कारोबार होता है, जिसमें से अधिकांश बिटकॉइन या एथेरियम हैं।

उद्योग के आकार और विनियामक सख्ती को देखते हुए अब इस संदर्भ में विनियमन की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने लायक है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि विनियमन के लिए विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।

जैसे-जैसे पारंपरिक वित्तीय प्रणाली बढ़ते हुए क्रिप्टो तंत्र से जुड़ती है, बढ़ती इंटरकनेक्टिविटी असंगठित प्रसार प्रभावों संबंधी चिंताओं को जन्म देती है और इससे प्रणालीगत स्थिरता प्रभावित हो सकती है। कुछ समय तक डिजिटल मुद्रा को एक उपकरण के रूप में देखा जाता रहा है। अब यह व्यवस्था बहुत जटिल होती जा रही है। इस वर्ष की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने बिटकॉइन और एस. एंड पी. 500 के बीच संबंध का संकेत देते हुए डेटा जारी किया। इससे शेयर बाजार और डिजिटल मुद्रा के बीच निवेशकों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।

इस विश्लेषण के तुरंत बाद वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता संबंधी परिणामों की चेतावनी दी। हालाँकि, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के संबंध में मौजूद कई डेटा

गैप को देखते हुए एक व्यापक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन कुछ हद तक अभी भी संभावना से बाहर है।

इसके अलावा, डिजिटल मुद्रा हेतु अंतर्निहित तकनीक की प्रकृति ऐसी है कि यह किसी भी या मौजूदा वित्तीय मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना सीमा पार लेनदेन को सक्षम बनाती है।

टोकन, विकेंद्रीकृत वित्त, एनएफटी और विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन जैसे नए एप्लिकेशन और मॉडल पारंपरिक मॉडल को चुनौती देते हैं और यह रेखांकित करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में "मूल्य" क्या है और इस "मूल्य" का लेन-देन कैसे किया जा सकता है। इससे सीमा पार डेटा प्रवाह, बौद्धिक संपदा अधिकार और पूंजी नियंत्रण से संबंधित मौजूदा नियमों के बीच आपसी टकराव का खतरा है। यह कर-निर्धारण के माहौल में अस्पष्टता के साथ-साथ कई अन्य नीतिगत चिंताओं को भी जन्म दे सकता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए डिजिटल मुद्रा की अंतर्निहित प्रौद्योगिकी की विशिष्ट प्रकृति, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नियामक चर्चाओं और निर्णयों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन डिजिटल मुद्रा के अनुसार, डिजिटल मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समन्वित विनियमन नहीं है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय निकाय क्रिप्टो के उदय के लिए जोखिमों और उपयुक्त नीतिगत प्रतिक्रियाओं का आकलन करने पर कार्य कर रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों और विनियामकों की निगाहें इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले से ही टिकी हुई हैं। कई देशों ने अपनी मौद्रिक प्रणाली को स्थिर करना और नवप्रवर्तन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। उनके उद्देश्य जैसे उपभोक्ता की रक्षा करना ,अवैध वित्तपोषण को रोकना, बाजार की अखंडता की रक्षा करना और नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना व्यापक रूप से व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। हालाँकि उनके दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है।

भारत के कुछ न्यायालयों ने मौजूदा कानूनों में संशोधन किया है। एक अन्य दृष्टिकोण जो यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित प्रतीत होता है ,इस उद्योग से व्यापक तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह से नए विनियामक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नता अंतर क्षेत्रीय मध्यस्थता के अवसरों

की पेशकश करते हुए अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष:

वास्तव में वैश्विक समन्वित दृष्टिकोण के लिए सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं/प्रणालियों का लाभ उठाते हुए मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ-साथ इससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन और सामान्य मानकों को स्थापित करने की दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से समावेशी समाधान हेतु उपयुक्त मुद्रा विकसित करने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भी आवश्यकता है।

संदर्भ: समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित संबंधित खबरें।

*****

विधि चंद्रकांत जटनिया

पदनाम:- अधिकारी
संस्था का नाम:- केनरा बैंक
मोबाइल नं. :- 9428058126
ई-मेल:- vidhijataniya@canarabank.com

महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने हमेशा ही वित्त को महत्व दिया था।
"बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया"

पैसे का तो खेल ही निराला है। मनुष्य जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं है। उसमें भी बैंकिंग क्षेत्र हर मायनों में सेवा क्षेत्र से जुड़े होने, ग्राहकों से सीधे संपर्क में आने और अपने वित्तीय लक्ष्य के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भविष्य में भी रहेगा। आज हर तरफ रुपये यानि वित्त का बोलबाला है और कोई भी आम आदमी हो, संस्था हो, कंपनी हो या व्यापारी हो – अपनी धनराशि की सुरक्षा के लिए उसे बैंक में जमा करता है। बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे।

भुगतान के सुगम माध्यम के रूप में कौड़ियों, शंखो, सीपियों तथा कीमती पत्थरों आदि के प्रयोग से गुजरते हुए धातुओं के सिक्कों तक की यात्रा का अपना अलग ही इतिहास है। यह तलाश एक बार तो कागज की मुद्रा पर आकर रुक गयी। बहुत लंबे अरसे से कागज की मुद्रा ने अपना वर्चस्व बना रखा था। बैंकिंग के बढ़ते कदम और सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती पैठ के साथ ही नकदी के अलावा भी भुगतान के नए-नए तरीके विकसित हुए जिससे नकदी की जरूरत सीमित कर दी गई।

भुगतान के इन विभिन्न तरीकों में शामिल हैं – चेक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर चेक आदि। सूचना प्रौद्योगिकी से भुगतान की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जिस भुगतान के लिये लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता था या फिर बहुत समय लग जाता था, वह तुरंत, कहीं भी – कभी भी होने लगा।

जैसे "कर ली दुनिया मुठ्ठी में।"

भुगतान की बात करें तो मुद्रा के स्वरूप में समय-समय बदलाव आया है। आइए आज हम मुद्रा के नये स्वरूप 'डिजिटल मुद्रा के वर्तमान और भविष्य' पर दृष्टिपात करते हैं।

1980 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने सबसे पहले डिजिटल मुद्राओं पर अपनी बात रखी। अगर हम सही मायने में देखें तो श्री जैन स्टोर बिन जी को डिजिटल मुद्राओं का प्रणेता कह सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन के बाद अब बैंकिंग में भुगतान के क्षेत्र में क्रांति हो गई है और ऐसे में यदि हम केवल कुछ साल पीछे देखें और आज की बैंकिंग प्रणाली को देखें तो हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की वजह से भुगतान के लिए अब नकदी की जरूरत समाप्त ही हो गई है लेकिन भुगतान के लिए अगर मुद्रा की आवश्यकता पर नजर डालें तो आज भी आवश्यकता है क्योंकि भुगतान का तरीका चाहे भले ही बदल जाए, मुद्रा की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। मुद्रा का डिजिटल स्वरूप वैश्विक अर्थ तंत्र को एक नए आयाम पर ले जाएगा और इसका प्रभाव आम व्यक्ति के जीवन पर भी अवश्य ही होगा।

कूटमुद्रा

कूटमुद्रा या क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जो वर्चुअल मुद्रा भी है। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें कूट लेखन का प्रयोग किया जाता है। इसकी नकल करना बेहद मुश्किल काम है।

कूटमुद्रा को एक तरह से "ई-मुद्रा" भी कह सकते हैं। यह नोटों की तरह ही होती है, केवल कंप्यूटर पर दिखाई देती है। यह कूटमुद्रा हमारी जेब में नहीं आती, इसलिए इसे आभासी या अंकीय मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसके इस्तेमाल के लिये कूट-लेखन यानी क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसका प्रयोग केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है अत: इसे हम दुनिया के किसी भी कोने में अंतरित कर सकते है। इसे किसी भी प्रकार की करेंसी जैसे रुपया, डॉलर, येन, यूरो में परिवर्तित कर सकते हैं।

अगर देखा जाए तो कूटमुद्रा की स्वीकार्यता और महत्व अब बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अपनी कूटमुद्रा जारी करने, उसके विनिमयन तथा उपयोग की दिशा में सक्रियता दिखा रहे है।

कूट मुद्रा पर सरकार की निगरानी नहीं होती क्योंकि इस पर निगरानी पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा रखी जाती है।

पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटरों का समूह होता है, जिनमें से प्रत्येक कंप्यूटर उक्त समूह की सूचनाएं शेयर करने के केंद्र के रूप में काम करता है, प्रत्येक कंप्यूटर उसमें संगृहीत फाइलों के लिए सर्वर का काम करता है।

कूट मुद्रा को सृजित भी किया जा सकता है। आप कूट मुद्रा में लेन-देन करने वाले ट्रेडर से ऑनलाइन $1 के बदले 1 कूट मुद्रा खरीद सकते हैं जो आपका खाता खोलकर उसमें एक कोड मुद्रा के रूप में जमा कर देगा। अगर आप भुगतान के लिए इस कूट मुद्रा का प्रयोग करना चाहें तो कुछ शर्त पूरी कर अंतरित करा सकते हैं।

इस प्रकार कह सकते हैं कि 'बिटकॉइन' दुनिया की पहली कूट मुद्रा थी इसके बाद कई अन्य मुद्राएं प्रचलन में आयीं।

कूट मुद्रा में लेन-देन करने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रहता है। इसे इसकी एक विशेषता के रूप में ले सकते हैं, लेकिन यही विशेषता उस समय अवगुण के रूप में बदल जाती है जब इसे गलत तरीके/गलत उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है।

वैसे देखा जाए तो कूट मुद्रा में निवेश करना सुरक्षित होने के साथ फायदेमंद भी है। इसकी मांग और पूर्ति की स्थिति के साथ इसके मूल्यों में भी उसी तरह से उतार-चढ़ाव होते हैं जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में होते हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भी कूट मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देखें तो धीरे- धीरे विभिन्न वस्तुओं की खरीद-बिक्री में कूट मुद्रा का प्रयोग, स्वीकार्यता और इनका महत्व बढ़ रहा है।

विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक अपनी कूट मुद्रा जारी करने, उसके विनिमयन तथा उपयोग की दिशा में सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन कूट मुद्रा की कुछ सीमाएं है जो डिजिटल मुद्रा के भविष्य को निश्चित रूप से तय करेगी।

कूट मुद्रा का पूरा साम्राज्य कंप्यूटर पर टिका हुआ है। कंप्यूटर पर आधारित होना नुकसानदायक है। साथ ही इसमें सबसे बड़ा जोखिम हैकिंग का है। इसमें प्रूफ ऑफ़ वर्क का उपयोग होने की वजह से लेन-देन को सुरक्षित बनाने का पूरा प्रयास किया गया

है, फिर भी बेहतर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे कंप्यूटर के क्रैश होने पर भी सुरक्षित रखा जा सके और इसकी हैकिंग की संभावना भी न रहे।

यह सच है कि कूट मुद्रा स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, परंतु यह भी सच है कि इनकी संख्या अभी बहुत ही कम है। कूट मुद्रा का सामान्य प्रयोग तभी हो सकेगा जब इसे उपभोक्ताओं के बीच व्यापक स्वीकृति मिले। परंपरागत मुद्रा के सापेक्ष कूट मुद्रा की प्रक्रियागत जटिलता इसकी स्वीकार्यता में बाधा डाल रही है। जब तक लेन-देन की पूरी सुरक्षा के साथ ही प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया जाएगा तब तक उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल मुद्रा की स्वीकार्यता सीमित ही बनी रहेगी।

यदि डिजिटल मुद्रा को एक सही योजना के साथ स्वीकार किया जाए तो आने वाला दौर भारत देश को विकसित देश बनाने की दिशा में एक नया कदम स्थापित करेगा। कवि 'रामधारी सिंह दिनकर' ने बहुत खूब कहा है –

"है कौन विघ्न ऐसा जग में
टिक सके आदमी के मग में,
ख़म ठोक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पांव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है,
पत्थर पानी बन जाता है।"

इसमें कोई संदेह नहीं कि कूट मुद्रा ने धीरे-धीरे अपनी जड़ें जमा ली है। कई जगह पर भविष्य की मुद्रा के रूप में डिजिटल मुद्रा को ही देखा जा रहा है। यही कारण है कि कई देशों की सरकारें इस डिजिटल मुद्रा को गंभीरता से ले रही हैं।

"संकटों से डरना नहीं, संकट हमारी परीक्षा है
सुगम विजय प्राप्त होगी, संघर्ष की यदि इच्छा है।"

आने वाले समय में केंद्रीय बैंक के लिए डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करना आवश्यक हो जाएगा। इसके लिए कार्यान्वयन में सावधानी और बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है।

यहां मैं डॉ. कलाम के एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगी -

एक बार डॉ. कलाम के भाषण के बाद एक दस साल की बच्ची उनसे ऑटोग्राफ लेने आई। उन्होंने उससे पूछा, "तुम्हारी महत्वकांक्षा क्या है?"

बच्ची ने बिना एक क्षण रुके जवाब दिया, "मैं एक विकसित भारत में जीना चाहती हूं।"

यदि हमें विकसित भारत का सपना साकार करना है तो भारत को वित्तीय रूप से साक्षर देश बनाना ही होगा और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर आगे बढ़ते रहना होगा।

टू द टॉप नॉनस्टॉप
बिना रुके निर्बाध रूप से शिखर तक ॥
जय हिन्द
जय हिन्दी
जय भारत

*****

विलास वैष्णव

पदनाम:- मुख्य प्रबंधक (ऋण एवं एनपीए)
संस्था का नाम:- भारतीय स्टेट बैंक
मोबाइल नं. :- 7600036032
ई-मेल:- vilas.vaishnav@sbi.co.in

अपनी शाखा का काम खतम करके बैठा ही था की मेरा मित्र गणेश आ गया। बातों ही बातों में उसने बताया कि डिजिटल मुद्रा क्या है और उसका भविष्य क्या है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, अरे भाई आजकल का दौर यही हैं, डिजिटल मुद्रा। गणेश ने उत्सुकता के साथ पूछा भाई हमें भी इस विषय में कुछ जानकारी बताओ।

मैंने कहा, एक तरफ भारत एक डिजिटल भुगतान "नकदी विहीन" अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, वहीं पर दूसरी ओर पूरा विश्व डिजिटल मुद्रा को लेकर उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार कर रहा है।

डिजिटल क्षेत्र में हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने पहली बार 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन से डिजिटल क्षेत्र में अपनी शुरुआत की थी। तब से लेकर अभी तक हमने डिजिटल प्लेटफार्म में अपनी एक नयी और अलग पहचान बना ली है, चाहे वह शॉपिंग हो, बिल भरना हो या फिर बिजनेस के लिए लोन हो। इन सभी दिशाओं में हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इस पूरे सफर में भारत ने प्रगति के साथ-साथ बहुत सारे स्कीम डिजिटल किए हैं जैसे भीम यूपीआई, डीजी लॉकर, को-विन, आधार इत्यादि। इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे काम आसान हो गए हैं। हमारा देश बैंकिंग क्षेत्र में भी कुछ बदलाव लाने की तैयारी में है। हमारी सरकार यह बदलाव, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर डिजिटल मुद्रा को लेकर आने वाली है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये डिजिटल मुद्रा है क्या? और यह किस तरह हमारे देश के लोगों को लेन-देन के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान करेगी। चलिये आज हम डिजिटल करेंसी/ मुद्रा से जुड़ी सभी जानकारी जैसे उसके फायदे और नुकसान समझते हैं।

डिजिटल करेंसी/मुद्रा:

जब देश के नकदी रुपयों को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तब उसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। हाल ही में हमारे देश में क्रिप्टोकरेंसी का चलन बढ़ा है। यह एक प्रकार की आभासी मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी है। हम धीरे-धीरे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। यह **क्रिप्टोकरंसी** भी एक तरह से शेयर बाजार की तरह ही है। इसमें एक ही समय में शेयर मार्केट की तरह करेंसी की कीमतों पर भारी उछाल तथा गिरावट देखी जा सकती है । हमारे देश मे लोग डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के लिए खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

डिजिटल मुद्रा से आम जनता और बैंकिंग सैक्टर को एक सुनहरा मौका मिलेगा जिससे मुद्रा को लेकर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता हुआ नजर आएगा, जिससे बैंकों में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मिनटों में ही उनका पैसा अंतरित हो जाएगा या फिर वह कुछ ही मिनटों में अपना पैसा कहीं पर अंतरित कर सकेंगे।

डिजिटल करेंसी की तरफ आकर्षण का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस मुद्रा के जरिए पैसा लगाकर कम समय में अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी ही वैश्विक बाजार यानी वर्ल्ड मार्केट में आपसी देशों द्वारा आदान-प्रदान या आयात-निर्यात आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

विश्व बाजार में उत्पादों की खरीद फरोख्त में धांधली तथा भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी भी भुगतान के लिए एक अच्छा उपाय है। यहां एक कंप्यूटर द्वारा बनाई गई मुद्रा है जिसे ऑनलाइन माइनिंग के जरिए एकत्रित किया जाता है

"केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं" (सीबीडीसी) की अवधारणा कोई नयी बात नहीं है। कुछ लोग सीबीडीसी की उत्पत्ति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन को देते हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में सुझाव दिया था कि संयुक्त राज्य (यूएस) के फेडरल रिजर्व बैंक जनता को ऐसा 'माध्यम' उपलब्ध कराएं जिसमें जमा राशियों की सुविधा और मुद्रा की सुरक्षा हो। हालांकि, डिजिटल मुद्रा की अवधारणा पर केंद्रीय बैंकों, अर्थशास्त्रियों और सरकारों द्वारा व्यापक चर्चा पिछले दशक में ही जाकर की गई है।

डिजिटल मुद्रा के प्रकार:

डिजिटल मुद्रा के तीन प्रकार हो सकते हैं जैसे:

1. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
2. वर्चुअल करेंसी
3. क्रिप्टो करेंसी

डिजिटल मुद्रा का उपयोग: माना जा रहा है कि हमारे देश में लाई जाने वाली डिजिटल मुद्रा दुनियाभर में प्रचलित क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की तरह ही उपयोग की जाएगी। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि डिजिटल मुद्रा सरकारी करेंसी होगी। इस पर सरकारी यानी कानून का मोहर होगा। डिजिटल मुद्रा को कैसे उपयोग करें, इसकी गाइडलाइंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भविष्य मे जारी की जाएगी। डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल किया जाएगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक जारी करेगी।

डिजिटल मुद्रा और विदेश परिदृश्य:

पूरे विश्व में 86% सेंट्रल बैंक ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन की बैंक, चाइना की बैंक, अमेरिका की बैंक, जो अपने कन्वेंशनल पैसों को बदलना चाह रही हैं यानी उन्हें बदलकर इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल बनाना चाह रही हैं। इस विषय पर कितने प्रतिशत देश चर्चा कर रहे हैं और इस पर काफी खोजबीन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व में अब तक 14% सेंट्रल बैंकों ने तो पायलट प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिये हैं। उन देशों के सेंट्रल बैंकों ने डिजिटल करेंसी पर अपना काम करना शुरू भी कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक और डिजिटल मुद्रा:

कुछ समय पहले भारत की वित्त मंत्री के नेतृत्व में भारतीय रिज़र्व बैंक की बैठक हुई जिसमें डिजिटल करेंसी के ऊपर चर्चा की गई थी। चर्चा में भारत सरकार ने सेंट्रल बैंक से डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने की बात रखी। वित्त मंत्री ने सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी लाने का सुझाव दिया जिससे लोग पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें। भारतीयों का क्रिप्टो करेंसी की तरफ झुकाव को लेकर सरकार ने यह तय किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक एक ऐसा तरीका लेकर आए जिससे कि भारत के लोग अपने पैसों को डिजिटली इस्तेमाल कर सकें और डिजिटल तरीके से कमा सकें। एक ऐसा तरीका जिससे लोगों का समय भी बचे और उनका पैसा सलामत भी रहे और साथ ही साथ यह देश डिजिटल उपकरणों को लेकर स्मार्ट बनें।

डिजिटल मुद्रा और उसकी विशेषताएं:-

- डिजिटल मुद्रा में लेन-देन के लिए बैंक या किसी अन्य बिचौलिये की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन-देन किया जा सकता है।
- डिजिटल मुद्रा में व्यापार के लिये किसी भी प्रकार के प्रपत्र (पहचान-पत्र आदि) की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकता है।
- डिजिटल मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है, किसी प्रपत्र की अनिवार्यता के अभाव में लेन-देन के दौरान लोगों की निजी-जानकारी सुरक्षित रहती है।
- डिजिटल मुद्रा का उपयोग बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिये विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा के रूप में किसी भी देश द्वारा वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है। डिजिटल करेंसी को देश की सरकार द्वारा मान्य किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी को देश के केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट में शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को नगदी रुपयों पर निर्भर होने से छुटकारा मिलेगा। लोगों को अकसर नगदी रुपयों को रखने में और इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। कभी-कभी वे सही समय पर नकदी रुपयों को निकाल या जमा भी नहीं करा सकते हैं। इसलिए इस मुद्रा के आने से लोगों को नकदी रुपए पर निर्भर होने से छुटकारा मिल सकेगा।
- डिजिटल करेंसी को रिटेल/ होलसेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने का भी विचार किया जा रहा है।
- रुपयों को प्रिंट कराने में जितना पैसा सरकार का लग जाता है, उसमें भी कमी आएगी।
- यह पैसा जमा कराने और निकलवाने के तरीके को काफी आसान कर देगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और पैसा भी इलेक्ट्रॉनिक होगा तो लोगों को काफी समय तक लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पैसों को स्टोर कर सकेंगे।
- डिजिटल करेंसी से लोगों को अपने पैसे को लेकर सुरक्षा महसूस होगी और उनके पैसे ज्यादा सिक्योर रहेंगे।

- डिजिटल मुद्रा के आने से लोगों को अपने देश के बाहर या फिर देश में ही पैसे अंतरित करने के लिए या फिर जमा करने के लिए अलग-अलग समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिससे बैंकिंग फ्रॉड जैसे कामों में भी कमी आएगी।

डिजिटल करेंसी का भविष्य:

- न्यायालय के आदेश के बाद देश में तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों, संबंधित नियामकों और अन्य हितधारकों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर विचार-विमर्श की पहल को बढ़ावा मिलेगा।
- हालांकि देश में क्रिप्टोकरेंसी की अनुमति देने और इसके विनियम हेतु नीति निर्माण में सरकार की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होगी। ध्यातव्य है कि जुलाई 2019 में प्रस्तुत क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2019 के मसौदे में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी।
- क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा करते हुए इसके दो पहलुओं-'निजी क्षेत्र द्वारा जारी मुद्रा (Private Currency)' तथा इसमें उपयोग की जाने वाली तकनीकी 'ब्लॉकचेन' और विकेंद्रीकृत बही-खता तकनीकी (Distributed Ledger Technology-DLT) जैसे पक्षों को अलग-अलग समझना बहुत ही आवश्यक है।
- क्रिप्टोकरेंसी के अध्ययन के लिये गठित समिति ने जहां किसी प्राइवेट करेंसी का विरोध किया है, वहीं समिति ने RBI तथा सरकार को 'ब्लॉकचेन' व DLT के प्रति सकारात्मक रवैया रखने तथा भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।
- उदाहरण के लिये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल आदि) में सरकार के विभिन्न विभागों में सुरक्षित रूप से आंकड़ों (Data) को एकत्र एवं संरक्षित रखने के लिये 'ब्लॉकचेन' पर कई प्रयोग किये जा रहे हैं तथा 'ब्लॉकचेन' में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिये केरल ब्लॉकचेन अकादमी (Kerala Blockchain Academy) की स्थापना जैसे प्रयास किये जा रहे हैं।

यद्यपि क्रिप्टोकरेंसी व्यापार, निवेश, तकनीकी और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ और कम खर्च वाली भविष्य की विनिमय प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करती है। परंतु वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में अनेक समस्याओं (जैसे-गोपनीयता, मूल्य अस्थिरता और इसके विनियमन की किसी नीति का अभाव) को देखते हुए देश में किसी निजी मुद्रा (Private Currency) को अनुमति देना एक बड़ी चुनौती होगी।

अतः भविष्य की जरूरतों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में सरकार, डिजिटल मुद्रा के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय, को बढ़ाया जाए जिससे इस क्षेत्र के बारे में जन-जागरूकता को बढ़ाया जा सके। साथ ही भविष्य की जरूरतों को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन के लिये एक मजबूत एवं पारदर्शी तंत्र का विकास किया जा सके।

आने वाले समय में डिजिटल करेंसी को भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2022-2023 डिजिटल करेंसी के आगमन का समय बताया जा रहा है। यदि भारत सरकार के डिजिटल करेंसी लॉन्च का फैसला अच्छा साबित हुआ तो यह भारत के डिजिटल क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिए सही साबित हो सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यह भारत के लोगों और सरकार को स्मार्ट नागरिक बनने की ओर जागरूक करता हुआ दिख रहा है। यह भारत की करेंसी को एक सस्ते और कुशल करंसी सिस्टम की ओर ले जाता हुआ साबित हो सकता है।

*****

विवेक गुप्ता

पदनाम:- मुख्य प्रबंधक (बीआईएस)
संस्था का नाम:- गेल (इंडिया) लिमिटेड, वडोदरा
मोबाइल नं. :- 9873077987
ई-मेल:- vivek.gupta@gail.co.in

हर देश की अपनी अधिकृत कागज़ी मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सउदी अरब के पास रियाल, रूस के पास रूबल है। संक्षेप में मुद्रा एक ऐसी धन-प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो और वहां के लोग इसके इस्तेमाल से जरूरी चीजें खरीद सकते हों यानी जिसकी कोई वैल्यू हो, मुद्रा कहलाती है।

आज इस दुनिया में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ऐसे में मुद्रा का भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। डिजिटल मुद्रा का अर्थ है मुद्रा का वो रूप जिसे आप छू तो नहीं सकते, लेकिन रख सकते हैं। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है।

डिजिटल मुद्रा का वर्तमान

वर्तमान में डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेंसी के रूप में उपलब्ध है। बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन कुछ प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी के नाम हैं। एक अनुमान के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत 2009 में हुई। पिछले कुछ सालों से क्रिप्टोकरेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारिक एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है। क्रिप्टोकरेंसी इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती हैं। इसे एक डिसेंट्रेलाइज्ड सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। क्रिप्टोकरेंसी में हुए लेन देन को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है। जिन लोगों या एजेंसीज द्वारा यह माइनिंग की जाती है, उन्हें माइनर्स कहा जाता है।

वह जगह जहां क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-फरोख्त और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या डिजिटल करेंसी एक्सचेंज या क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से जाना जाता है।

वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार का पूंजीकरण 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

मुद्रा का नियंत्रण देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। किन्तु क्रिप्टोकरेंसी पर किसी देश का नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकारें इसे शक़ की निगाहों से देखती हैं और इसे पारंपरिक करेंसी के लिए खतरा मानती हैं। सरकार को क्रिप्टोकरेंसी में मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल लगता है क्योंकि सभी लेनदेन एन्क्रिप्टेड होते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए विश्व के सभी प्रमुख देशों ने अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने की योजना बनाई है। इसे CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) का नाम दिया गया है। यह डिजिटल मुद्रा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत होगी और पारंपरिक मुद्रा की तरह इसका संचालन केंद्रीय बैंक की देख रेख में होगा।

विश्व के प्रमुख देशों की डिजिटल मुद्रा की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:-

भारत

भारत सरकार ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2022-23 में एक "डिजिटल रुपया" पेश किया जाएगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2022 में घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसका समर्थन करेगा। वर्तमान में, यह विकास की स्थिति में है।

वित्त मंत्री के अनुसार, CBDC भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, देश की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की दक्षता और कम खर्च को बढ़ाएगा, और एक स्थिर, विनियमित डिजिटल मुद्रा प्रदान करेगा जो निजी क्रिप्टोकरेंसी के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी।

नाइजीरिया

अक्टूबर 2021 में, नाइजीरिया CBDC की स्थापना करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। eNaira को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है और इसका उपयोग इन-स्टोर संपर्क रहित भुगतान के साथ-साथ धन हस्तांतरण के लिए भी किया जा सकता है।

रूस

फरवरी 2022 में, रूस के केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ रूस ने घोषणा की कि उसने CBDC के प्रारंभिक परीक्षण पूरे कर लिए हैं, जिसे "डिजिटल रूबल" के रूप में भी जाना जाता है।

चीन

अप्रैल 2020 में चीन डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसे ई-सीएनवाई या डिजिटल युआन 2022 के नाम से जाना जाता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की योजना है कि चीनी डिजिटल मुद्रा 2022 तक चीन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाए।

कनाडा

बैंक ऑफ़ कनाडा के पास अभी भी अपने CBDC के लॉन्च के लिए कोई ठोस समयरेखा नहीं है। यह विकास की स्थिति में है।

अमेरिका

यहां सीबीडीसी अनुसंधान की स्थिति में है। मार्च 2022 में, जो बिडेन प्रशासन ने डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

डिजिटल मुद्रा का भविष्य

डिजिटल मुद्रा भविष्य की मुद्रा है। कागज़ी मुद्रा से सम्बंधित समस्याओं को देखते हुए और डिजिटलाइजेशन के दौर में डिजिटल मुद्रा का भविष्य बहुत उत्साहजनक है।

कागज़ी मुद्रा से सम्बंधित समस्याएं निम्नलिखित हैं:-

- मुद्रा की छपाई और इससे सम्बंधित ढांचे का रखरखाव।
- समय के साथ नोटों का खराब होना और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से बदलने की जटिल प्रक्रिया।
- जाली करेंसी का लगातार भय बना रहता है।

- करेंसी के आवागमन के दौरान सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है जिससे परिचालनगत व्यय बढ़ता है।
- नोटों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बैंकों/एटीएम की स्थापना की निरंतर आवश्यकता।
- नोटों की छपाई के लिए महंगे पेपर का इस्तेमाल होता है और कई बार नोट की कीमत से ज्यादा व्यय उसकी छपाई पर हो जाता है।

डिजिटल मुद्रा के आने पर उपर्लिखित समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मुद्रा की कोई छपाई नहीं होगी और न ही मुद्रा का भौतिक आवागमन होगा। डिजिटल मुद्रा का लेन-देन ऑनलाइन सिक्योर्ड नेटवर्क के द्वारा होगा। डिजिटल मुद्रा का उत्पादन ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा किया जाएगा। लोगों को कागज़ी नोट की बजाए उतनी कीमत का कोड रखना होगा। यह कोड मोबाइल या किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण में रखा जा सकेगा। डिजिटल मुद्रा का लेन-देन केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत सिस्टम के जरिए होगा।

हालांकि, डिजिटल मुद्रा के आने पर निम्नलिखित समस्याएं होने की संभावना है:

- डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से सॉफ्टवेर पर निर्भर है। इसको हैकरस या साइबर अटैक से सुरक्षित रखना एक चुनौती से कम नहीं होगा।
- डिजिटल मुद्रा का लेन-देन ऑनलाइन नेटवर्क के द्वारा होगा। भारत जैसे विविध भौगोलिक देश के लिए सब जगह तीव्र नेटवर्क प्रदान करना एक समस्या है।
- डिजिटल मुद्रा के संचालन के लिए बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी परिवर्तन करना होगा। नए सिस्टम्स के बारे में विविध जानकारी के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- दीर्घ काल से कागज़ी मुद्रा का चलन है और लोग उसके उपयोग के साथ काफी सहज हो गए हैं। कागजी मुद्रा से डिजिटल मुद्रा में स्विच करना एक व्यवहारिक चैलेंज होगा।
- डिजिटल मुद्रा को अंतर्राष्टीय स्तर आम सहमति, विदेशी मुद्रा विनिमय सहमति आदि विषयों पर गहन विचार विमर्श करना होगा तथा मौजूदा प्रचलित नियमों में बदलाव करना होगा। यह बदलाव करने में बहुत समय लगेगा।

*****

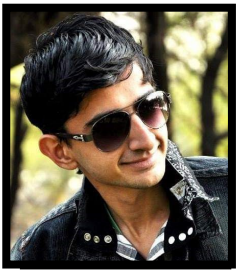

विवेक चंद्रकांत जटनिया

पदनाम:- सहायक
संस्था का नाम:- न्यू इंडिया एस्योरंस लिमिटेड
मोबाइल नं. :- 7990429539
ई-मेल:- vivek.jataniya@newindia.co.in

विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों ने कह दिया चकित जहां,
घर-घर उर्मिया जागी मुश्किलें हुई आसान।

हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक जमाना था जब सिक्के और नोट नहीं थे, आदान -प्रदान का प्रचलन हुआ करता था। आपको अगर सब्जी चाहिए थी तो बदले में इतना गेहूं दे दो, आपको नमक चाहिए तो बदले में इतनी सब्जी दे दो। आदान-प्रदान से ही कारोबार चलता था। धीरे-धीरे मुद्रा का चलन आरंभ हुआ, उसके पश्चात सिक्के और नोट छपने लगे। लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी आधारित नकदी रहित व्यवस्था द्वारा हम धन प्रेषित कर सकते हैं, धन मांगने का अनुरोध कर सकते हैं, वस्तु की खरीद कर सकते हैं, बिल भी चुका सकते है। इस प्रकार के लेन-देन में कभी जेब कटने का तो सवाल ही नहीं उठेगा।

प्रधानमंत्री ने मई 2016 में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों से नकदी रहित लेनदेन को अपनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यदि हम नकदी-रहित लेनदेन करना सीख लेते हैं और उसके अनुकूल बन जाते हैं तो हमें नोटों की जरूरत नहीं होगी। व्यवसाय स्वचालित हो जाएंगे जिसके परिणाम स्वरूप पारदर्शिता आएगी। गलत तरीके से लेन-देन बंद हो जाएगा जिससे काले धन का प्रभाव कम होगा। इसलिए मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि हमें कम से कम शुरुआत तो करनी चाहिए। एक बार हमने शुरू किया तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ते जाएंगे। बीस साल पहले किसने सोचा होगा कि हमारे हाथों में इतने सारे मोबाइल होंगे। धीरे-धीरे हमने आदत डाली और अब हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। शायद यह नकदी रहित समाज भी ऐसा ही बन जाए। यह जितनी जल्दी होगा, उतना ही देश बेहतर होगा।

कहा जाता है –

"आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।"

आधुनिक इंटरनेट युग में लेनदेन की प्रक्रिया में भी आधुनिक होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। जैसे मोबाइल फोन में हमने बहुत ज्यादा प्रगति की है, एक ऐसा वक्त था जब किसी को फोन करना हो तो आपको पहले से बताना पड़ता था कि इस व्यक्ति को फोन करना है और बहुत वक्त के बाद आपकी बारी आती थी और आप बात कर सकते थे लेकिन उस दौर से आज हम ना सिर्फ फोन कॉल बल्कि वीडियो कॉल तक पूरे विश्व में कहीं पर भी कर सकते हैं। इसी तरह वित्तीय प्रणाली में करेंसी नोटों की जगह डिजिटल मुद्रा अपने आप में एक बहुत कमाल का कदम है।

सरकार ने नकदी या कैशलेस होने के बहुत से फायदे पहले भी बताए और विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस होने की प्रक्रिया में गति आ गई है। विमुद्रीकरण से काले धन पर अंकुश लगने की पूरी संभावनाएं भी है। कैशलेस होने से अर्थव्यवस्था में तेजी तो आएगी, परंतु उस तेजी के लिए भारत को बहुत इंतजार करना है, कैशलेस होने के लिए बहुत सी समस्याएं भी है, उनसे भी निपटना होगा और हर उस वर्ग को साथ लेकर चलना होगा जो केवल कैश पर ही भरोसा करता है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर चलाए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक शाखा व सरकारी तंत्र को डिजिटल माध्यमों का प्रचार-प्रसार करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए है।

आधुनिक वित्तीय प्रणाली में करेंसी नोटों के अलावा कागज के अन्य भी बहुत सारे उपयोग है जिसमें बांड लेनदेन पत्राचार संचार प्रतिभूतियों का रूप हो लेकिन अब कहे तो तत्सबंधी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ले चुके हैं। साक्ष्य की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का प्रमाण कभी नहीं हो सकता। अपुष्ट साक्ष्यों की अगर माने तो आधुनिक समय में भौतिक नकदी का उपयोग दिन-ब-दिन गिर रहा है और इसमें भी कोविड-19 महामारी की वजह से यहां गिरावट और भी ज्यादा मजबूत हुई है। कोविड -19 जैसी महामारी के कारण कई केंद्रीय बैंकों और विश्व के बहुत सारे देशों की सरकारों ने मुद्रा के डिजिटल संस्करण की खोज करना शुरू कर दिया है ।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद अब बैंकिंग में भुगतान के क्षेत्र में क्रांति हो गई है और केवल 10 साल पीछे देखें और आज की बैंकिंग प्रणाली को अगर देखें तो हम

इसे आसानी से समझ पाएंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की वजह से भुगतान के लिए अब नकदी की जरूरत मानो समाप्त ही हो गई है लेकिन भुगतान के लिए अगर मुद्रा की आवश्यकता पर नजर डालें तो वहां कभी कम नहीं हो सकती।

कूट मुद्रा आज के तौर पर एक डिजीटल मुद्रा है। कूट मुद्रा को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है :

कूट मुद्रा एक ऐसी अंकीय मुद्रा है जिसमें मुद्रा की काया उत्पन्न करने को विनियमित करने के लिए कूट रचित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है इसे केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना परिचालित किया जाता है।

कूट मुद्रा कल्पित मुद्रा है जिसे कोड देकर सूचित किया जाता है तो कूट मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम से किया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह देश की मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है।

अगर बात करें डिजिटल मुद्रा की तो डिजिटल मुद्रा के आने से जो सबसे बड़ी परेशानी होगी वह है "पियर टू पियर" इंटरनेट प्रोटोकॉल। पियर टू पियर कंप्यूटरों का एक समूह होता है जिनमें से प्रत्येक कंप्यूटर उक्त समूह के भीतर फाइल इसे शेयर करने के केंद्र के रूप में काम करता है। जब एक पियर टू पियर नेटवर्क इंटरनेट के जरिए स्थापित किया जाता है तब वहां सारी फाइलों का इंडेक्स बनाने के लिए एक केंद्रीय सरवर का उपयोग किया जा सकता है और नेटवर्क के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के बीच फाइलों की शेयरिंग विभाजित होती है। क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहां जाता है।

प्रख्यात अर्थशास्त्री जूलियन साइमन ने 'अंतिम संसाधन' नामक अपनी पुस्तक में सही कहा है कि

'सूझ-बुझ वाले मानव ही सबसे बड़ी सम्पदा है।'

डिजिटल मुद्रा : पैसे का भविष्य

अभौतिक या वर्चुअल मुद्राओं का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निजी मुद्राओं के हानिकारक आर्थिक और सामाजिक परिणामों से बचा जा सकता है। यहां कहना बिल्कुल ही ठीक होगा की "डिजिटल मुद्रा ही पैसे का भविष्य है। "एक बार यहां वास्तविक तौर पर लोगों तक पहुंचा दिया गया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारत

देश में कोई भी निजी मुद्राओं से व्यवहार करना पसंद करेगा। डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से व्यवहार करना अत्यंत ही सरल है।

1980 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन सबसे पहले डिजिटल मुद्राओं पर अपनी बात रखी है। इसीलिए अगर सही मायनों में देखें तो हम श्री जैन स्टोर बिन जी को डिजिटल मुद्राओं का प्रणेता कह सकते है। उन्होंने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था कि फेडरल रिज़र्व बैंक जनता को कोई ऐसा माध्यम दे जिसमें जमा राशियों की सुविधा और रखी गई मुद्रा की सुरक्षा भी मौजूद हो।

चुनौतियां:

डिजिटल मुद्रा के अपने फायदे हो और यह भी सच है कि इससे लेनदेन की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी लेकिन इसी के साथ उसे अपनाने पर चुनौतियां भी स्वीकार करनी होगी। निजी मुद्राओं में भी गलत नकदी को रोकना बहुत मुश्किल है तो फिर डिजिटल मुद्रा आने पर फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं। निजी धन भी छुपाया जा सकता है और टैक्स ना भरा हो ऐसा धन भी बहुत बड़े मात्रा में उपस्थित है। मुद्रा के डिजिटल होने से यह परेशानी और भी बढ़ सकती है। लेकिन चुनौतियों से डरकर होने वाले फायदे को नकारा नहीं जा सकता। डिजिटल मुद्रा के सफल होने के लिए एक सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।

आने वाला दौर :

आने वाले वक्त में केंद्रीय बैंक को डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करना आवश्यक हो जाएगा। इसके कार्यान्वयन में सावधानी और बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक सही योजना के साथ अगर डिजिटल मुद्रा को स्वीकार किया जा सके तो आने वाला दौर भारत देश को विकास की ओर ले जाने की तरफ एक नया कदम स्थापित करेगा।

भारत विमुद्रीकरण के पश्चात तीव्र गति से नकद आधारित समाज से नकदी-रहित समाज की ओर बढ़ रहा है। यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब हमारा देश पुरानी आदतों को छोड़ रहा है और नए माध्यमों को तीव्र गति से अपना रहा है, जो वास्तविक रूप में आधुनिक युग में प्रवेश दिलाएगा। कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने के

बाद हम भी अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में आ जाएंगे। यह इतनी जल्दी संभव नहीं है, इसके लिए हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे ही सही हमें इसका लाभ दिखाई देने लगेगा। हमारी विकासशील कही जाने वाली अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में भी इस डिजिटल मुद्रा की अहम् भूमिका होगी। यही संभावना नजर आ रही है कि वह दिन दूर नहीं जब विमुद्रीकरण, भारत की भावी अर्थव्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध होगा, हम भी डिजिटल मुद्रा से ही व्यवहार करेंगे।

ऐसे में आइन्स्टाइन का कथन याद हो आता है-

"हर कठिनाई में अवसर निहित होता है, तलाशना मात्र होता है।"

*****

शक्तिवीर सिंह

पदनाम:- मुख्य प्रबंधक एवं संकाय
संस्था का नाम:- बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मोबाइल नं. :- 9739817000
ई-मेल:- shaktivir.singh@bankofbaroda.co.in

परिचय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए प्रत्येक समाज की एक सामाजिक व्यवस्था होती है. सामाजिक व्यवस्था में जीवनयापन हेतु कई प्रणाली एवं चरण हैं, इन्हीं चरणों में एक महत्वपूर्ण चरण है लेन–देन, मानव सभ्यता के आरंभ से ही किसी न किसी प्रकार का लेन-देन मानवता के लिए मूलभूत आवश्यकता रही है चाहे वो वस्तु विनियमय (Barter system) हो या वर्तमान में भारत की मुद्रा "रुपया" हो। भारत में ऐतिहासिक तौर पर रुपया चाँदी पर आधारित मुद्रा थी। भारत की बात की जाए तो भारत विश्व कि उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का प्रचलन लगभग छठी सदी ईसापूर्व में शुरू हुआ। "रुपए" शब्द का अर्थ शब्द रूपा से जोड़ा जा सकता है जिसका अर्थ होता है चाँदी। संस्कृत में रूप्यकम् का अर्थ है चाँदी का सिक्का, रुपया शब्द सन 1540 - 1545 के बीच शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किए गए चाँदी के सिक्कों लिए उपयोग में लाया गया, जो मूल रुपया चाँदी का सिक्का होता था। मुद्रा की यात्रा सुदीर्घ परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, Punched सिक्कों से लेकर वर्तमान में चमक बिखेरते सिक्के बाज़ार में नए आकार में ढल कर मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

कलरव कूजित युग में जहां प्रत्येक उपकरण, वस्तु तकनीक आधारित हो गयी है, आँख खोलते ही मोबाइल देखना दैनिक क्रियाओं हेतु विद्युत उपकरणों का प्रयोग हमें तकनीकी युग में तकनीक के जाल में फंसे हुए हैं और वास्तविकता भी यही है कि मानव सभ्यता अब इसकी आदी हो चुकी है। ऐसे में "मुद्रा" को भी तकनीक से अभिभूत होने से कब तक रोका जा सकता था। कागज और सिक्कों से निकलकर मुद्रा अब "डिजिटल मुद्रा" के रूप में लेन-देन का महत्वपूर्ण साधन बन रही है।

कोरोना महामारी के कारण जहां पूरे विश्व में जीवन की अपूरणीय क्षति हुई वहीं यदि इसके सकारात्मक पहलू पर नजर डाली जाए तो हम पाते हैं कि विगत दो-ढाई वर्षों में तकनीक के माध्यम से तकनीक से भागने वाले व्यक्ति भी तकनीक के काफी करीब पहुंच गए हैं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि "आवश्यकता आविष्कार की जननी है" वैश्विक महामारी के समय जब समूचा विश्व अपने घरों में कैद था तो तकनीक के माध्यम से सभी आभासी रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े भी थे और इसी दौर में "डिजिटल मुद्रा" ने पूरे विश्व में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज की बल्कि लेन-देन का प्रमुख साधन भी बनी। भारतीय परिपेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सदा से ही डिजिटल साधनों के प्रयोग के पैरोकार रहें हैं उनके नेतृत्व में डिजिटल क्रांति में छोटे स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति देखी गयी है। आज रेहड़ी पटरी वाले भी क्यू आर कोड के माध्यम से डिजिटल मुद्रा को स्वीकार रहे हैं , डिजिटल क्रांति का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है।

भारत युवाओं का देश हैं। देश की औसत आयु 30 वर्ष से कम है, नई पीढ़ी विशेषकर युवा डिजिटल मुद्रा की ओर सबसे ज्यादा अग्रसर है। डिजिटल मुद्रा केवल एक दशक से बाज़ार में उपलब्ध है, किन्तु आरंभ में इसकी ओर रुझान नहीं था अब लोग इसकी ओर न केवल आकर्षित हुए हैं बल्कि इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने बजट 2022-23 में घोषणा की है कि केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2022-23 के आरंभ में एक डिजिटल मुद्रा जारी की जाएगी। यह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है जिसके विषय में विश्व की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ जल्दबाज़ी में कोई भी निर्णय लेने से बचती रही हैं। डिजिटल रुपए (Digital Rupee) के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भारत की वैध मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। हालाँकि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency- CBDC) को जल्दबाज़ी में अपनाने के संबद्ध में जोखिमों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। बीते एक दशक में एथरियम और बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं या क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता ने विश्व भर के अधिकांश केंद्रीय बैंकों को उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने पर गंभीरता से विचार करने के लिये मजबूर कर दिया है, जो कि कैशलेस समाज के लक्ष्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा की कमियों को दूर करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। इस संदर्भ में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) ने यूरोपीय संघ के लिये 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC) यानी केंद्र बैंक द्वारा

जारी डिजिटल मुद्रा के मूल्यांकन का इरादा व्यक्त किया है। वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन-देनों को सुविधा न प्रदान करने का निर्देश दिया था।

भारतीय मुद्रा

भारत की आधिकारिक मुद्रा का नियंत्रक भारतीय रिज़र्व बैंक है। नोटों पर रिज़र्व बैंक का वादा दर्ज होता है कि वह धारक को एक तय रकम अदा करने का वचन देता है। इस वचन को पूरा न करने का मौका अभी तक इतिहास में कभी नहीं आया कि लोगों ने रिजर्व बैंक के दफ्तर के बाहर लाइन लगा दी हो कि रिज़र्व बैंक अपने वादे को पूरा करे। रिज़र्व बैंक ने वादा किया, इतने भर से मान लिया जाता है कि यह आधिकारिक मुद्रा है। यानी भारत में आधिकारिक मुद्रा को जारी करने वाला एक ही संगठन है- भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक अब तक इस मुद्रा को भौतिक स्वरूप में ही जारी करता रहा है। डिजिटल स्वरूप में जारी मुद्रा भौतिक तौर पर जारी न होगी, यानी यह डिजिटल मोड में ही होगी। इसे छुआ ना जा सकेगा, न ही इसके नोट या सिक्के होंगे पर इसकी पूरे तौर पर कानूनी मान्यता होगी। तकनीकी भाषा में कहें तो रिजर्व बैंक अगर डिजिटल रुपया जारी करता है, तो यह लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर से आशय ऐसी मुद्रा से है, जिसे लेने से भारत में कोई इनकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कहीं ऐसा चलन हो सकता है कि रेजगारी न होने पर कोई दुकानदार टाफी या चाकलेट दे देता है, पर यह लीगल टेंडर नहीं है। यानी किसी ग्राहक को विवश नहीं किया जा सकता कि वह धनराशि की जगह चाकलेट/ टाफी को स्वीकार करे परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रुपया लीगल टेंडर है, इसलिए इसे किसी वस्तु या सेवा के भुगतान में इसे स्वीकार करना ही होगा। आम मुद्रा की तरह लेन-देन में इसका चलन होगा, लेकिन इसे भौतिक रूप में नहीं, डिजिटल रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इसे डिजिटल बटुए में रखा जा सकेगा और वहीं से भुगतान और ऑनलाइन खरीददारी संभव होगी। इस तरह डिजिटल रुपया कागज के नोट की जगह बदला जा सकेगा तो कुल मिलाकर यह डिजिटल रुपया एक तरह से कागज के नोट का डिजिटल संस्करण होगा।

मुद्रा का डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में अंतर

डिजिटल रुपए के महत्त्व को समझने से पूर्व हमें सर्वप्रथम मुद्रा के डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में अंतर को जानना होगा। वास्तविक मुद्रा के डिजिटलीकरण की

शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के आगमन के साथ हुई थी। इसकी सहायता से वाणिज्यिक बैंक अधिक कुशल और स्वतंत्र तरीके से ऋण के प्रवाह (Cash Flow)को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, हालाँकि इससे देश की बुनियादी मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।इसके विपरीत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा देश की बुनियादी मुद्रा को प्रभावित करती है, जिससे देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा सृजन और आपूर्ति के लिये मौजूदा बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं डिजिटल करेंसी का सृजन कर इसे सीधे उपभोक्ता तक पहुँचा सकेगा।

डिजिटल मुद्रा

यह एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्त्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। यद्यपि यह भौतिक मुद्राओं के समान है, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ-साथ तात्कालिक लेनदेन की अनुमति देती है। डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी (Digital Money) और साइबरकैश (Cyber Cash) के नाम से भी जाना जाता है।

डिजिटल मुद्रा का महत्व

यह बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा। भारत का काफी उच्च मुद्रा-जीडीपी अनुपात सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडी) का एक और लाभ है, इससे काफी हद तक बड़े नकदी उपयोग (सीबीडीसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। हालिया परिवर्तनों को देखें तो मध्य अमेरिका का एक छोटा-सा तटीय देश अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चीन ने वर्ष 2020 में अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया जिसे अनौपचारिक रूप से "डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान,डीसी/ईपी" (Digital Currency Electronic Payment, DC/EP) कहा जाता है।

डिजिटल मुद्रा के पक्ष में

CBDC द्वारा क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल मुद्रा की सुविधा एवं सुरक्षा और पारंपरिक

बैंकिंग प्रणाली के विनियमित, आरक्षित-समर्थित धन परिसंचरण दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं को संयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । डिजिटल मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों के साथ लेन-देन में भारतीय जमाकर्ताओं को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करेगी । उपभोक्ताओं हेतु ई-रूपया (e-rupee) बैंक जमा का एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है जहाँ PhonePe , Google Pay और Paytm जैसे ऐप के माध्यम से लगभग 76 ट्रिलियन रुपए का वास्तविक समय भुगतान/रियल टाइम पेमेंट (Real-Time Payments) होता है । खरीद के ऑनलाइन होने के साथ मांग जमा में विश्वास का आधार (कि वे अंकित मूल्य पर नकद में परिवर्तित हो जाते हैं) एक सैद्धांतिक अवधारणा ही होगी जैसे-जैसे खरीद ऑनलाइन होती है, मांग जमा (Demand Deposits) में विश्वास उत्पन्न करने वाले कई उपाय, जैसे कि अंकित मूल्य पर नकद में परिवर्तन में सैद्धांतिक तौर पर कमी को बढ़ावा दे सकते हैं । ई-मुद्रा परिवर्तनीयता की धारणा को दैनिक वास्तविकता पर निर्धारित कर सकती है । यह सीमा-पार भुगतानों के निपटान हेतु कोरेस्पोंडेंट बैंकों के खर्चीले नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है । विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिये अपने घर पैसा भेजना आसान और सस्ता हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिये बड़ी बचत का निर्माण होगा जो विश्व में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्त्ता देश है ।

डिजिटल मुद्रा के विपक्ष में

यदि ई-कैश (e-cash) लोकप्रिय हो जाता है और RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट में रखी जाने वाली राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है इसी स्थिति में दुर्बल बैंक को अपने पास कम लागत वाली जमा राशि (Low-Cost Deposits) को बनाए रखने हेतु प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है । छोटे बैंकों द्वारा कम लागत वाली जमा राशि की स्थिति में सुधार के बावजूद ऋणदाता अपनी ऋण संपत्ति को छोड़ने और मुनाफे का त्याग करने के प्रति अनिच्छुक बने रह सकते हैं । इसका निहितार्थ है कि लेस लिक्विड बैलेंस शीट (less-liquid balance sheets) अर्थात् बलेंस शीट में तरलता की कमी उन्हें बैंक परिचालन हेतु सुभेद्य बना सकता है । सभी अर्थव्यवस्थाएँ वित्तीय स्थिरता के लिये मौजूद खतरे के प्रति सचेत हैं और उन्नत राष्ट्र भी बैंक नोटों के घटते उपयोग, विशेष रूप से कोविड के बाद को लेकर चिंतित हैं । पूर्णरूपेण अनाम/बेनाम नकदी के विपरीत अधिकांश CBDC को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि केंद्रीय बैंक व्यय का पता लगाने में सक्षम होंगे । हालाँकि बैंकों के साथ किये गए लेन-देन भुगतान ऐप हेतु दृश्यमान नहीं भी हो सकते हैं और फिनटेक फर्म सस्ते ऋणों हेतु चुने जा रहे उन लोगों से संबंधित आँकड़ों से वंचित हो सकती हैं जिनके पास संपार्श्विक नहीं है ।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में अन्य देशों की स्थिति

कुछ देशों ने पहले ही किसी न किसी रूप में CBDC जारी कर रखा है। वर्ष 2020 में बहामास के केंद्रीय बैंक ने एक डिजिटल मुद्रा जारी की थी। दुनिया भर के अधिकतर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं की व्यवहार्यता, उपयोगिता और मूल्य पर विचार कर रहे हैं। चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर CBDC का परीक्षण किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान में दो बड़े देशों में प्रतिस्पर्द्धा की अनुपस्थिति को देखते हुए चीन द्वारा CBDC को अपनाना मजबूरी थी। स्वीडन में बैंक नोट मुद्रा आपूर्ति का महज 1% हैं फिर भी रिक्सबैंक (स्वीडिश सेंट्रल बैंक) द्वारा CBDC को अपनाने की कोई जल्दबाज़ी नहीं की जा रही है। पाँच वर्षों से विभिन्न मूल्यांकनों के बाद भी स्वीडिश मौद्रिक प्राधिकरण ई-क्रोना (e-krona) जारी करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सका है। एस. फ़ेडरल रिज़र्व विश्व की सबसे लोकप्रिय लेखा इकाई के रूप में डॉलर पर आधारित निजी 'स्टेबलकॉइन्स' (Unit of Account) से प्रतिस्पर्द्धा हेतु आधिकारिक मुद्रा जारी करने के बारे में सार्वजनिक परामर्श कर रहा है। डिजिटल यूरो 24 माह लंबे जाँच से गुज़र रहा है। यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक वर्ष 2025 तक इसकी पेशकश कर सकता है। जापान अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने में वर्ष 2026 तक का समय ले सकता है।

डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता

वर्तमान समय में देखा जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डिजिटल मुद्रा को अपना चुकी हैं या अपनाने की कगार पर हैं और भारत भी इस वर्ष के अंत तक डिजिटल मुद्रा को अपना चुका होगा। डिजिटल मुद्रा के आने से सबसे पहले रखरखाव, मुद्रण के रूप में आने वाले व्यय से सीधे तौर पर बचा जा सकता है और दूसरी ओर भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय निगरानी बड़ी सहजता से की जा सकती है। डिजिटल मुद्रा आरंभिक चरण में सभी को लुभा अवश्य रही है किंतु मुझे भय है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इलेक्ट्रोनिक कचड़ा (Electronic Garbage) इतना अधिक बढ़ जाएगा कि सरकार और हमें अभी से उसकी रोकथाम और उसके विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं इसी प्रकार डिजिटल मुद्रा भी अपने साथ संभावनाओं के अपार द्वार ला रही है।

निष्कर्ष : आज का समय प्रतिस्पर्धाओं का है, प्रत्येक क्षेत्र में होड़ लगी हुई है तथा डिजिटल मुद्रा भी इस से अछूती नहीं है। दुनिया के सभी देश इस मुद्रा को अपना चुके

हैं या अपनाने वाले हैं । आज के हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि आधुनिकता का समय डिजिटल मुद्रा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यह आधुनिकता परंपरा का पूर्व रूप हैं जो आगामी दशकों में मुद्रा की नयी परंपरा कायम करेंगी । तकनीक के इस महायुग में आभासी तंत्र हर जगह पर्याप्त रूप से व्याप्त हो चुका है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह कहने में गुरेज नहीं हैं कि डिजिटल मुद्रा अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हैं जहां उपयोगकर्ताओं को भौतिक रूप से ढोने और खोने की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी । यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि यह तकनीकी प्रयोग सामान्य तकनीकी प्रयोग नहीं हैं, देश की मौद्रिक व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है अतः डिजिटल मुद्रा के आगमन में भले ही थोड़ी देर हो जाए किन्तु जब भी आए सशक्त रूप में आए । इस तथ्य में कोई दोहराव नहीं है कि डिजिटल मुद्रा आने वाले कल का भविष्य है इसलिए डिजिटल मुद्रा को सुदृढ़ और सशक्त रूप में अपनाना न केवल आज की मांग है अपितु बदलाव के साथ कदम से कदम मिला कर चल पाने का माध्यम भी है।

संदर्भ :-

- भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट
- दैनिक जागरण समाचार पत्र
- भारत सरकार बजट 2022-2023
- द हिन्दू समाचार पत्र
- नवभारत टाइम्स समाचार पत्र
- जनसत्ता समाचार पत्र

*****

गौतम कुमार

पदनाम:- मुख्य प्रबंधक एवं संकाय
संस्था का नाम:- बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मोबाइल नं. :- 7574820085
ई-मेल:- ba.baroda@bankofbaroda.co.in

एक संस्कृत श्लोक के अनुसार *"लक्ष्मी अर्थात् धन चंचला है"* इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि समय-समय पर धन के रूप-प्रतिरूप परिवर्तित होते रहे हैं। प्राचीनकाल में धन-मुद्रा का अर्थ मवेशी होते थे, बाद में सोने -चांदी के सिक्कों का प्रचलन आया फिर मध्यकालीन भारत में टोकन रूपी सिक्के विनिमय का साधन बने। उसके बाद रुपए या कागजी नोट आए और अब ये कागज़ी मुद्राएं डिजिटल मुद्राओं में परिवर्तित हो रही हैं।

यह सर्वविदित है कि मुद्रा किसी भी राष्ट्र रूपी देह की आर्थिक गतिविधियों का रुधिर है। देश की आर्थिक मजबूती का एक सामान्य मानक वहां की मुद्रा की मजबूती भी है। जिस प्रकार अमेरिका का नाम सुनते ही डॉलर शब्द मस्तिष्क में कौंधता है उसी प्रकार आईएनआर भारतीय रुपये को दर्शाता है।

क्राऊडर के अनुसार, मुद्रा आधुनिक समय में मनुष्य द्वारा किये गए तीन महत्वपूर्ण अविष्कारों : मुद्रा, पहिया और वोट में से एक है।

हमने अपनी स्कूली शिक्षा के अर्थशास्त्र की पुस्तक में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को पढ़ा था:-

मुद्रा मुख्यत: चार कार्य करती हैं:-

1. माध्यम (मीडियम) का
2. मापन (मीजर) का
3. स्तर-मान (स्टैंडर्ड)के रूप में
4. संग्रह कोष (स्टोर) का

यदि भारत की आगामी डिजिटल मुद्रा या डिजिटल रुपया की बात करें जो सरकार

द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होगी तो उपर्युक्त आधारभूत बिन्दु डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में सही बैठती हैं, लेकिन अनियंत्रित या नॉन फिएट (इसकी चर्चा आगे की गई है) मुद्रा जैसे बिटकॉइन आदि कूट मुद्रा के संदर्भ में बिन्दु संख्या 2 एवं 4 अर्थात् मापन (मीजर) तथा स्तरमान (स्टैंडर्ड) के मानकों को पूर्ण नहीं करती।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

21वीं सदी पूरी तरह डिजिटल-सदी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने जिस प्रकार एक आभासी संसार की रचना की है उसी प्रौद्योगिकी ने मुद्रा को भी आभासी रूप देने में कसर नहीं छोड़ी है।

डिजिटल मुद्रा अमूर्त मुद्रा है, जिसे पाँच सौ या दो हजार के कागज़ी नोटों की तरह भौतिक रूप से देख या छू नहीं सकते। भौतिक रूप में किसी परंपरागत टकसाल से डिजिटल मुद्रा का मुद्रण नहीं किया जाता इसलिए इसे आभासी मुद्रा भी कहा जाता है।

2009 में पहली बार बिटकॉइन विश्व के सामने आया था और एक दशक में यह अनौपचारिक रूप से निवेशकों की आँखों का तारा बन गया। हालांकि भारत समेत कई देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को इसके जोखिम को लेकर चेताया भी लेकिन फिर भी लोग लालच वश इससे जुड़े ही रहे।

इसकी लोकप्रियता का मूल कारण अनाप- शनाप लाभ कमाने का लालच रूपी जाल हैं जिसमें कई नौसिखिये फँसकर लाखों रुपये गंवा भी चुके हैं। जून 2022 में ही खबर आ रही थी कि क्रिप्टो-निवेशकों ने 22 लाख करोड़ रुपये गंवा दिये।

इसलिए 2013 में फिर 2016 में और इसके बाद तो हर वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़े शब्दों में (अपने परिपत्रों एवं मीडिया के माध्यम) निवेशकों को चेताया कि अनियमित एवं अनिगमित क्रिप्टो बाजार में निवेश से निवेशक दूर रहें।

हालांकि इस पर लगाम लगाना किसी भी सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा दुष्कर है क्योंकि यह एक ऐसी समांतर डिजिटल कैश प्रणाली है, जो एक ओपन सोर्स कंप्यूटर चेन से जुड़ी हुई है और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। इसे तकनीकी भाषा में "नॉन-फिएट" भी कहते हैं।

वर्तमान प्रश्न : क्या डिजिटल मुद्रा एवं क्रिप्टो करेंसी एक है?

कई बार डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त होती है

लेकिन डिजिटल मुद्रा किसी देश की सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर निर्गत होती हैं एवं इसके मूल्य के पीछे सरकार की गारंटी होती है जैसे आम कागज़ी मुद्रा में होती है।

हालांकि डिजिटल मुद्रा हो या क्रिप्टो मुद्रा दोनों की कार्य विधि एक ही है, दोनों में ही ब्लॉकचेन तकनीक का ही प्रयोग होता है। किन्तु दोनों की कार्यविधि से इतर दोनों की वैद्यता एवं विश्वसनीयता में अंतर है।

क्रिप्टो करेंसी (जैसे "बिटकॉइन", इथेरियम आदि) की विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं होती साथ ही यह मांग एवं पूर्ति के आधार पर ब्लॉकचेन से विकेंद्रित रूप में काम करते हुए अपना मूल्य निर्धारण करती है।

लेकिन वैध डिजिटल मुद्रा जिसे कोई सरकार निर्गत करती हैं वह एक **लीगल टेंडर** के रूप में कार्य करती हैं और उसकी विश्वसनीयता राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा है। इसे तकनीकी भाषा में फिएट करेंसी (मुद्रा) भी कहते हैं।

डिजिटल मुद्रा और बजट 2022-2023 : वर्तमान पहल

डिजिटल मुद्रा अचानक भारतीय वित्तीय प्रणाली में चर्चा का विषय तब बन गई जब माननीय वित्त मंत्री ने बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) जारी की जाएगी।

कोरोना महामारी से युद्ध, कागज रहित (पेपर लेस) अर्थव्यवस्था का स्वप्न एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर गतिमान देश के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है। भविष्य में इस ऐतिहासिक निर्णय को भारतीय मुद्रा एवं वित्तीय बाजार में एक मील के पत्थर एवं साहसिक निर्णय की तरह देखा जाएगा।

भारत जैसे विकासशील देशों पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि ये देश तकनीकी नवाचार को विलंब से अपनाते हैं, इसीलिए ये किसी भी नवोन्मेषी पहल का शुरुआती लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा सीबीडीसी की घोषणा ने विश्व को एक संदेश भी दिया कि अभी अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ इस दिशा में अनिर्णय की स्थिति में है, जबकि भारत ने आधिकारिक रूप से डिजिटल रुपये को डिजिटल अर्थव्यवस्था में शुरुआती प्रयोग करने की घोषणा भी कर दी है।

- भारतीय रिजर्व बैंक की सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगी जबकि अन्य वर्चुअल

करेंसी या क्रिप्टोकरेंसी देश में लीगल टेंडर नहीं हैं लिहाजा वो जोखिम वाले मुद्रा होंगे।

- डिजिटल रुपया भविष्य में भारत की वैध मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
- आरबीआई अधिनियम की धारा-2 और 22 को उस प्रभाव में संशोधित करने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि डिजिटल रुपये संबन्धित कानूनी पहलू को जोड़ा जा सके।

वर्तमान में डिजिटल मुद्रा :वैश्विक पटल पर

सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय अधिकारों को पहचानना चाहिए और साथ ही व्यापार, निवेश और व्यापक सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देना चाहिए. उदाहरण के लिए क्रिप्टो-मुद्रा या बिटकॉइन को लें. यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र इस पर एक साथ काम करें और सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में न जाए, जो हमारे युवाओं को खराब कर सकता है। :- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी

- विश्व के सौ से अधिक देश सीबीडीसी की उपयोगिता पर आरंभिक चरण में काम रहे हैं।
- कुछ देश अभी परीक्षण की अवस्था में हैं तो कुछ अभी इसपर शोध कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो इसे आम जनता के बीच जारी भी कर दिया है।
- मध्य अमेरिका का एक छोटा-सा तटीय देश अल साल्वाडोर डिजिटल मुद्रा को कानूनी रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
- चीन भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है।
- ब्रिटेन भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने की संभावना तलाश रहा है।
- अमेरिकी सरकार भी अपने फेडरल रिजर्व से डिजिटल मुद्रा पर गंभीर रूप से कार्य कर रहा है।

उपर्युक्त बिन्दुओं से यह तथ्य निकल कर सामने आता है कि जो देश इस तकनीक को सुरक्षित रूप से अपनाने में अग्रणी होगा उसकी मुद्रा का बोलबाला और स्वीकार्यता बढ़ेगी साथ ही कई प्रकार के अन्य वित्तीय नवाचरों में आगे बढ़ेगा।

डिजिटल मुद्रा से निहित वर्तमान मुद्दे

यदि भारत जैसे देश समय पर डिजिटल मुद्रा संबधित पहल न करें तो नॉन फिएट क्रिप्टो मुद्रा धीरे –धीरे यहां की अर्थव्यवस्था में घातक रूप से घुसपैठ कर सकती है।

क्रिप्टो मुद्रा में निवेश को लेकर इस बजट में 30 प्रतिशत का कर लगाना इसपर लगाम लगाने की ही एक कवायद है।

वर्तमान समय में करोड़ों लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएँ नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन है। अत: वे बैंक में बिना कोई वैध खाता रखे ही बिटकॉइन जैसे कूट मुद्रा की मदद से छुपा हुआ लेन –देन कर सकते हैं। इस तरह यह बैंकिंग एवं सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है।

भविष्य में डिजिटल मुद्रा से होने वाले लाभ

1) डिजिटल मुद्रा से अर्थव्यवस्था को लाभ

- भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यदि डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से प्रचलन में आ गई तो अरबों रुपये की बचत होगी जो कि नोटों की छपाई में व्यय होती है। निम्न तालिका में मुद्रण खर्च का विवरण जान सकते हैं।

नोट का मूल्य	मुद्रण खर्च (रुपये में)
200	2.93
500	2.94
2000	3.54

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का परिचालन (सर्कुलेशन) 21.1 लाख करोड़ रुपये रहा। यदि डिजिटल मुद्रा का प्रचार –प्रसार बढ़ता है तो इन नोटों के रखरखाव, नोटों के फटने-गलने की संभावना ही ख़त्म हो जाएगी।
- अभी भी हमारा देश जाली नोटों की समस्या से जूझ रहा है और इस जाली मुद्रा से निपटने का सबसे कारगर तरीका है डिजिटल मुद्रा का प्रचलन।
- भारत का काफी उच्च मुद्रा-जीडीपी अनुपात सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडी) का एक और लाभ है, इससे काफी हद तक बड़े नकदी उपयोग (सीबीडीसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है तथा कागज़ी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

2) डिजिटल मुद्रा से बैंकिंग को लाभ

- नागरिकों हेतु ई-रूपया बैंक जमा का एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

- यह बिना किसी इंटर-बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा।
- हालांकि बैंकों के कासा जमाराशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा लेकिन बैंक नवोन्मेषी जमा उत्पाद लाकर एवं उसे डिजिटल मुद्रा से जोड़कर लाभान्वित हो सकते हैं।
- बैंकिंग का मानव श्रम जो नगदी या मुद्रा के भौतिक प्रबंधन एवं वितरण में लगा रहता है उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 3,367 करेंसी चेस्ट और 2,782 छोटे सिक्कों के डिपो हैं। इनके रख रखाव, निगरानी, सुरक्षा पर अरबों रुपये व्यय होते हैं।

3) डिजिटल मुद्रा से नागरिकों को लाभ

- डिजिटल मुद्रा के प्रचलन से नागरिकों को बिना बैंकिंग या वित्तीय पटल माध्यम का इस्तेमाल किए धन-प्रेषण आदि में अधिक सुविधा होगी एवं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर लगाने वाले शुल्क आदि से उन्हें निजात मिलेगी।
- लोगों को भौतिक रुपये या मुद्रा को संभालने / खो जाने आदि के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
- जाली मुद्रा या नोटों से छुटकारा मिलेगा।
- विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिये अपने घर पैसा भेजना आसान और सस्ता हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिये बड़ी बचत का निर्माण होगा जो विश्व में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्त्ता देश है।

आगे की राह एवं निष्कर्ष

सीबीडीसी यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में संप्रभु मुद्रा (सॉवरेन करेंसी) है और केंद्रीय बैंक की तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर देयता (चलन में मुद्रा) के रूप में दिखाई देगी।

किन्तु इसके साथ जुड़ी हुई चुनौतियों का हल भी ढूँढना आवश्यक होगा

1) डिजिटल मुद्रा की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी सुरक्षा। साइबर संसार एक असीमित एवं अछोर समुद्र की तरह है। डिजिटल मुद्रा किसी राष्ट्र की वित्तीय ताकत है अत: इसकी सुरक्षा देश की सरहद की सुरक्षा जितना संवेदनशील है।
2) डिजिटल मुद्रा के परिचालन हेतु ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी या किसी भी अन्य तरीके को गति, मापनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता जैसे परस्पर विरोधी लक्ष्यों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।

3) एक नई तरह के तकनीकी कौशल विकास की जरूरत होगी जो डिजिटल मुद्रा से निहित मामलों को तीव्रता से हल करने के तरीके ढूँढने होंगे।
4) इंटरनेट की उपलब्धता के मामले में भारत जैसे देश में अभी भी विशाल डिजिटल विभाजन को देखते हुए ऑफलाइन उपयोग हेतु एक प्रोटोकॉल पर कार्य करना होगा।
5) भविष्य में डिजिटल मुद्रा के आगमन से कई प्रकार के अधिनियमों जैसे कि आरबीआई के नोट एवं सिक्कों के निर्गत करने के नियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आदि में भी समीचीन परिवर्तन करने होंगे।

स्रोत एवं संदर्भ

- https://rbi.org.in/hindi/home.aspx
- https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials

*****

बसंत कुमार

पदनाम:- वरिष्ठ सहायक
संस्था का नाम:- भारतीय स्टेट बैंक
मोबाइल नं. :- 9904320968
ई-मेल:- basant.kumar5@sbi.co.in

"मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है।"
- मार्शल

वस्तुत: मुद्रा ही वह साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को संभव बनाती है। समय के साथ-साथ मुद्रा के स्वरूप में भले ही परिवर्तन आता रहा हो लेकिन आर्थिक व्यवस्था के हर रूप में मुद्रा के वजूद ने विनिमय व्यवस्था की तरलता बनाए रखी है। चाहे वह कार्मिक का वेतन हो, पूंजीपति का ब्याज हो, श्रमिक की मजदूरी हो, भूमिपति का लगान हो या उद्यमी का लाभ हो, धन का संचरण मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। मुद्रा का महत्व केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित न होकर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्रियता के विकास से भी संबद्ध है। यहां यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मुद्रा आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न अवयवों अर्थात् उत्पादन, उपभोग विनिमय, वितरण और लोक वित्त आदि के घटकों में इस तरह से समाहित है कि उसके बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था के संरचना की कल्पना भी करना बेमानी होगी।

यूं तो भारत में मुद्रा का चलन सोने चांदी और अन्य धातुओं के रूप में लगभग छठी शताब्दी से ही विद्यमान है लेकिन भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिन्दुस्तान ने 1770 में जारी की थी। रुपया एक कागजी मुद्रा है। भारत का केंद्रीय बैंक यानि भारतीय रिज़र्व बैंक नोटों को उनके मूल्य तय करके जारी करता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी मुद्रा भी प्रचलन में है जो डिजिटल है और दुनिया भर में लोगों द्वारा सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए स्वीकार की जा रही है जबकि ये केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी नहीं की जाती है।

इंटरनेट के बढ़े प्रभाव एवं प्रचलन ने डिजिटल मुद्रा के एक नए युग की शुरुआत कर दी

है। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल वालेट का निर्माण कर एक वालेट से दूसरे वालेट में डिजिटल मुद्रा का लेन-देन किया जाता है। इन डिजिटल मुद्राओं का फोन, कम्प्युटर या अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से डिजिटल मुद्रा एक्स्चेंज से क्रय करके विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से इस्तेमाल किया जाता है। इन डिजिटल मुद्राओं को बोल चाल की भाषा में क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है।

मुद्रा का स्वरूप चाहे कुछ भी हो उसकी उपलब्धता, परिचालन प्रणाली और उसका दोषरहित होना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में डिजिटल मुद्रा के विनियमन की स्थिति और चुनौतियों का आकलन करने के लिए इस संदर्भ में विनियामक यानि भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों पर गौर करना अत्यंत जरूरी हो जाता है जिनके परिप्रेक्ष में ही हम विनिमयन का आकलन कर पाएंगे : -

- बैंक नोटों के निर्गम को नियन्त्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यत: देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना।
- मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना।
- वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना।
- विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन करना।
- मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना।
- सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना।
- साख नियन्त्रित करना।

आभासी मुद्रा के लगातार बढ़ते प्रचलन के बीच आज के परिदृश्य में इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति और विनियमन की कमी, उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता और केंद्रीय प्राधिकरण की कमी आभासी मुद्रा के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती है। क्रिप्टो करेंसी से संबन्धित सबसे बड़ी समस्या इसके नियंत्रण और प्रबंधन की है। हाल के वर्षों में क्रिप्टो करेंसी के बाजार मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होती रही है। ऐसे में इसमें निवेशित लोगों के धन की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

बदलते दौर के साथ लाइटकोइन, जैकेश, एथ्यूरम, बिटकाइन आदि डिजिटल मुद्राएं आजकल चर्चा का विषय बन गए हैं। आभासी मुद्रा के आर्थिक जगत मे प्रचलन के

बीच आज के परिदृश्य में इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति और विनियमन की कमी, उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता और केंद्रीय प्राधिकरण की कमी आभासी मुद्रा के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती है। क्रिप्टो करेंसी से संबन्धित सबसे बड़ी समस्या इसके नियंत्रण और प्रबंधन की है। हाल के वर्षों में क्रिप्टो करेंसी के बाजार मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होती रही है। ऐसे में इसमें निवेशित लोगों के धन की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

बदलते दौर के साथ लाइटकोइन, जैकेश, एथ्यूरम, बिटकाइन आदि डिजिटल मुद्राएं आजकल चर्चा का विषय बन गए हैं। आभासी मुद्रा के आर्थिक जगत मे प्रचलन के साथ ही इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति, उपयोगकर्ताओं की गोपनियता के साथ–साथ विनियमन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण की कमी ने डिजिटल मुद्रा के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

डिजिटल मुद्रा की भारतीय पृष्ठभूमि –

वर्तमान में विश्व में कई तरह की डिजिटल करेंसी है। परंतु इसमें सन्निहित जोखिम को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल, 2018 को वर्चुअल करेंसी में ट्रेड पर बैन लगा दिया था। डिजिटल करेंसी को कोई बैंक जारी नहीं करता है। इसे जारी करने वाले ही इसे कंट्रोल करते हैं जबकि पूरी डिजिटल दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। इनमें से बिटकोइन सर्वाधिक लोकप्रिय है परंतु विगत महीनों में इसके मूल्य में भारी-उतार चढ़ाव परिलक्षित हुआ है। निवेशकों को इसके प्रतिकूल प्रभाव से बचाने और उनकी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 (Banning of Crypto currency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019) के ड्राफ्ट में देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रस्ताव किया गया था। इस बिल को व्यापक स्वरूप देते हुए क्रिप्टो करेंसी जारी करने वाले, रखने वाले और इसमें किसी भी प्रकार की डील करने के दोषी पाये जाने वालों के लिए 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक 2013 से ही क्रिप्टो करेंसी के खतरों के बारे में लोगों को आगाह कर रहा था। रिज़र्व बैंक का मानना था कि इसपर शुरुआत से ही रोक लगनी चाहिए थी और ऐसा करने का उसे अधिकार भी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 अप्रैल, 2018 से ही इसपर रोक लगा रखी थी और सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर रखे थे। इंटरनेट और मोबाइल असोशिएशन ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की ओर

से भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 04 मार्च, 2020 को अपने एतिहासिक निर्णय में भारतीय रिज़र्व बैंक का लगभग दो वर्ष पुराना निर्णय खारिज कर दिया और इससे भारत में डिजिटल मुद्रा के युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

विनियमन की वर्तमान स्थिति –

आज जबकि क्रिप्टो करेंसी को उसे जारी करने वाले ही नियंत्रित करते है और उसे जारी करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक या सरकारी नियामक की अनिवार्यता नहीं है, ऐसे में यह एक प्रकार से निजी उद्यम जैसा है। क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है और इसी कारण इनके मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है। 2013 के अप्रैल में बिटक्वाइन की कीमत एक ही रात में 70 फीसदी गिरकर 233 डॉलर से 67 डॉलर पर आ गई थी।

भारी उतार चढ़ाव के कारण क्रिप्टो करेंसी मौलिक करेंसी का स्थान नहीं ले पा रही है और किसी केन्द्रीय विनियामक के द्वारा नियंत्रित नहीं होने के कारण यह संवैधानिक मुद्रा के सभी नैसर्गिक गुणों से काफी दूर है। अब जबकि सरकारी स्तर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगले वित्त वर्ष में CBDT यानि 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' लाने की घोषणा वर्ष 2022 के बजट भाषण के दौरान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी है, इसे देश में लीगल टेंडर के रूप में मान्यता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।

बी आई एस द्वारा वर्ष 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण द्वारा पता चला है कि 86 प्रतिशत केंद्रीय बैंक सीबीडीटी को अपनाने जा रहे है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीबीडीटी भारत की फिएट करेंसी, भारतीय राष्ट्रीय रुपया (INR) जैसी होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज (विनिमय) भी किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि यह संप्रभु मौलिक मुद्रा के प्रतिस्थापन्न के रूप में प्रयोग में आ सकेगी।

आज के समय में डिजिटल करेंसी एक प्रकार से डिजिटल कैश प्रणाली है और इसपर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी यह लोगों में खासकर युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी में जब कोई लेन- देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है। आज दुनिया भर में सैंकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्स्चेंज काम कर रहे हैं। भारत में भी वजीरएक्स, जेबपे, क्वाइनस्विच कुबेर, क्वाइन डीसीएक्स गो समेत कई एक्सचेंज संचालित हो रहे हैं जहां लोग किसी एक

एक्स्चेंज पर अपना पंजीकरण कर क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। निवेश के लिए इनकी उपलब्धता के अलावा क्वाइनबेस और बिनान्से जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। इसमें वस्तुतः किसी विनियामक का नियंत्रण नहीं है और इस कारण निवेशित रकम की प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी भी किसी की नहीं है। पूरा का पूरा क्रिप्टो कारोबार नेटवर्क के द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। इन ब्लॉक चेन प्रक्रिया की निगरानी इनसे जुड़े कुछ लोगों के द्वारा पावरफूल कम्प्युटरों के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार माइनर्स के द्वारा इसकी माइनिंग प्रोसेस की जाती है और बाद में एक्सचेंजों के द्वारा इनकी खरीद और बिक्री की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में विनियामक की कोई भूमिका ही नहीं है।

विनियमन की चुनौतियां –

कागजी मुद्रा के इस्तेमाल मे लगातार कमी आ रही है और भारतीय रिज़र्व बैंक भी डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना चाहता है। अब जबकि विश्व के विभिन्न देश अपनी सीबीडीटी शुरू करने कि योजना पर कार्य करना शुरु कर चुके हैं, नाइजीरिया 'नाइरा', वेनेजुएला 'बॉलिवर' और दक्षिण कोरिया 'डिजिटल युआन' नाम से CBDT लाने वाले हैं तो इस कार्य में यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अमेरिका, रूस चीन और तुर्की भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे है।

इससे यह भी प्रतीत होता है कि विश्व के ज्यादतर देशों ने यह मान लिया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने कि कोशिस करना व्यर्थ है। अतएव वे स्वयं की फिएट क्रिप्टो करेंसी लाने और उसकी विनियमन के चुनौतियों से निबटने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मौलिक मुद्रा के समरूप टैक्स निर्धारण कि चुनौती - डिजिटल करेंसी द्वारा व्यापारिक लेन-देन और पूंजीगत लाभ की स्थिति में टैक्स का निर्धारण और देयता सुनिश्चित करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगी।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) – क्रिप्टो करेंसी के चलन के बाद इसके द्वारा विदेशों में होने वाले भुगतान पर नियंत्रण और फेमा के निर्देशों का अनुपालन करने की बड़ी चुनौती का सामना करना भी विनियामक के लिए प्रमुखता का क्षेत्र होगा।

क्रिप्टो कारेंसी और पारंपरिक करेंसी के विनिमय के लिए समुचित मंच तैयार करना – अब जबकि दोनों ही प्रकार के करेंसी अर्थात् पारंपरिक और क्रिप्टो करेंसी कानूनी रूप से हस्तांतरित होंगे तो इनका आपस में विनिमय करने हेतु समुचित मंच

तैयार करना भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य साबित होने वाला है। विभिन प्रकार के डिजिटल मुद्रा की विश्वसनीयता, मध्यस्थों का आकलन और जारी करने वाली एजेंसियों के साथ ताल-मेल बिठाने का काम भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

ए एम एल और आतंकवाद से संबन्धित चिंताएं – एंटी मनी लॉनड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने में ये डिजिटल करेंसी कहीं अपना योगदान न देना शुरू कर दे, इससे संबन्धित चिंताओं से लगभग सभी देश ग्रस्त है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अतएव समय रहते इस बात को संज्ञान में लेकर इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक है।

पारदर्शिता बनाए रखना और मूल्यों में असामान्य उतार चढ़ाव को रोकने संबंधी चुनौतियां – डिजिटल करेंसी के विनियमन में इसके आभासी स्वरूप के कारण इसके हस्तांतरण के पारदर्शी स्वरूप को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। कई बार सट्टेबाजी के जाल में फंस कर इसके मूल्यों में अस्वाभाविक उतार-चढ़ाव होना शुरू हो जाता है। इस कारण इस करेंसी की विश्वसनीयता ही दांव पर लग जाती है।

उतरोत्तर डिजिटल तकनीक का उन्नयन और फिशिंग तथा हैकिंग से बचाना - अपने डिजिटल स्वरूप के कारण डिजिटल मुद्रा के चलन और विनियमन को उन सभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा जो डिजिटल तकनीक से जुड़ी हैं। इनमें किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम से पूरे व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने की महती ज़िम्मेदारी भी शामिल होगी।

अंतत:

अब जबकि सीबीडीटी के रूप में डिजिटल मुद्रा के रूप में क्रिप्टो करेंसी के एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है, अनिवार्यता इस बात की है कि इस विषय पर गहन छान-बीन कर सावधानी और सहूलियत का खयाल रख कर इसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। साथ ही डिजिटल मुद्रा से संदर्भ में सभी के हितों का ख्याल रखकर इसकी समुचित विनियमन सुनिश्चित की जाए।

संदर्भ:-

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – विकिपीडिया
2. https://www.drishtiias.com.hindi
3. https://www.amarujala.com

*****

ममता वारके

पदनाम:- वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा
संस्था का नाम:- पंजाब नैशनल बैंक
मोबाइल नं. :- 9960309096
ई-मेल:- mamtawarke@gmail.com

भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है और मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में वस्तु-विनिमय चलता था। समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और वस्तु-विनिमय से कठिनाई होने लगी जिसके कारण कौड़ियों से आरंभ हुआ व्यापार धेले, दमड़ी, पाई, आने, खोटे सिक्के से लेकर खरे सिक्कों में होने लगा। यह संसार परिवर्तनशील है, यह प्रकृति भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है । कहते है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और सदियों से आवश्यकताओं के कारण नित नए आविष्कार होते आए हैं। इन अविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। आज के बाजारों में सिक्कों की खनक में कमी आ गयी है और बटुए में कागज़ी रुपये के स्थान पर बाज़ारों में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल पेमेंट के नए माध्यम आ गए हैं। लेकिन इन डिजिटल पेमेंट के माध्यमों से भी सारा लेन-देन रुपए में होता है।

भारत सरकार भी कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में भारत सरकार ने दिनांक 01 जुलाई, 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट अर्थात् डिजिटल इंडिया अभियान की पहल की थी। डिजिटल क्षेत्र में भारत किसी भी देश से कम नहीं है। वर्ष 2015 से 2022 तक के सफर में भारत ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। ज्ञातव्य है कि कोविड 19 महामारी के दौरान डिजिटल अभियान ने आम नागरिकों को किस प्रकार राहत प्रदान कर दी। आज पनवाड़ी की दुकान हो या सब्जीवाला, फलवाला हो या दूधवाला, कामवाली बाई हो या फिर बनिए की दूकान या छोटी-मोटी खरीदारी के बिल भरने से लेकर खुदरा व्यवसायियों के साथ-साथ बड़े व्यवसायी सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग कर रहें हैं। सरकार के साथ ही बैंकों द्वारा भीम यूपीआई, डीजी लॉकर, कोविन इत्यादि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आम नागरिक का जीवन आसान कर दिया। डिजिटलीकरण

अर्थात् नकदी रहित अर्थव्यवस्था से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। डिजिटल क्रांति के व्यापक विस्तार से वसुधैव कुटुम्बकम परिकल्पना को साकार किया है। अब संपूर्ण विश्व एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल रहा है। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व रूप से प्रभावित हुआ है।

डिजिटल इंडिया भारत का सपना है और हम इस सपने को साकार करने की योजना व रणनीति है। हमें यह मानना होगा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह समय की आवश्यकता है। देश के डिजिटलीकरण तथा जनसामान्य तक तकनीक को पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। उनका संदेश है कि विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए समय के साथ हमें नए परिवर्तनों को अपनाना होगा। भारत सरकार ने वैश्विक विकास की गति की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए डिजिटल भारत अभियान का शुभारंभ किया था जिसके अंतर्गत देश के समस्त कार्यालयों, मंत्रालयों, संस्थाओं, वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों को समस्त देशवासियों के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं, सेवाएं, जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपनी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के साथ जोड़ा जा रहा हैं। इंटरनेट के मायाजाल ने शहरों से लेकर गांवों तक मोबाईल की पहुँच से और उसके द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग से मानव जीवन को और आसान कर दिया है।

डिजिटल प्रयोग से हम अपने कार्यों में पारदर्शिता और सटीकता ला सकते हैं एवं समय की बचत भी कर सकते हैं। इससे बैंक की साख कई गुना बढ़ सकेगी। विगत वर्षों में हमने पाया है कि इंटरनेट की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से बैंक तेजी से अपना कार्य कर पा रहा है। इसके सभी माध्यमों द्वारा बैंकिंग लेन-देन नकदीरहित होने लगे है। देखते ही देखते यह हर वर्ग में लोकप्रिय हो गए। नकदी प्रेषण हो या खरीददारी, घर में भुगतान करने में डिजिटल माध्यम का अधिक उपयोग हो रहा है। बैंकों में नकदी निकासी में लगने वाली कतार कम हो गई है।

भारत में डिजिटल करंसी

ज्ञातव्य है कि देश में करेंसी नोटों को छापने का काम केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से किया जाता है। सिक्कों के निर्माण का काम वित्त मंत्रालय (Finance Minister) का होता है। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर अब बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रही है।

यह परिवर्तन हैं भारत को डिजिटल भारत बनाना अर्थात् भारत की मुद्रा को डिजिटल बनाना। जब नगदी रुपये को डिजिटल सिस्टम में स्टोर किया जाता है और उसके इलेक्ट्रोनिक रूप का प्रयोग किया जाता है तो उसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है अर्थात् आपकी मुद्रा को इलेक्टट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल मुद्रा से देश के बैंकिंग सेक्टर और नागरिकों को ऐसा अवसर मिलेगा जहां सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा इस रुपये के आने से आपको बैंक में लंबी कतार लगाना बंद हो जाएगा आपके डिवाईस पर स्टोर डिजिटल मुद्रा कहीं भी त्वरित रूप से भेज सकेंगे।

इसी वर्ष 2022 में सरकार के वार्षिक बजट की घोषणा के समय भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया था कि भारत अगले वित्त वर्ष में डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करेगा जिसे डिजिटल रुपया (Digital Rupee) कहा जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) मुद्रा के जरिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। यह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है जिस बारे में विश्व की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ जल्दबाज़ी में कोई भी निर्णय लेने से बचती रही हैं। डिजिटल रुपए (Digital Rupee) के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भारत की वैध मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व से इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। हालाँकि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency-CBDC) को जल्दबाज़ी में अपनाने से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। साथ ही, सरकार का ध्यान पहले से बाजार में उपलब्ध निजी डिजिटल मुद्राओं का विकल्प उपलब्ध कराने पर भी है, जो हाल ही के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी हैं। दुनियाभर में लाखों लोग वर्तमान में डिजिटल मुद्राओं के कारोबार में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत का केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बाज़ार में लाने से पहले काफी गंभीरता से भारतीय बाज़ार का अध्ययन कर फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।

आगे, डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी, 2022 में मीडिया से बातचीत में कहा था कि डिजिटल मुद्रा बाज़ार में उतारने में कई खतरे हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा था, "सबसे बड़ा खतरा तो साइबर सुरक्षा का है। इसके अलावा नकली मुद्रा का भी खतरा है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत खुदरा और थोक दोनों तरीके से डिजिटल मुद्रा लाने के मॉडलों पर विचार कर रहा है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) द्वारा किसी राष्ट्र विशेष (या क्षेत्र) की अधिदिष्ट या वैध मुद्रा (Fiat Currency) के आभासी रूप का प्रतिनिधित्व करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन का उपयोग करती है। डिजिटल रुपया उपयोगकर्त्ताओं को ऑनलाइन टोकन के रूप में जमा खातों से क्रय शक्ति को स्मार्टफोन वॉलेट में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा, जो नकदी की तरह भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता होगी। एक डिजिटल रुपया एटीएम रहित बैंक नोट की तरह कार्य करेगा।

डिजिटल मुद्रा के लाभ

- बेहतर मूल्यांकन के साथ कार्यान्वयनः काग़ज़ी मुद्रा के घटते उपयोग के साथ मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। यह भारत जैसी उच्च भौतिक नकदी उपयोग वाली अर्थव्यवस्थाओं में अधिक कुशलता लाएगा।
- हालाँकि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण निर्णय का उचित नियोजन और अच्छी तरह से मूल्यांकित कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जल्दबाज़ी में किए गए कार्यान्वयन से लाभ से अधिक हानि की स्थिति बनेगी।
- कठोर केवाईसी मानदंड: डिजिटल रुपया वरदान साबित हो सकता है। मौद्रिक प्राधिकरण के लिये बैंक प्रबंधन को यह नोटिस देने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना गलत नहीं होगा कि वे जमाकर्त्ताओं को कम महत्त्व दें।
- 'अपने ग्राहक को जानें (नो योर कस्टमर) मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है ताकि आतंकी वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुद्रा के दुरूपयोग को रोका जा सके।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका: भारतीय रिज़र्व बैंक को अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखना होगा। डिजिटल मुद्रा के परिचालन हेतु ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी या किसी भी अन्य तरीके को गति, मापनीयता, ऑडिटेबिलिटी, सुरक्षा और गोपनीयता जैसे परस्पर विरोधी लक्ष्यों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।
- भारत जैसे देश में अभी भी विशाल डिजिटल विभाजन को देखते हुए ऑफलाइन उपयोग हेतु एक प्रोटोकॉल पर कार्य करना होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी द्वारा क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल मुद्रा की सुविधा एवं सुरक्षा और पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के विनियमन दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं को संयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- डिजिटल मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों के साथ लेन-देन में भारतीय जमाकर्त्ताओं को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करेगी। उपभोक्ताओं हेतु ई-रूपया (e-rupee) बैंक जमा का एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, जहाँ फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप के माध्यम से लगभग 76 ट्रिलियन रुपए का वास्तविक समय भुगतान (रियल टाइम पेमेंट) होता है।
- खरीद के ऑनलाइन होने के साथ मांग जमा में विश्वास का आधार (कि वे अंकित मूल्य पर नकद में परिवर्तित हो जाते हैं) एक सैद्धांतिक अवधारणा ही होगी। जैसे-जैसे खरीद ऑनलाइन होती है, मांग जमा (डिमांड डिपॉज़िट) में विश्वास उत्पन्न करने वाले कई उपाय, जैसे कि अंकित मूल्य पर नकद में परिवर्तन में सैद्धांतिक तौर पर कमी को बढ़ावा दे सकते हैं।
- ई-मुद्रा परिवर्तनीयता की धारणा को दैनिक वास्तविकता पर निर्धारित कर सकती है।
- यह सीमा-पार भुगतानों के निपटान हेतु संबंधित बैंकों के खर्चीले नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।
- विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिये अपने घर पैसा भेजना आसान और सस्ता हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिये बड़ी बचत का निर्माण होगा जो विश्व में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्त्ता देश है।
- डिजिटल करेंसी उसी तरह काम करेगी जैसे कि अभी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम काम करते हैं अर्थात् अपने स्मार्टफोन से ही ई-रुपये में भुगतान कर सकेंगे या पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे नकदी पर लोगों की निर्भरता घटेगी।
- इसके साथ ही नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई पर होने वाला भारी-भरकम खर्च भी बचेगा। डिजिटल करेंसी आने से नकली रुपयों पर रोक लगेगी। रिश्वतखोरी और बेनामी लेन-देन पर भी काफी हद तक लगाम लगाया जा सकेगा।
- ब्लॉकचेन तकनीकी आधार पर होने से सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं और किसी अनधिकृत व्यक्ति को द्वारा किसी भी हस्तक्षेप या परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सुरक्षित है। हर लेनदेन का रिकार्ड रखता हैं और समय-समय पर रिकार्ड को अद्यतन करता है। अत्यंत कम समय में लेनदेन होता हैं।
- सेवा शुल्क की दरें कम हैं।
- डिजिटल करेंसी को देश की सरकार से मान्यता हासिल होती है। इसलिए इसमें जोखिम नहीं होता है। इसे सॉवरेन मुद्रा में यानी उस देश की करेंसी में बदला जा सकता है।

डिजिटल मुद्रा के समक्ष चुनौतियां :

- भारत देश के समक्ष सर्वप्रथम चुनौती है प्रत्येक गाँव में बिजली की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना ताकि इंटरनेट का प्रयोग करने में सुलभता हो और आसानी से डिजिटल मुद्रा का प्रयोग हो सके।
- प्रत्येक देशवासी को डिजिटल साक्षरता हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रबंधन कराना।
- डिजिटल मुद्रा पूर्ण रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सुरक्षित है, लेकिन कंप्यूटर क्रैश, हैकिंग, वायरस, मालवेयर आदि का खतरा मौजूद है।
- यदि ई-कैश (e-cash) लोकप्रिय हो जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मोबाइल वॉलेट में रखी जाने वाली राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, ऐसी स्थिति में छोटे बैंकों को अपने पास कम लागत वाली जमा राशि को बनाए रखने हेतु प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है।
- छोटे बैंकों द्वारा कम लागत वाली जमा राशि की स्थिति में सुधार के बावजूद ऋणदाता अपनी ऋण संपत्ति को छोड़ने और मुनाफे का त्याग करने के प्रति अनिच्छुक बने रह सकते हैं।
- इसका निहितार्थ है कि लेस लिक्विड बैलेंस शीट (less-liquid balance sheets) अर्थात् तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में तरलता की कमी उन्हें बैंक परिचालन हेतु सुभेद्य बना सकता है।
- सभी अर्थव्यवस्थाएँ वित्तीय स्थिरता के लिये मौजूद खतरे के प्रति सचेत हैं और उन्नत राष्ट्र भी बैंक नोटों के घटते उपयोग, विशेष रूप से कोविड पश्चात परिस्थिति को लेकर चिंतित हैं।
- पूर्णरूपेण अनाम/ बेनाम नकदी के विपरीत अधिकांश सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि केंद्रीय बैंक व्यय का पता लगाने में सक्षम होंगे।
- इसकी खासियत यह है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी (Sovereign Currency) में बदला जा सकता है। भारत में इसे डिजिटल रुपया कहा जा सकता है। डिजिटल मुद्रा दो तरह की होती है। एक को खुदरा (रिटेल) और दूसरे को थोक (होलसेल) रिटेल डिजिटल मुद्रा के नाम से पुकारा जाता हैं। थोक (होलसेल) डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

- हालाँकि बैंकों के साथ किये गए लेन-देन भुगतान ऐप्स हेतु दृश्यमान नहीं भी हो सकते हैं और फिनटेक फर्म सस्ते ऋणों हेतु चुने जा रहे उन लोगों से संबंधित आँकड़ों से वंचित हो सकती हैं जिनके पास संपार्श्विक नहीं है।

डिजिटल मुद्रा के संबंध में वैश्विक स्थिति:

- कुछ देशों ने पहले ही किसी न किसी रूप में CBDC जारी कर रखा है। वर्ष 2020 में बहामास के केंद्रीय बैंक ने एक डिजिटल मुद्रा जारी की थी।
- दुनिया भर के अधिकतर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं की व्यवहार्यता, उपयोगिता और मूल्य पर विचार कर रहे हैं।
- चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी का परीक्षण किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान में दो बड़े देशों में प्रतिस्पर्द्धा नहीं होने को देखते हुए चीन द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी को अपनाना मजबूरी थी।
- स्वीडन में बैंक नोट मुद्रा आपूर्ति का महज 1% हैं फिर भी रिक्सबैंक (स्वीडिश सेंट्रल बैंक) द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी को अपनाने की कोई जल्दबाज़ी नहीं की जा रही है।
- पाँच वर्षों से विभिन्न मूल्यांकनों के बाद भी स्वीडिश मौद्रिक प्राधिकरण ई-क्रोना (e-krona) जारी करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं सका है।
- यू।एस।ए फ़ेडरल रिज़र्व विश्व की सबसे लोकप्रिय लेखा इकाई रूप में डॉलर पर आधारित निजी 'स्टेबलकॉइन्स' (Unit of Account) प्रतिस्पर्द्धा हेतु आधिकारिक मुद्रा जारी करने के बारे में सार्वजनिक रूप से परामर्श कर रहा है।
- डिजिटल यूरो पर 24 माह लंबी जाँच की गयी है यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक वर्ष 2025 तक इसे बाज़ार में ला सकता है।
- जापान अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने वर्ष 2026 तक का समय ले सकता है।

डिजिटल रुपए को अपनाने हेतु जल्दबाज़ी के कारण:

भारत की जल्दबाजी का एक कारण क्रिप्टोकरेंसी जुड़े मुद्दों का समाधान करना है जिसमें भारत के लाखों लोग अपनी राशि निवेश कर चुके हैं। ऐसे लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के जाल से बचाना जो वर्तमान में डिजिटल मुद्राओं के कारोबार में लगे

हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, हालाँकि यह समझना कठिन है कि ई-रुपया रुपया लोगों को तुरंत अमीर बनने के लिये क्रिप्टोकरेंसी अपनाने के लालच से कैसे रोक सकेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण चीन से प्रतिस्पर्द्धा जो अपनी डिजिटल मुद्रा e-CNY (Chinese Yuan Renminbi) बाज़ार में लाने के लिये तैयार है। चीन सीमा पार व्यापार और वित्त में डॉलर के एक प्रतिद्वंद्वी मुद्रा को बढ़ावा देना चाहता है। आदर्श रूप एक बहुवर्षीय परियोजना कार्यान्वयन जल्दबाज़ी करना अनावश्यक जोखिमों से भरा हो सकता है।

सन्दर्भ:

- www.iasdrishti.com

*****

शोकीन फोगाट

पदनाम:- वैज्ञानिक/ अभियंता 'एस.डी.'
संस्था का नाम:- अंतरिक्ष उपयोग केंद्र
मोबाइल नं. :- 8401588205
ई-मेल:- shokeen@sac.isro.gov.in

एक डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टोमुद्रा वित्तीय लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा का एक आभासी रूप है और क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसकी जालसाजी करना लगभग असंभव है। डिजिटल मुद्रा उद्योग वर्ष, 2008 के आसपास बिटकॉइन के लोकप्रिय होने के साथ शुरू हुआ। इसके इसके बाद क्रिप्टो परिदृश्य तेजी से बढ़ा है; जिसमें वर्तमान में दुनिया भर में 10,000 से अधिक डिजिटल मुद्राओं का कारोबार किया जा रहा है।

डिजिटल मुद्रा की विशेषताएं

- बेनामी : डिजिटल मुद्राएं बिना किसी पहचान, क्रेडिट स्कोर या बैंक खाते के उधार देना, बेचना, खरीदना या उधार लेना संभव बनाती हैं।
- अत्यधिक सुरक्षित: इसके निर्माण के सभी अभिलेखों एवं कब इसे भेजा या प्राप्त किया जाता है संबंधी जानकारीयां एक प्रकार की बड़ी डिजिटल खाताबही में संग्रहीत की जाती हैं, जिसे कोई भी आसानी से देख सकता है। इसे चोरी या जब्त नहीं किया जा सकता है और इसे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- हस्तांतरण के लिए सस्ता: डिजिटल इगितल मुद्रा का उपयोग क्रेडिट या पारंपरिक साधनों का उपयोग करने की तुलना में मूल्य को सस्ता और तेजी से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी को क्रिप्टो भेजने की लागत, जिसे नियमित मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, चेक या वायर ट्रांसफर जैसी किसी चीज़ से सस्ता है।
- कोई भौतिक रूप नहीं: डिजिटल मुद्रा भौतिक रूप में मौजूद नहीं है (जैसे कागजी मुद्रा) और आमतौर पर केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है। हालांकि, यह हो सकता है और कई सरकारें अपनी संबंधित फिएट मुद्रा का क्रिप्टो सिक्का संस्करण बनाने के लिए काम कर रही हैं।

- विकेंद्रीकृतः डिजिटल मुद्राएं आमतौर पर केंद्रीय बैंक की मुद्रा के विपरीत विकेंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग करती हैं। जब एक जारीकर्ता द्वारा जारी या जारी करने से पहले डिजिटल माइनिंग किया जाता है, तो इसे केंद्रीकृत माना जाता है। जब विकेन्द्रीकृत नियंत्रण के साथ बनाया जाता है, तो प्रत्येक डिजिटल मुद्रा वितरित खाता प्रौद्योगिकी कहलाती है, जो आम तौर पर एक ब्लॉकचेन है जो सार्वजनिक वित्तीय लेनदेन डेटाबेस के रूप में कार्य करती है।
- प्रयुक्त ब्लॉकचेन तकनीक: ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो डेटा के एन्क्रिप्टेड ब्लॉकों को संग्रहीत करता है और फिर उन्हें डेटा के लिए कालानुक्रमिक एकल स्रोत बनाने के लिए एक साथ श्रृंखलाबद्ध करता है। डिजिटल संपत्ति को कॉपी या ट्रांसफर करने के बजाय वितरित किया जाता है, जिससे संपत्ति का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनता है। परिवर्तनों का एक पारदर्शी बहीखाता दस्तावेज़ की भिन्नता को बनाए रखता है, जो संपत्ति में विश्वास पैदा करता है।

डिजिटल मुद्राओं से संबंधित विभिन्न चुनौतियां:

- गोपनीयता संबंधी चुनौतियां: उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता दांव पर है। डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करने में उपयोगकर्ता के डेटा की गोपनीयता चिंता का विषय है क्योंकि सभी लेनदेन जानकारी वितरित खाता बही में संग्रहीत है, जो सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है।
- उच्च अस्थिरता: बिटकॉइन की कीमत अचानक बढ़कर लगभग $20,000 हो गई और फिर गिरकर $6,000 हो गई। ऐसी घटनाओं के कारण, निवेशकों के लिए डिजिटल मुद्रा तंत्र पर भरोसा करना जटिल है।
- काले धन के लिए गंतव्य: नियामकों और नीति निर्माताओं के बीच डर यह है कि डिजिटल मुद्राएं, फिट मुद्रा के मूल्य का एक वैकल्पिक स्रोत होने के नाते, काले धन को वैध बनाने या आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं: डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के दौरान साइबर सुरक्षा उल्लंघनों और हैकिंग की संभावनाएं प्रबल होती हैं। विभिन्न हमले आम हैं, यहां तक कि कंपनियां और सरकारें भी उनके लिए पूर्ण सुरक्षित नहीं हैं। उदाहरण के लिए स्विस ब्लॉकचैन कंपनी ने बताया है कि उनके बटुए से लगभग $8 मिलियन मूल्य के क्रिप्टो टोकन चोरी हो गए हैं।

- अवैध गतिविधियां: डार्कनेट के माध्यम से नए पैसे से अवैध गतिविधियों जैसे की नशीली दवाओं की बिक्री, हथियार आदि को बढ़ावा देने के लिए गुमनाम तरीके से डिजिटल मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। यह सीमा पार विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में इसके उपयोग के जोखिम को भी बढ़ाता है।
- मौद्रिक नियंत्रण और आर्थिक व्यवहार: यह वैश्विक मौद्रिक नीति निर्माण को नाटकीय रूप से बदल सकता है। लोग नए डिजिटल सिक्के के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का आदान प्रदान करेंगे ताकि इसके आधार पर कई उत्पादों को खरीदा और बेचा जा सके। इससे बैंकों के मुनाफे पर और असर पड़ेगा और उनकी बैलेंस शीट पर दबाव पड़ेगा।
- मुद्रास्फीतिः सरकारों और नीति निर्माताओं के पास मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाएगी। आमतौर पर जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, केंद्रीय बैंक विभिन्न मौद्रिक दरों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते हैं। क्रिप्टोमुद्रा केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी इसलिए तरलता नियंत्रण एक मुद्दा होगा।

डिजिटल मुद्राओं का विनियमन:

डिजिटल मुद्राओं को किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा शुरू, माइनिंग और/ या वितरित किया जा सकता है। तर्क के लिए यदि डिजिटल मुद्राओं को मान्यता/ कानूनी/ विनियमित किया जाना है या सामान्य भाषा में कानूनी निविदा बनाई जाती है तो सवाल उठता है कि क्या सभी डिजिटल मुद्राएं/ सिक्के, डिजिटल टोकन और/ या अपूरणीय टोकन ("एनएफटी) को मान्यता/ वैध/ विनियमित किया जाना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति होती है, तो अचानक बाजार में लेनदेन के लिए अत्यधिक कानूनी निविदाएं उपलब्ध होंगी। यदि कुछ प्रमुख डिजिटल मुद्राओं को ही मान्यता दे दी जाए तब भी प्रत्येक व्यक्ति कानूनी निविदाएं प्रस्तुत करने में सक्षम होगा क्योंकि अधिकांश डिजिटल मुद्राएं अनुमति रहित ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं।

2021 में अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। उस संदर्भ में, कोई यह तर्क दे सकता है कि बिटकॉइन, एथेरियम, डोंगकोइन आदि जैसे कुछ प्रमुख सिक्कों को पहचानने के लिए सरकारों के पास पर्याप्त संसाधन है। हालाँकि, कुछ प्रमुख सिक्कों को पहचानना भी एक सही समाधान नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ विवाद की मुख्य जड़ मान्यता की विशेषता नहीं है, बल्कि

क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाली अंतर्निहित तकनीक है । इसके अलावा, कुछ मात्रात्मक कारक हैं जैसे अस्थिरता, व्यापार की मात्रा, बाजार पूंजीकरण, आविष्कारक की पहचान, आदि, जो चुनिंदा सिक्कों की कानूनी मान्यता को संदिग्ध बना सकते हैं।

डिजिटल मुद्राओं के आसपास संपूर्ण कानूनी, नियामक और नीतिगत कार्रवाई एक विकसित, उत्तरदायी और कभी-कभी एक प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है । संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी विशिष्ट सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दिए बिना डिजिटल मुद्राओं के आदान-प्रदान, उपयोग और रखने पर कर लगाया है। दूसरी ओर, यूनाइटेड किंगडम डिजिटल मुद्राओं को पूंजीगत संपत्ति के रूप में मानता है, इस प्रकार विनिमय के संबंध में मौजूदा टैक्स स्लैब के आधार पर पूंजीगत लाभ कर लगाता है। कनाडा और जर्मनी डिजिटल मुद्राओं के साथ अधिक उदार रहे हैं। पहला इसे एक डिजिटल संपत्ति के रूप में मानता है और केवल बिक्री पर कर लगाता है, जबकि दूसरा इसे निजी धन के रूप में मानता है और एक वर्ष के भीतर स्वैप या बेचे जाने पर कर लगाता है । चुनिंदा सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में पहचानने के बजाय, अधिकांश देशों ने कर लगाना, नियंत्रित मान्यता प्रदान करना और उपयोगकर्ताओं के साथ व्यवहार करने में स्व-प्रकटीकरण तंत्र शुरू करना सबसे अच्छा समझा है।

डिजिटल मुद्राएं और भारत:

भारत में पहले से ही दुनिया में क्रिप्टो निवेशकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस क्षेत्र में व्यापारी और निवेशक सरकारों से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डिजिटल मुद्राओं को मान्यता, वैध और/ या विनियमित किया जाए ताकि अधिक निवेश किया जा सके । हालांकि, इस तरह की मांग के साथ अंतर्निहित समस्या तकनीकी दृष्टिकोण से उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जितनी कि कानूनी दृष्टिकोण से।

यह 2018-19 के बजट भाषण में था जब वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार क्रिप्टोमुद्रा को कानूनी निविदा के रूप में नहीं मानेगी। 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्राओं को बनाने में किसी भी व्यक्ति या संस्था को सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली इसके द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया। वर्ष 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में डिजिटल मुद्राओं के ट्रेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि डिजिटल मुद्राएं कमोडिटी की प्रकृति के हैं और इसलिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

भारत में डिजिटल मुद्राओं के विनियमन की दिशा में कदम:

क्रिप्टोमुद्रा और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 ("ड्राफ्ट बिल") का वर्तमान मसौदा अन्य बातों के साथ-साथ भारत में सभी निजी डिजिटल मुद्राओं को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। उद्योग को स्रोत से प्रतिबंधित/ विनियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का संचालन करने वाली कोई केंद्रीकृत इकाई या प्राधिकरण नहीं है। इसके उपयोग, होल्डिंग, लेन-देन आदि को विनियमित/ प्रतिबंधित किया जा सकता है। सरकार मुख्य रूप से चार कारणों से डिजिटल मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने की पक्षधर है : कीमतों में अस्थिर उतार-चढ़ाव, साइबर हमलों और पोंजी योजनाओं वाले उपभोक्ताओं के लिए जोखिम, बिजली की खपत पर प्रभाव और अंत में इसका संभावित उपयोग आपराधिक गतिविधि में यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद आदि के लिए।

2022 के बजट में, 2022 बिल के माध्यम से सभी डिजिटल मुद्राओं और एनएफटी के संबंध में विनियामक तंत्र को गति देने के लिए आभासी डिजिटल संपत्ति की परिभाषा पेश की गई है । सरकार ने इस परिभाषा के कास्टिंग नेट से किसी भी डिजिटल मुद्रा और/ या एनएफटी को वर्गीकृत या अवर्गीकृत करने की शक्ति बरकरार रखी है। यह प्रावधान संभावित रूप भारत के डिजिटल रुपये या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ("सीबीडीसी") को बेचने के लिए डाला गया है यानी भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा पेश की जाने वाली प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को कर/ विनियमन का विषय बनाया जा रहा है। वित्त विधेयक, 2022 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 ("आईटी अधिनियम") में परिणामी प्रस्तावित संशोधन किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आभासी डिजिटल संपत्ति (डिजिटल मुद्राएं और एनएफटी) के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा।

सरकारी समर्थन के अलावा प्रस्तावित सीबीडीसी और निजी डिजिटल मुद्राओं के बीच एक बुनियादी अंतर है। आमतौर पर बिटकॉइन और एथेरियम जैसी अन्य निजी डिजिटल मुद्राओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुमति रहित ब्लॉकचेन तकनीक के विपरीत, सीबीडीसी एक लाइसेंस प्राप्त ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा । अनुमति रहित ब्लॉकचेन तकनीक एक खुला नेटवर्क है जहां कोई भी निजी व्यक्ति ब्लॉकचैन में नोड्स जोड़कर योगदान कर सकता है। स्वीकृत ब्लॉकचेन तकनीक और विशेष रूप से सीबीडीसी के साथ केवल केंद्र सरकार और सरकार द्वारा प्राधिकृत

अन्य एजेंसियों के पास ही सीबीडीसी की आपूर्ति को नियंत्रित करने, मात्रा में बदलाव करने और/ या नियंत्रित करने का अधिकार होगा। तकनीकी रूप से कहें तो अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन नोड्स में निर्मित एक एक्सेस कंट्रोल परत होती है, जो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को नोड्स बनाने/ जोड़ने से प्रतिबंधित करती है। यह तकनीक बैंकों, सरकारों और/ या ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए बहुत फायदेमंद होती है जबकि इस मामले में यह निश्चित रूप से भारत सरकार के अपने डिजिटल रुपये को सुरक्षित बनाने में कारगर साबित होगी।

आगे का रास्ता:

डिजिटल मुद्रा, अपने सभी जोखिमों के बावजूद, शायद 21वीं सदी की सबसे रोमांचक संपत्ति है। क्रिप्टोमुद्रा के बारे में उत्साहित होने के हजारों कारण हैं, लेकिन क्रिप्टोमुद्रा में आपकी निवेश रणनीति बाजार अनुसंधान एवं सतर्कता पर आधारित होनी चाहिए डिजिटल मुद्राओं के सही उपयोग के लिए सभी हितधारकों को सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है। तदनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने ज्ञान के आधार को अद्यतन करना होगा और अधिक नैतिक विशेषज्ञों के साथ काम करना होगा जबकि साथ ही इस क्षेत्र में जांच के साथ-साथ अपराध का पता लगाने के लिए सहायक सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। सरकार को विकसित देशों से संकेत लेना चाहिए और सुरक्षा उपाय और नियामक संरचना होनी चाहिए। क्रिप्टोमुद्रा विनियमन बिल को पारित करने में तेजी लाने की भी आवश्यकता है।

सन्दर्भ:

- www.rbi.gov.in
- www.indiabudget.gov.in
- www.india.gov.in
- www.investopedia.com
- www.complyadvantage.com

*****

सुरेश पटेलिया

पदनाम:- निजी सचिव
संस्था का नाम:- भाकृअनुप, बोरीयावी, आणंद
मोबाइल नं. :- 9428479305
ई-मेल:- ss.patelia@icar.gov.in

विश्व गुरु बनने के लिए भारत को अपनी डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता है और मोदी सरकार ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है।

पिछले एक दशक से डिजिटल मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है जिन्हें ब्लॉकचेन सॉफ़्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के मामले में ऐसा नहीं है, इसका नियंत्रण इसकी ख़रीद-बिक्री करने वाले लोगों के हाथों में सामूहिक तौर पर होता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती हैं इसलिए उन्हें क्रिप्टोकरेंसी भी कहते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर देशों की सरकारें या तो इन्हें ग़ैर-कानूनी मानती हैं या इन्हें किसी न किसी रूप में नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं।

भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों के विपरीत दक्षिण अमेरिका के देश अल सल्वाडोर ने अब इसके इस्तेमाल पर क़ानूनी मुहर लगा दी है। हालांकि जब क़ानूनी तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के कार्यान्वयन के लिए अल सल्वाडोर ने विश्व बैंक से तकनीकी मदद मांगी तब विश्व बैंक ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे ले कर पारदर्शिता और पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। इधर दूसरी ओर, चीन ने मनी-लॉड्रिंग के इल्ज़ाम में अब तक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े करीब 1100 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। चीन ने डिजिटल करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस क्षेत्र में कदम रखा है, हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होता लेकिन चीन ने जो डिजिटल करेंसी शुरू की है उस पर पूरा सरकारी नियंत्रण है। दरअसल, डिजिटल युआन परंपरागत युआन करेंसी की ही केवल डिजिटल शक्ल है। इसे चीन के कुछ शहरों में प्रयोग के तौर पर पिछले साल शुरू किया गया था। अमेरिका भी डिजिटल डॉलर शुरू करने के बारे में विचार कर रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी की ख़रीद-बिक्री के लिए भारत में इस समय 19 क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट हैं जिनमें वज़ीरएक्स का नाम पिछले दिनों सुर्ख़ियों में था। केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशायालय (ईडी) ने वज़ीरएक्स के संस्थापक और निदेशक निश्चल शेट्टी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के क़ानून के तहत 2,971 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन का हिसाब देने को कहा है। ईडी ने वज़ीरएक्स पर अपने उपयोगकर्ताओं की 'नो योअर कस्टमर' (केवाईसी) यानी ग्राहक वेरिफ़िकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं लेने का आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार वज़ीरएक्स का इस्तेमाल कुछ चीनी नागरिकों ने अपने वज़ीरएक्स वॉलेट में राशि जमा करके किया। वज़ीरएक्स के संस्थापक शेट्टी ने जवाब में तीन ट्वीट किए और इस इल्ज़ाम को नकारते हुए ईडी के साथ पूरा सहयोग का वादा किया।

क्या है डिजिटल मुद्रा ?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वो करेंसी होगी जो केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा। सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान जब क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल, "The Cryptocurrency and Regulation of official digital currency Bill 2021", पारित किया था तो सरकार ने संसद में कहा था कि उसका उद्देश्य **"रिज़र्व बैंक द्वारा जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए सहायक फ्रेमवर्क तैयार करना है।"** डिजिटल रूपी, एक प्रकार की भारतीय क्रिप्टो करेंसी होगी जो कई मायने में दुनिया की दूसरी क्रिप्टोकरेंसी से अलग होगी। यह पूरी तरह से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेगुलेटेड होगी। यही नहीं, ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि यह डिजिटल करेंसी किसके पास है, इसकी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक को होगी। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में डिजिटल करेंसी का ट्रायल करने की योजना बना रही है और दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत हो सकती है।

बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक पिछले कुछ सालों से डिजिटल करेंसी की सेफ्टी और मॉनटरी पॉलिसी पर इसके प्रभाव के साथ-साथ इसके प्रचलन में नकदी सहित विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रहा है। भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिज़र्व बैंक की डिजिटल मुद्रा को सीबीडीसी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को ऑनलाइन रूप में लीगल टेंडर के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। कहने का तातपर्य यह कि डिजिटल रुपया प्रचलन में चल रही फिएट करेंसी का ऑनलाइन वर्जन होगा। इसके

अतिरिक्त **"यह बिल भारत की सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करता है, हालाँकि कुछ विशेष अपवादों को इसके अंतर्गत छूट मिलेगी जिससे क्रिप्टोकरेंसी के प्रयोग और तकनीकी के विकास में मदद मिले।"** हाल में ही भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर काफी सतर्क और सावधान हैं। यह पूरी तरह से नया प्रोडक्ट है, जिसको लेकर वो काफी गंभीर हैं। इस साल के अंत तक हम पूरी तरह से सक्षम होंगे और एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि अपनी डिजिटल करेंसी का पहला परीक्षण शुरू कर सकें। उनके मुताबिक, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एक सेंट्रलाइज लेजर का उपयोग करने और कई पार्टिसिपेंट्स का डिजिटल डेटाबेस रखने के ऑप्शन पर विचार कर रहा हैं। जिसे डिस्ट्रीब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। वहीं, सेंट्रलाइज लेजर के डेटाबेस का स्वामित्व और संचालन केवल केंद्रीय बैंक के पास होगा। दरअसल, नकदी के उपयोग में गिरावट और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके ट्रायल पर विचार करना शुरू किया है। आपको बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक से काफी समय से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर वो अपनी डिजिटल करेंसी की शुरूआत कब करेंगे। खासकर बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ने के बाद यह सवाल भारतीय रिज़र्व बैंक पर कुछ ज्यादा ही दबाव बढ़ाने लगा है। यह ठीक है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिटकॉइन पर बैन तक लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन हटा दिया था। इसी के साइड इफेक्ट्स से निबटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक एक डिजिटल मुद्रा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा है, जिसमें इसकी सुरक्षा, भारत के वित्तीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव के साथ-साथ यह मौद्रिक नीति और प्रचलन में मुद्रा को कैसे प्रभावित करेगा। वहीं, नकदी के उपयोग में गिरावट और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बढ़ती रुचि के बाद केंद्रीय बैंकों ने पिछले एक साल में डिजिटल मुद्राओं की तलाश में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या सीबीडीसी- डिजिटल रूप में कानूनी निविदा कहा जाता है और अनिवार्य रूप से उनकी संबंधित फिएट मुद्राओं का ऑनलाइन संस्करण है। भारत के मामले में वह डिजिटल रुपया होगा। गवर्नर के मुताबिक, हम इसके बारे में बेहद सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि यह भारतीय रिज़र्व बैंक और विश्व स्तर पर पूरी तरह से एक नया उत्पाद है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक एक डिजिटल मुद्रा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहा है, जिसमें इसकी सुरक्षा भारत के वित्तीय क्षेत्र

पर प्रभाव और साथ ही यह मौद्रिक नीति और प्रचलन में मुद्रा को कैसे प्रभावित करेगा । उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक केंद्रीकृत खाता बही या तथाकथित वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) के बीच विकल्प तलाश रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला है । दरअसल, सेंट्रल बैंक केवल साधारण मुद्रा के मूल्य की तरलता को बढ़ाकर अथवा घटाकर उसे नियंत्रित कर सकता है क्योंकि मुद्रा पर सरकारी नियंत्रण काफी हद तक होता है । लेकिन टेक जायंट हमेशा से यह चाहते हैं कि उन्हें कम से कम सरकारी निगरानी में काम करना पड़े। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी एक बेहतर विकल्प बनकर आई, जो कि पूर्णतः सरकारी नियंत्रण से दूर होती है। क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क यह दिया जाता है कि यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा व्यवस्था है। इसका नियंत्रण किसी सरकार के हाथ में नहीं है। किन्तु किसी देश के भीमकाय तंत्र को चलाने के लिए सबसे जरुरी है आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण। क्रिप्टोकरेंसी सरकारी नियंत्रण में नहीं है यह सुनने में भले अच्छा लगे लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण, उसकी निगरानी आवश्यक है। इसके बिना कराधान की जटिल प्रक्रिया की कल्पना नहीं कि जा सकती और उसके बिना प्रशासन का रहना असंभव है।

किन्तु जिस तेजी से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है उसके कारण इसपर प्रतिबंध लगाए रखना भी सही नहीं होगा। अतः सबसे बेहतर विकल्प है कि सरकार अपनी ही एक क्रिप्टो करेंसी निकाले। इस वक्त ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन का चलन जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी भविष्य का डॉलर बन सकती है, वैश्विक आर्थिक ढांचे और मुद्रा व्यवस्था में यह डॉलर का भावी विकल्प बन सकती है। चीन ने इसको समझते हुए पहले ही अपनी डिजिटल मुद्रा निकाल दी थी। चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में यह कहा भी था कि चीन की डिजिटल मुद्रा, वर्तमान मुद्रा व्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य से लाई गई है। इसके जरिए अमेरिका के प्रतिबंधों का डर खत्म हो जाएगा जो डॉलर आधारित वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में रहता है।

अब भारत के लिए भी यही सही होगा कि इसके पूर्व कि चीनी डिजिटल मुद्रा अपना एक इकोसिस्टम तैयार करे, भारत भी इस क्षेत्र में आगे आये। वैसे भी कोरोना ने दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के महत्व का परिचय करवा दिया है । भारत का डिजिटलीकरण अभी जिस अवस्था में है, उसमें भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा।

किन्तु इसके पूर्व कि अमेरिका और चीनी कंपनियां वैश्विक डिजिटल मुद्रा व्यवस्था पर कब्जा जमाए भारत को आगे आना ही होगा। कोरोना के बाद से अमेरिकी फेडरल बैंक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी संख्या में मुद्रा प्रवाहित कर रहे हैं। मुद्रा कि बढ़ती तरलता ने डॉलर की कीमत कम कर दी है और उसका अवमूल्यन हो रहा है। जब यूरोपियन यूनियन एकजुट हुआ और यूरो का चलन बढ़ने लगा तो उसे डॉलर के विकल्प के रूप में पेश किया गया, लेकिन यूरो डॉलर को वैश्विक मुद्रा व्यवस्था से हटा नहीं सका। यही कहानी 2008 की मंदी के बाद युआन के साथ हुई। इसे भी डॉलर का विकल्प मना जा रहा था, किन्तु युआन भी विकप्ल नहीं बन सका। यह दोनों उदाहरण बताते हैं कि वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में डॉलर के वर्चस्व को किसी भी अन्य पेपर करेंसी के जरिये नहीं बदला जा सकता। किन्तु डिजिटल करेंसी इस पूरे ढांचे को ही बदल देगी। देखा जाए तो यह एक ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देगी जैसा इंटरनेट ने 90 के दशक के बाद किया था। डिजिटल करेंसी डॉलर का विकप्ल हो सकती है और भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय डिजिटल मुद्रा ही इस परिवर्तन कि वाहक बने।

जब विनियमन की बात आती है तो डिजिटल मुद्राओं को भारत में एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा सपोर्ट किया जाएगा जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक तरलता, नकदी और डिजिटल मुद्रा लेनदेन दोनों को नियंत्रित करता है। क्रिप्टोकरेंसी के मामले में यह एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली है और एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं है। हालांकि, सभी क्रिप्टो लेनदेन एक विकेन्द्रीकृत खाता बही में दर्ज किए जाते हैं जो सभी के लिए उपलब्ध है। स्थिरता के मोर्चे पर जब लेनदेन की बात आती है तो डिजिटल मुद्राएं स्थिर और प्रबंधन में आसान होती हैं, क्योंकि उन्हें वैश्विक बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर क्रिप्टो बहुत अस्थिर है और दरें लगभग नियमित रूप से बढ़ती और गिरती हैं। डिजिटल मुद्रा लेनदेन का विवरण केवल इसमें शामिल लोगों, प्रेषक और रिसीवर और बैंक के लिए उपलब्ध है। क्रिप्टो लेनदेन का विवरण विकेन्द्रीकृत खाता बही के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है। इसी वर्ष जनवरी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बुकलेट जारी करते हुए कहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। हालांकि यह प्राइवेट करेंसी नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी की लोकप्रियता हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। भारत में सरकार और रेगुलेटरों

को इस पर काफी संदेह है। ऐसे में भारतीय रिज़र्व बैंक इस संभावना की खोज कर रहा है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं और अगर है तो इसे कैसे चालू किया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहा है कि रुपए के डिजिटल एडिशन से क्या फायदा है और यह कितना उपयोगी है।

स्पष्ट है कि जल्द ही अपना भी डिजिटल रुपया होगा जो हमारे आपके लेन-देन का तरीका बदल देगा। रुपया अब पॉकेट में रखने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि जेब से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में परिचालित होगा। न तो ये आपको जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा और इसका प्रिंट भी नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए यह आपके काम आएगा। जैसे- क्रिप्टोकरेंसी 'बिटकॉइन' का क्रेज हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, वैसा ही होगा हमारा अपना डिजिटल रुपया होगा। एक अच्छी बात ये है कि इसे हमारी सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक रेगुलेट करेगा, इसलिए पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा।

संदर्भ :

- इंटरनेट एवं ओपन एक्सेस के माध्यम से सूचना एवं आंकड़ो का संकलन किया गया है।

*****

अमी कार्तिक पटेल

पदनाम:- वरिष्ठ परियोजना सहायक
संस्था का नाम:- भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला
मोबाइल नं. :- 9979607372
ई-मेल:- amee@prl.res.in

प्रस्तावना

मुद्रा एक साधन है जिसके मूल्य से आप सामान और सेवाओं को खरीद सकते हैं। रुपया एक कागज़ी मुद्रा है जो भारतीय रिज़र्व बैंक छापता है जिससे हम रोज़मर्रा की चीजें इत्यादि खरीदते हैं। रुपए का मूल्य रिज़र्व बैंक द्वारा तय होता है।

दूसरी ओर डिजिटल मुद्राएं हैं जो केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी नहीं की जाती हैं। ये मुद्राएं हालांकि लोगों द्वारा दुनिया भर में सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए स्वीकार की जा रही हैं।

एक पारंपरिक बैंक में आपका एक बैंक खाता होता है और बैंक आमतौर पर लेन-देन की प्रक्रिया के लिए कुछ चार्जेस लेता है।

डिजिटल मुद्रा का लेन-देन मूलत: इंटरनेट पर होता है। डिजिटल वॉलेट एक तरह का अकाउंट है जिसमे आप अपनी डिजिटल मुद्रा रखते हैं। इंटरनेट के माद्यम से डिजिटल मुद्रा एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर होता है। इस प्रक्रिया में हमें बैंक के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल वॉलेट को फोन, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

आप डिजिटल मुद्रा को किसी भी अन्य मुद्रा जैसे रुपया, डॉलर आदि के बदले में डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों पर खरीद सकते हैं ।

डिजिटल रुपया: आवश्यकता और महत्त्व :

संदर्भ:

बीते एक दशक में एथरियम और बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं या क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता ने विश्व भर के अधिकांश केंद्रीय बैंकों को उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने पर गंभीरता से विचार करने के लिये मजबूर कर दिया है, जो कि कैशलेस सोसाइटी के लक्ष्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल मुद्रा की कमियों को दूर करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

इस संदर्भ में यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) ने यूरोपीय संघ के लिये 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC) यानी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के मूल्यांकन का इरादा व्यक्त किया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय संस्थाओं को किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेन-देन को सुविधा न प्रदान करने का निर्देश दिया था।

हालांकि बीते दिनों रिज़र्व बैंक ने संकेत दिया था कि वह सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है। विश्व भर में आज ऐसे तमाम देश हैं, जो सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा की संभावना की तलाश कर रहे हैं, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, ऐसे में भारत को डिजिटल मुद्रा विकसित करने हेतु प्रतिस्पर्द्धा में पीछे नहीं रहना चाहिये और जल्द-से-जल्द इस प्रकार की संभावनाओं की तलाश करनी चाहिये।

मुद्रा के डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में अंतर

- डिजिटल रुपए के महत्त्व को समझने से पूर्व हमें सर्वप्रथम मुद्रा के डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में अंतर को समझना होगा।

- मौजूदा वास्तविक मुद्रा के डिजिटलीकरण की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम के आगमन के साथ हुई थी। इसकी सहायता से वाणिज्यिक बैंक अधिक कुशल और स्वतंत्र तरीके से ऋण के प्रवाह को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, हालाँकि इससे देश की बुनियादी मुद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- इसके विपरीत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा देश की बुनियादी मुद्रा को प्रभावित करती है, जिससे देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा सृजन और आपूर्ति के लिये मौजूदा बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं डिजिटल करेंसी का सृजन कर इसे सीधे उपभोक्ता तक पहुँचा सकेगा।

सरकार द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता

- अवैध गतिविधियों पर रोक: एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी (एथरियम और बिटकॉइन आदि) के अराजक डिज़ाइन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें डिजिटल मुद्रा के सृजन और रखरखाव की शक्तियाँ प्रयोगकर्त्ताओं अथवा उपभोक्ताओं के पास होती हैं।
- बिना किसी सरकारी निगरानी और सीमा पार भुगतान में आसानी के कारण इस प्रकार की डिजिटल मुद्रा का उपयोग प्रायः चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के लिये काफी आसानी से किया जा सकता है।
- डिजिटल मुद्रा को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगा सकता है।

अस्थिरता: चूँकि क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल मुद्रा किसी भी संपत्ति अथवा मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं होती है और इसका मूल्य केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिये बिटकॉइन जैसे अन्य क्रिप्टोकरेंसीज़ के मूल्य में काफी अस्थिरता देखने को मिलती है।

- केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को किसी संपत्ति अथवा पारंपरिक मुद्रा का समर्थन प्राप्त होगा, जिसके कारण इसका मूल्य अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे एथरियम और बिटकॉइन की तरह अस्थिर नहीं होगा।
- रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण: अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, इसमें शामिल होने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत केंद्रीय बैंकों ने यह स्वीकार किया कि वे किसी-न-किसी रूप में 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी' (CBDC) पर कार्य कर रहे हैं।

- इसके अलावा चीन भी अपनी डिजिटल रेनमिनबी (चीन की मुद्रा) को लॉन्च करके मुद्रा और भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- ऐसे में भारत के लिये डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना न केवल वित्तीय प्रणाली में बदलाव लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह रणनीतिक दृष्टि से भी काफी आवश्यक है।

डिजिटल मुद्रा छद्म युद्ध: चीन अपनी डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देकर एक नए और उन्नत वैश्विक वित्तीय सिस्टम की स्थापना का प्रयास कर रहा है, वहीं अमेरिका भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिये बीते दिनों अमेरिका की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने लिब्रा (Libra) नामक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिससे चीन की डिजिटल मुद्रा से मुकाबले के लिये अमेरिका की डिजिटल मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

- ऐसे में भारत एक छद्म डिजिटल मुद्रा युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका और चीन नए युग के वित्तीय उत्पादों (डिजिटल मुद्रा) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिये संघर्षरत हैं।
- इस तरह डिजिटल रुपया न केवल वित्तीय नवाचार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच इस छद्म युद्ध में भारत की स्थिति को और अधिक मज़बूत करने के लिये भी काफी महत्त्वपूर्ण है।

डॉलर पर निर्भरता को कम करना: यह भारत को अपने सामरिक साझेदारों के साथ व्यापार हेतु लेन-देन की मुद्रा के रूप में डिजिटल रुपया के प्रभुत्त्व को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही कम हो जाएगी।

डिजिटल रुपए का महत्त्व

- मौद्रिक नीति का तत्काल प्रभाव: डिजिटल रुपए रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपकरण प्रदान कर और अधिक सशक्त बनाएगा।
    - ◊ डिजिटल रुपए के उपयोग से रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष रुप से मुद्रा सृजन और आपूर्ति की शक्ति प्रदान होगी, जिससे नीतिगत बदलावों के प्रभावों को तत्काल प्रतिबिंबित किया जा सकेगा, जबकि अब तक रिज़र्व बैंक अपने नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिये वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर है।

- जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के मौजूदा संकट, PMC बैंक घोटाला और भारतीय वित्तीय प्रणाली की मौजूदा स्थिति हमारे मौजूदा बैंकिंग मॉडल की नाज़ुकता का प्रमाण है।
  - ◊ देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नियामकों को अर्थव्यवस्था में लेन-देन और ऋण प्रवाह की निगरानी में मदद करेगा, जिससे घोटालों और धोखाधड़ी की निगरानी करने में सहायता मिलेगी और जमाकर्त्ताओं के पैसे को भी सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
  - ◊ इसके अलावा यह निवेशकों को मौजूदा अत्यधिक जोखिम वाली डिजिटल मुद्रा की तुलना में एक अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा।
- बैंकिंग प्रणाली के लिये नया आयाम: डिजिटल रुपया बैंकों की अनुमति अथवा उनके साथ साझेदारी किये बिना भारत की लगभग सभी बड़ी प्रोद्योगिकी कंपनियों को फिनटेक (Fintech) कंपनी के रूप में परिवर्तित कर देगा। तकनीकी कंपनियों के लिये उन ग्राहकों को लुभाना आसान होगा, जिनकी पहुँच बैंकिंग सिस्टम तक नहीं है।
- कैशलेस सोसाइटी के लिये महत्त्वपूर्ण: सरकार द्वारा समर्थित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा आम उपयोगकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं को नकदी का उपयोग न करने के प्रति प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण हो सकती है, जो कि कर चोरी पर नियंत्रण हेतु काफी उपयोगी होगा।
  - ◊ डिजिटल रुपया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कैशबैक, पैसे भेजने, ऋण देने, बीमा, शेयर खरीदने और दूसरे वित्तीय लेन-देनों को आसान बना देगा।

स्थिति एवं चुनौतियां : एक अनुमान के मुताबिक, करीब सात लाख भारतीय यूजर्स के पास इस वक्त एक बिलियन डॉलर (करीब 7,290 करोड़ रुपये) से ज्यादा मूल्य के क्रिप्टो असेट्स मौजूद हैं। नया कानून लाने से पहले सरकार अर्थव्यवस्था में मौजूद क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपना रुख भी साफ कर सकती है और इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। फिर भी 2018 में सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्कुलर पर रोक लगाने के साथ इसे प्रचलन में रहने देने की मान्यता दे दी थी। साल 2019 में भी इस कानून

को प्रतिबंध करने की मांग हो चुकी है। हालांकि तब सरकार ने इसको लेकर कोई भी बिल संसद में पेश नहीं किया था। वहीं, क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में कुछ अपवादों को छोड़कर डिजिटल करेंसी के बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है काम

इसी वर्ष जनवरी में आरबीआई ने एक बुकलेट जारी करते हुए कहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। हालांकि यह प्राइवेट करेंसी नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी की लोकप्रियता हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। भारत में सरकार और रेगुलेटरों को इस पर काफी संदेह है। ऐसे में आरबीआई इस संभावना की खोज कर रहा है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं और अगर है तो इसे कैसे चालू किया जाए। आरबीआई यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहा है कि रुपए के डिजिटल एडिशन से क्या फायदा है और यह कितना उपयोगी है।

स्पष्ट है कि जल्द ही अपना भी डिजिटल रुपया होगा जो हमारे आपके लेन-देन का तरीका बदल देगा। रुपया अब पॉकेट में रखने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि जेब से निकलकर वर्चुअल वर्ल्ड में सर्कुलेट होगा। न तो ये आपको जेब में रखने के लिए मिलेगा और न ही इसका प्रिंट होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए यह आपके काम आएगा। जैसे- क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन का क्रेज हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, वैसा ही होगा हमारा अपना डिजिटल रुपया। एक अच्छी बात ये है कि इसे हमारी सरकार, आरबीआई रेगुलेट करेगा, इसलिए पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रुपया, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान तलाशने में मदद करेगा। साथ ही इससे भारतीय नागरिकों को देश की पुरानी बैंकिंग प्रणाली से भी मुक्ति मिलेगी और भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम जुड़ सकेगा। अर्थव्यवस्था में तरलता, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ार आदि पर डिजिटल रुपए के प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत के नीति निर्माताओं द्वारा भारत में सरकार समर्थिक डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। चूँकि आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच छद्म डिजिटल मुद्रा युद्ध देखने को मिल सकता है, इसलिये यदि ऐसे में भारत भी अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और भारत को इसके लिये पहले से ही तैयार रहना चाहिये।

*****

पूजा साव

पदनाम:- अधिकारी (राजभाषा एवं डीसीएस)
संस्था का नाम:- गेल (इंडिया) लिमिटेड, वडोदरा
मोबाइल नं. :- 8820068224
ई-मेल:- puja.shaw@gail.co.in

हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है।

बॉलीवुड के विख्यात अभिनेता आमिर खान की प्रसिद्ध फिल्म थ्री इडियट्स का यह डायलॉग तो हम सभी को याद ही होगा। अपना काम आसान करने और वक्त बचाने के लिए तो मनुष्य ने टेलीफोन, कैल्कुलेटर, गाड़ी आदि अनेक मशीनों का आविष्कार किया। लेकिन मानव समाज ने शायद ही कभी मशीनों को चलाने के लिए मशीन की कल्पना की होगी। मनुष्य को बुद्धिजीवी शायद इसलिए भी कहा जाता है कि ये अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने आसान काम को और भी आसान करने का मार्ग ढूंढ़ ही लेता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलेक्सा नामक यंत्र की जिसका निर्माण मशीनों को चलाने के लिए किया गया। बदलते समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यस्ततम जीवनचर्या के कारण अब हमारे पास समय का अभाव है और प्रत्येक व्यक्ति अपना समय केवल अपने हित में ही उपयोग करना चाहता है। तभी तो अब व्यक्ति घर की सफाई के लिए बाई के पीछे अपना समय व्यतीत करने के स्थान पर रोबोट का उपयोग करना पसंद करता है, चाय की दुकानों से पता पूछकर समय लगाने के स्थान पर गूगल मैप का उपयोग कर शॉटकर्ट लेना पसंद करता है और पैसों के लेन-देन हेतु बैंक की लम्बी कतार में खड़े रहने के स्थान पर ई-बैंकिंग को ही वरीयता देता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मशीनी युग के बाद अब हमारा समाज डिजिटल युग में परिवर्तित हो रहा है। तभी ई-रिक्शा, ई-सिगार, ई-मीटिंग, ई-बैंकिग, ई-भुगतान आदि प्रचलन में है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी ने डिजिटलीकरण की इस प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की है। परिवर्तन प्रकृति का वह अभिन्न नियम है, जिससे हमारे समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहता। जहां तक लेन-देन की बात है, तो समाज के विकास के साथ लेन-देन की प्रक्रिया निरंतर परिवर्तित होती रही है। वस्तुओं के आदान-प्रदान के साथ शुरू

हुई लेन-देन की प्रक्रिया में धीरे-धीरे मुद्रा शामिल हुई, फिर मुद्रा के भुगतान प्रारूप में परिवर्तन के पश्चात ई-भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ हुई और अब मुद्रा का स्वरूप डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित हो रहा है।

वर्ष 2022-23 के लिए संघ का बजट प्रस्तुत करते समय माननीया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए वित्त वर्ष में डिजिटल रूपया जारी किया जाएगा । डिजिटल रूपया एक केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) है, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किया जाएगा।

मन में यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि क्या डिजिटल मुद्रा और मुद्रा का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान दोनों एक ही है? डिजिटल मुद्रा विनियमन को समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि मुद्रा के डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा दोनों में क्या अंतर है? मुद्रा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में हम अपने पास उपलब्ध भौतिक मुद्रा का डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं, जबकि डिजिटल मुद्रा हमारे पास डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होती है और इसका भुगतान भी डिजिटल माध्यम से ही किया जाता है। किसी भी देश की डिजिटल मुद्रा वहां की सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा होती है। वर्तमान में विश्व स्तर पर ऐसे कई देश हैं, जो सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, जिसमें चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं।

हम सभी इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है। चाहे यह प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों के बीच हो, व्यवसाय के बीच हो, विद्यार्थियों के बीच हो या देशों के बीच में हो। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब अन्य देश डिजिटल मुद्रा को अपना रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में भारत कैसे पीछे रह सकता है । शायद इन्हीं परिस्थितियों पर विचार करते हुए माननीया वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल मुद्रा को जारी करने की घोषणा की गई।

क्या है डिजिटल मुद्रा ?

डिजिटल मुद्रा एक प्रकार की धनराशि ही है, जो आपके पॉकेट में न होकर आपके बैंक खाते में होती है। डिजिटल मुद्रा का उपयोग सम्पर्कहीन भुगतान के लिए किया जाता है, जैसे कि आप जब अपने बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर आप अपने फोन में उपलब्ध फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि पेमेंट ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं, अथवा शॉपिंग या बिल का भुगतान करते हैं।

अंतर केवल इतना है कि वर्तमान मुद्रा प्रणाली यानी कागजी (भौतिक) मुद्रा को आप अपने बैंक खाते या एटीएम से आहरण कर सकते हैं और डिजिटल मुद्रा को आप अपने बैंक खाते या एटीएम से आहरित नहीं कर सकते हैं। डिजिटल मुद्रा तीन प्रकार की हो सकती है – सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी।

डिजिटल मुद्रा का विनियमन :

वर्तमान में हमारे देश में डिजिटल मुद्रा के विनियमन से संबंधित कोई भी अधिनियम नहीं है, किन्तु संसद के अगले सत्र में डिजिटल मुद्रा के विनियमन संबंधी बिल पारित होने की संभावना है, जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 दिया गया है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वह मुद्रा होगी जो केन्द्रीय बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा होगी। यह "ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों" पर आधारित होगी।

ब्लॉकचेन तकनीक क्या है और यह कैसे कार्य करती है ?

ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल रूप में उपलब्ध किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, जैसे डिजिटल मुद्रा। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और वितरित करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। ब्लॉकचेन लेनदेन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) के रूप में भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार वर्ष 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे डिजिटल मुद्रा के साथ कई अन्य कामों में भी उपयोग किया जा रहा है। ब्लॉकचेन को डिजिटल मुद्रा का बैकबोन भी कहा जाता है। यह एक सुरक्षित और विकेन्द्रीकृत तकनीक है, जिसे हैक कर पाना लगभग असंभव है। डेटाबेस किसी भी सिस्टम की जानकारी का कलेक्शन होता है। ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा ही होता है। लेकिन यह कई श्रेणियों के तहत जानकारी इकट्ठा करता है, जिसे ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक कई दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं, जो डेटा का एक चेन बनाते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं।

डिजिटल मुद्रा विनियमन की वर्तमान स्थिति : थॉमसन रॉयटर्स इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा क्रिप्टो को सबसे पहले अपनाने वालों में से एक रहा है और

कनाडा राजस्व प्राधिकरण (सीआरए) आम तौर पर देश के आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रिप्टोकरेंसी को एक वस्तु की तरह मानता है। थाईलैंड में, डिजिटल संपत्ति व्यवसायों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं की निगरानी करने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उद्देश्यों के लिए 'वित्तीय संस्थान' माना जाता है।

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के अनुसार मार्केट कैप 1 ।7 ट्रिलियन डॉलर के साथ वर्तमान में 18,142 क्रिप्टोकरेंसी हैं और 460 क्रिप्टो-एक्सचेंज हो रहे हैं। हर 24 घंटे में, $91 बिलियन मूल्य की क्रिप्टो का व्यापार होता है।

स्पष्ट है कि कुछ देशों ने डिजिटल मुद्रा को अपनाना आरम्भ कर दिया है, यानी इसे भविष्य की मुद्रा कहना अनुचित नहीं होगा।

चुनौतियां : किसी भी क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन सदैव उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। कागजी मुद्रा को डिजिटल मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने का भी यही कारण रहा होगा। किन्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी नए कार्य को आरम्भ करते समय कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही डिजिटल मुद्रा के विनियमन में निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है :

- **अवैध गतिविधियां :** चूंकि डिजिटल मुद्रा के सृजन और उसके रखरखाव का अधिकार उपयोगकर्ता के पास होता है, इसलिए इसमें सरकार/ मध्यस्थ संस्थान की निगरानी नहीं होती है। सरकार अथवा किसी मध्यस्थ संस्थान यानी बैंक/ वित्तीय संस्थान की निगरानी के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिम का खतरा हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि डिजिटल मुद्रा को सरकार/ केन्द्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाए, ताकि उचित निगरानी से धोखाधड़ी को रोका जा सके।
- **अस्थिरता :** भारत जैसा देश, जहां अधिकांश नागरिक मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं और जिनके लिए अपनी मेहनत से अर्जित की गई धनराशि की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, ऐसे देश में डिजिटल मुद्रा के विनियमन में इसकी अस्थिरता सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। डिजिटल मुद्रा किसी भी संपत्ति अथवा मुद्रा द्वारा समर्थित नहीं होती है और इसका मूल्य केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिये इसके मूल्य में अस्थिरता देखने को मिलती है। यदि इसे केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाए, तो यह किसी संपत्ति अथवा पारंपरिक मुद्रा द्वारा समर्थित होगी, जिसके कारण इसका मूल्य स्थिर होने की संभावना होगी।

- **डिजिटल मुद्रा छद्म युद्ध :** चीन अपनी डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देकर एक नए और उन्नत वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थापना का प्रयास कर रहा है, वहीं अमेरिका भी इसी दिशा में प्रयासरत है। उदाहरण के लिये बीते दिनों अमेरिका की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने लिब्रा (Libra) नामक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसे अमेरिका द्वारा चीन की डिजिटल मुद्रा के समतुल्य प्रस्तुत किया गया। ऐसी परिस्थिति में भारत डिजिटल मुद्रा के एक छद्म युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि अमेरिका और चीन नए युग के वित्तीय उत्पादों (डिजिटल मुद्रा) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिये संघर्षरत हैं। ऐसे में डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करना और सरलतापूर्वक उसका विनिमय आरम्भ करके अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाना भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
- **डॉलर पर निर्भरता :** अन्य देशों के साथ व्यापार से संबंधित लेन-देन के लिए डॉलर पर निर्भरता भी भारत में डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने के मार्ग में एक चुनौती है। डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा एक अच्छा उपाय होगा। यह भारत को अपने सामरिक साझेदारों के साथ व्यापार हेतु लेन-देन की मुद्रा के रूप में डिजिटल मुद्रा के प्रभुत्त्व को स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता स्वतः ही कम हो जाएगी, क्योंकि केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी होने के कारण डिजिटल मुद्रा के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- **डिजिटल मुद्रा के प्रति साक्षरता :** केन्द्रीय बैंक/ सरकार द्वारा जारी किसी भी नए वित्तीय उत्पाद को जारी करने के पश्चात उपभोक्ता अथवा ग्राहकों को उसके उपयोग के संबंध में साक्षर बनाने की आवश्यकता होती है। डिजिटल मुद्रा के उपयोग के संबंध में उपभोक्ता वर्ग को साक्षर बनाने की दिशा में सबसे पहले डिजिटल मुद्रा के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा क्योंकि इस देश में ऐसे कई लोग हैं, जिनका जीवन केवल अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था में ही व्यतीत हो जाता है और जो इससे थोड़ा आगे जाने का सामर्थ्य रखते हैं, वो अपनी धनराशि के साथ किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी होने के कारण डिजिटल मुद्रा के प्रति लोगों में विश्वसनीयता बढ़ सकती है, जिससे इसके प्रति लोगों को आसानी से साक्षर बनाया जा सकेगा।

डिजिटल मुद्रा की विशेषताएं एवं लाभ

- डिजिटल मुद्रा को देश की सरकार द्वारा मान्य किया जाएगा।
- डिजिटल मुद्रा को देश के केन्द्रीय बैंक के तुलनपत्र (बैलेंस शीट) में शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल मुद्रा के उपयोग से नकद पर निर्भरता नहीं रहेगी।
- डिजिटल मुद्रा को खुदरा/ थोक दोनों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।
- डिजिटल रूप में उपलब्ध होने के कारण प्रिंटिंग के प्रति व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे पैसे और कागज दोनों की बचत होगी, जो आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होने के कारण इसका लेन-देन आसान होगा और लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी यानी उपयोगकर्ता के समय की बचत होगी।

डिजिटल मुद्रा से हानि

जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि किसी भी नई प्रणाली के आरम्भ में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में नई प्रणाली के साथ केवल लाभ ही नहीं बल्कि हानि भी जुड़ी होती है। डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में भी यह मद लागू है। डिजिटल मुद्रा के आरम्भ होने से सबसे बड़ी हानि रोजगार की हो सकती है, जो वर्तमान में हमारे देश की मुख्य समस्या है। कम मैन पावर की आवश्यकता होने के कारण बैंकों/ वित्तीय संस्थानों में रोजगार के क्षेत्र में कमी आ सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा जिसे डिजिटल रुपया के नाम से लॉन्च किए जाने की योजना है, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाने में सहायक होगा। साथ ही इससे पुरानी बैंकिंग प्रणाली में भी परिवर्तन होगा जिससे भारत के बैंकिंग मॉडल में एक नया आयाम जुड़ सकेगा। अर्थव्यवस्था में तरलता, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाज़ार आदि पर डिजिटल रुपए के प्रभाव को देखते हुए यह

आवश्यक है कि भारत में सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। डिजिटल मुद्रा के लाभ और उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह भविष्य की मुद्रा है और इसके प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

- Economic Times
- https://hindi.thequint.com/business/cryptocurrency-bill-modi-government-bitcoin-what-is-the-difference-between-digital-currency-and-crypto
- https://navbharattimes.indiatimes.com/business/budget/budget-news/what-is-blockchain-technology-which-will-be-used-for-rbi-digital-currency/articleshow/89294401.cms
- https://www.punjabkesari.in/business/news/learn-how-cryptocurrency-currency-works-around-the-world-1499331

*****

प्रेम रामनाणी

पदनाम:- वरिष्ठ सहयोगी
संस्था का नाम:- भारतीय स्टेट बैंक
मोबाइल नं. :- 7984233271
ई-मेल:- prem.ramanani@sbi.co.in

वर्ष 2008 में बड़े-बड़े वैश्विक वित्तीय दिग्गज एक-एक कर गिर रहे थे। यूएस शेयर मार्केट की अब तक की 10 सबसे बड़ी दैनिक गिरावटों में से तीन गिरावटें 2008 में दर्ज हुईं। पेड़ गिरता है तो खूब शोर होता है, लेकिन बीज की बुआई एकदम मूक होती है। ठीक उसी तरह, जहां एक ओर प्रस्थापित वित्तीय व्यवस्था के बड़े-बड़े "पेड़ों" के गिरने का हाहाकार मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर 31 अक्तूबर 2008 में भावी वित्तीय जगत के बीज बोए गए। ***सतोशी नाकामोटो*** नामक व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह) द्वारा ***"बिटकोइन: अ पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम"*** शीर्षक से एक विकेंद्रित मुद्रा व्यवस्था की प्रस्तुति करता हुआ *व्हाइट पेपर* प्रकाशित हुआ। दो माह पश्चात 3 जनवरी, 2009 के दिन सर्वप्रथम डिजिटल मुद्रा का सृजन हुआ, जिसे ***बिटकोइन*** नाम दिया गया। उसके करीब दो वर्षों बाद बिटकोइन का प्रथम व्यापारिक प्रयोग हुआ, जब किसी ने 10,000 बिटकोइन में 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। आज वह राशि लगभग $ 571 मिलियन जितनी होती है।

उस घटना के चौदह वर्षों में उस इलेक्ट्रोनिक मुद्रा प्रणाली को अनगिनत नाम दिये जा चुके हैं। जैसे कि- क्रिप्टो करंसी, क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल करन्सी, आभासी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल एसेट्स आदि।

क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा क्या है? इसकी कोई सार्वत्रिक परिभाषा आज तक नहीं बन पाई। कुछ ने इसे मूल्य के आदान-प्रदान की एक विधि; तो कुछ ने इसे एक वस्तु, उत्पाद या एसेट के रूप में चिह्नित किया है। इसके सर्जक *नाकामोटो* ने बिटकॉइन को ब्लॉकचैन नामक अंतर्निहित तकनीक पर आधारित एक नया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम कहा था, जो पूरी तरह से अंतर्वैयक्तिक (peer-to-peer) है, यानि इसमें तृतीय पक्ष यानि कि *थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इन्टरमीडिएरी* की कोई भूमिका

नहीं रहती। सरल अर्थ में कहें तो आभासी मुद्राओं के लिए कोई केंद्रीय नियामक नहीं होगा और उन्हें वैश्विक रूप से दृश्यमान बही-खाते में रखा जाएगा, जो प्रौद्योगिकी के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होगा।

सरल, सुलभ और **निर्बाध** व्यवस्था के चलते सृजन के करीब 14 वर्षों के अंतराल में *बिटकॉइन* जैसी करीब 18,142 क्रिप्टो करन्सी, 460 क्रिप्टो एक्स्चेंज अस्तित्व में हैं। उनका मार्केट कैप $1 ।7 ट्रिलियन जितना है। हर 24 घंटे में $91 बिलियन जितने क्रिप्टो का व्यापार हो रहा है, जिनमें मुख्यतः *बिटकोइन* या *एथेरियम* हैं।

इस प्रकार क्रिप्टो 21वीं सदी का ***हॉट-पिक*** है, लेकिन इसकी निरंकुशता हानिकारक हो सकती है। आज दुनियाभर के शासकों-प्रशासकों-सेंट्रल बैंक नियामकों की आंखें इस बेलगाम घोड़े पर गड़ी हुई हैं।

क्या क्रिप्टोकरेंसी खतरनाक है?

- प्रारंभ में डिजिटल मुद्रा एक ***डाइवर्सिफिक्केशन टूल*** के तौर पर निवेश का एक नवोन्मेशी अवसर प्रदान कर रही थी। परंतु विनियमन के अभाव से धीरे-धीरे यह व्यवस्था तथाकथित रूप से करचोरी, कालाधन संचय, आतंकवाद, दानचोरी, नशीलेपदार्थों का व्यापार, मानव तस्करी, मनी-लॉन्ड्रिंग व अन्य आपराधिक प्रवृतियों के वित्तपोषण के लिए बदनाम होने लगी।
- इस उद्योग में प्रवेश निर्बाध होने के कारण हज़ारों की संख्या में नई-नई डिजिटल करंसी निकलीं और उनकी कीमतों में अंधाधुंध तेज़ी-मंदी, मूल्य में अत्यधिक अस्थिरता होने लगी। बेतहाशा मूल्यवृद्धि भोले-भाले निवेशकों को ललचाने लगी और वे इसके अंतर्निहित जोखिमों को समझे बिना ही *"अनजाने तालाब में कूदने लगे"*।
- अब जब *आईएमएफ़* के ताज़ा अध्ययन में बिटकोइन और एस&पी 500 सूचकांक के बीच एक अंतःसंबंध उजागर हुआ तो निवेशकों के स्टॉकमार्केट एवं क्रिप्टोकरन्सी के बीच बदलते रुझान चिंतित करने लगे।
- उक्त विश्लेषण के तुरंत बाद वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board) ने चेतावनी दी कि यदि क्रिप्टो एसेट्स और पारंपरिक व प्रस्थापित वित्तीय प्रणालियों के बीच अंतःसंबंध इसी गति से बढ़ते रहे तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता का

संतुलन बिगड़ सकता है। क्योंकि जैसे-जैसे डिजिटल मुद्रा प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है उसका पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के साथ मेलजोल और टकराव भी बढ़ रहा है और यह पारस्परिक प्लवन प्रभाव (Spillover Effect) सिस्टमिक अस्थिरता का खतरा उत्पन्न कर रहा है।

ऐसे में प्रभावकारी बन पाने की हद तक विकसित हो चुकी क्रिप्टो व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके अस्तित्व को स्वीकारना अनिवार्य हो चुका है। समय आ चुका है कि डिजिटल मुद्रा के राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरीय नियमन संबंधी विमर्श एवं निर्णयों को प्राथमिकता दी जाए और उस संबंध में ठोस नीति- नियम सभी हितधारकों के समक्ष रखा जाए।

वैश्विक स्थिति

World Economic Forum's Global Future Council on Crypto Currencies के अनुसार अभी तक क्रिप्टोकरन्सी के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समन्वयित नियमन नहीं है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं डिजिटल मुद्रा के जोखिमों के आंकलन व संबंधित नीति प्रतिकारों (Policy Responses) के लिए प्रयासरत हैं।

एक समान उद्देश्य होने के बावजूद अलग-अलग देशों ने विभिन्न तरीकों से विनियमन की राह चुनी है। जहां भारत ने मौजूदा क़ानूनों में बदलाव तो ईयू एवं यूएई ने इसके लिए बिलकुल ही नए नियामकों का गठन करने का रास्ता अपनाया है।

मार्च, 2022 में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा एक कार्यपालक आदेश (Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही डिजिटल मुद्रा के संभावित शक्ति एवं प्रभाव को अब तक की सबसे उच्च स्तरीय गंभीर स्वीकार्यता प्राप्त हुई।

व्हाइट हाउस का यह आदेश अंतर-एजेंसी तालमेल के लिए एक मील का पत्थर है। व्हाइटहाउस अब डिजिटल असेट्स पर अनुसंधान व नियमन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों को प्रवृत कर सकेगा। साथ ही यह आदेश डिजिटल असेट्स एवं संबन्धित तकनीक के संभावित सदुपयोग एवं जोखिम से निपटने के लिए सरकारी तंत्र की सक्रिय भागीदारी को आधिकारिक अभिगम प्रदान करता है।

World Economic Forum's Digital Currency Governance Consortium की स्टीरिंग समिति के अनुसार अमरीकी राष्ट्रपति की यह पहल पारंपरिक वित्तीय

प्रणाली एवं उभरती हुई डिजिटल मुद्रा प्रणाली के आपसी टकराव एवं अन्य जोखिमों के बारे में सोचने एवं सकारात्मक रूप से सुलझाने के लिए रास्ते खोलेगा। इससे क्रिप्टो एसेट्स के नियमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रास्ता खुलेगा और परिणामतः नियमन की लागत भी कम होगी, निवेशकों के हितों की रक्षा होगी और क्रिप्टोअसेट्स के गुनाहित प्रयोग पर रोकथाम लगेगी।

भारतीय परिदृश्य

- किसी भी केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य 1. जनता के हितों की रक्षा, 2. अवैध वित्तीय लेनदेन की रोकथाम, 3. वित्तीय बाज़ारों की पावनता बनाए रखना एवं 4 ।नवोन्मेष को बढ़ावा देना होता है। क्रिप्टो व्यवस्था का तथाकथित रूप से इन सभी उद्देश्यों के विपरीत जाता देख रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जून, 2013 में आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को संभावित वित्तीय, परिचालनीय, कानूनी, ग्राहक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के प्रति चेतावनी दी।
- उसके बावजूद भी जब बैंकों ने क्रिप्टोएक्स्चेंज पर लेन-देन की अनुमति जारी रखी तो आरबीआई समय-समय पर आभासी मुद्रा के प्रति अपनी शंकाओं और चिंताओं को प्रकट किया।
- 2017 के अंत तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि आभासी मुद्रा विधिक मुद्रा (Legal Tender) नहीं है।
- 6 अप्रैल, 2018 को आरबीआई ने सभी व्यापारी, सहकारी, स्माल फ़ाइनेंस बैंकों, एनबीएफ़सी एवं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए आभासी मुद्रा में लेनदेन करने और/या उस हेतु कोई भी सेवा प्रदान करने/ करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके प्रभाव से क्रिप्टोकरन्सी के दाम औंधे मुंह गिरे, एक्स्चेंज फ्रीज़ हो गए।
- आरबीआई के उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मार्च, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के उपरोक्त आदेश को निरस्त कर दिया और इस प्रकार उक्त प्रतिबंध हट गया।
- इस दौरान भारत सरकार ने आभासी मुद्राओं पर अध्ययन करने हेतु एक समिति भी बनाई हुई थी। फरवरी, 2021 में जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी आभासी मुद्रा (CBDC) के अलावा अन्य निजी आभासी मुद्राओं पर भारत में प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश प्राप्त हुई है।

- कुछ दिनों पश्चात ही वित्तमंत्री का एक और वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा- "हम चाहते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में हर तरह के सकारात्मक प्रयोगों के लिए स्थान होना चाहिए। हम अपने मस्तिष्क बंद नहीं कर रहे। (We are not closing our minds.)"
- नवंबर, 2021 आते-आते संसद की वित्तीय स्थायी समिति एवं क्रिप्टोएक्स्चेंज के प्रतिनिधियों, ब्लॉकचैन एंड क्रिप्टोअसेट्स काउंसिल (BACC) के बीच बैठक में यह समाधान निकलता हुआ दिखाई दिया कि क्रिप्टो को प्रतिबंधित नहीं बल्कि नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
- 2021 और 2022 के बजटीय प्रावधानों में डिजिटल एसेट्स का उल्लेख व उन पर अर्जित लाभ को कर के दायरे में लाया गया है। परंतु यह भी स्पष्ट किया गया कि इससे क्रिप्टो को वैधता प्राप्त नहीं हो जाती।
- अब आरबीआई भी अपनी खुद की आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी (सीबीडीसी) लाने की तैयारी में है।

वैश्विक रुझान व समय की मांग को देखते हुए भारत सरकार ने आभासी मुद्राओं को प्रतिबंधित करने की बजाय उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर मन बनाया हुआ प्रतीत होता है। इस हेतु जल्द ही एक ठोस कानून पर भी विमर्श जारी है।

सबसे अधिक स्वीकृत अनुमान यह है कि भारत में किसी भी निजी क्रिप्टो करंसी का प्रयोग लेनदेन या भुगतान हेतु तो वर्जित होगा लेकिन सोना, शेयर या बॉन्ड की तरह उनका डिजिटल एसेट्स के तौर पर संग्रह किया जा सकेगा और फ़िज़िकल रुपये के विकल्प के तौर पर डिजिटल रुपये (CBDC) को आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो सकती है।

मर्यादाएँ / चुनौतियाँ :

धीरे-धीरे विश्व का रुझान अब क्रिप्टो को पूर्ण प्रतिबंधित करने की बजाए उसे नियंत्रित करने का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु जिसका सृजन ही नियंत्रण के उन्मूलन की संकल्पना से किया गया था उसको नियंत्रण के दायरे में लाना आसान खेल नहीं हैं। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई चुनौतियां हैं। जैसे कि:

- सर्वप्रथम डिजिटल मुद्रा की समूची व्यवस्था के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक शब्दावली की रचना की आवश्यकता है। बिना समान मानकों एवं शब्दावली के अभाव में यह व्यवस्था अपरिभाषित या कुपरिभाषित और लचीली बनी हुई है।

- तकनीक पर आधारित होने के कारण मानक तकनीकी व डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल आदि का निर्माण होना चाहिए।

- प्रादेशिक असमानताओं ने ना केवल व्यवस्था को ढीला बनाया हुआ है, बल्कि अनिश्चितता को भी बनाए रखा है, जिससे इस वित्तीय उद्योग की अनुपालन लागत और जवाबदेही निरर्थक बन गई है ।
- टोकनाइज़ेशन, डीसेंट्रलाइज़्ड फ़ाइनेंस, नॉन-फंजिबल टोकन्स जैसे नवीन एप्लीकेशन्स व मॉडल्स एवं डीसेंट्रलाइज़्ड स्वायत्त व्यवस्था मौजूदा वित्तीय प्रणालियों को चुनौती दे रहे हैं और किस को "व्यक्ति" माना जाए, क्या "मूल्य" है और उस "मूल्य" का लेन-देन कैसे होगा? ऐसी सभी पारंपरिक धारणाएं पुनःपरिभाषित करनी पड़ेंगी।
- क्रिप्टो मुद्रा जिस तकनीक पर आधारित है, उसके द्वारा बिना किसी मौजूदा वित्तीय इंटरमिडियरी के भी क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन संभव हो सकती है। इसी वजह से क्रिप्टो का समूचा ढांचा क्रॉस बोर्डर डाटा फ्लो, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पूंजी नियंत्रण की मौजूदा नियामक व्यवस्था के सीधे टकराव में आ रहा है। इस के कारण कर व्यवस्था में विसंगतियाँ व अन्य अनेक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में खलल पहुंच रहा है तथा असंतुलन पैदा हो रहा है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा शुरू करने में भी कई चुनौतियाँ हैं** । **उदाहरणत:** संभावित साइबर सुरक्षा खतरा, आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव, डिजिटल मुद्रा की ट्रैकिंग, कर व्यवस्था में बदलाव, धारक का सत्यापन व प्रामाणिकता, निजता अधिकार का अतिक्रमण, डाटा की सुरक्षा इत्यादि।

कुल मिलाकर एक वैश्विक समन्वित अभिगम के बिना डिजिटल मुद्रा का विनियमन कठिन है और उस समन्वय हेतु देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उच्च स्तरीय साझेदारी करनी पड़ेगी। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए तकनीक का सहारा लेकर जोखिम आंकलन एवं मानक विनियमन नीति निर्धारण करना होगा।

"*सतोषी नाकामोटो* कौन था या कौन है?" आजतक एक रहस्यमयी पहेली है । उस गुमनामी से निकली हुई तकनीक आज 14 वर्षों बाद वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बदलकर रख देने जितनी लोकप्रिय हो चुकी है। आज विश्व उस तकनीक को स्वीकारने या प्रतिबंधित करने के दोराहे पर आकर खड़ा है। इस दोराहे का एक मध्य

मार्ग भी है जो कि सबसे उपयुक्त है और वह हैं विनियमन। समय के साँचे में हर वस्तु ढल जाती है, देशों और संस्थानों के आपसी सहयोग से यह विनियमन की गुत्थी भी जल्दी और सकारात्मक ढंग से सुलझ जाएगी यही आशा है।

"निरंकुशता में अराजकता है, प्रतिबंध में नकारात्मकता है, विनिमय उपयुक्त रास्ता है; परंतु विनियमन ना सरल है, ना सस्ता है, फिर भी परिश्रम और शुभाशय से हर समस्या का समाधान निकलता है। नवोन्मेष आवश्यक है, होना भी चाहिए, परंतु पारदर्शिता और विश्वसनीयता की लागत पर नहीं"

*****

सुमन्त कुमार

पदनाम:- लिपिक (एसडबल्यूओ-ए)
संस्था का नाम:- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मोबाइल नं. :- 9722800315
ई-मेल:- sumant31281@gmail.com

समय का चक्र हमेशा गतिमान रहता है और हम सब इसी चक्र के साथ सतत गतिशील रहते हैं । सभ्यता का उदय एवं विकास इसी चक्र की गतिशीलता का परिणाम रहा है. जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानवीय आवश्यकताएं सतत् बढ़ती गयी और इसी क्रम में अन्य उपयोगी चीजों के साथ मुद्रा का भी उदय हुआ और यह समय के साथ विभिन्न रूपो से होता हुआ वर्तमान में अपने नये रूप डिजिटल मुद्रा के रूप में सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान हो चुका है।

मानव जीवन हमेशा सुलभता का अभ्यस्त रहा है। कितना सुलभ और सहज है मनुष्य सदैव इसे अपनाने की कोशिश करता है. यही स्थिति वर्तमान में मुद्रा विनियमन के साथ भी है। डिजिटल मुद्रा का प्रचार-प्रसार अभी बहुत तेजी से हो रहा है। नई मुद्रा के स्वरूप को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है लेकिन इसका व्यापक प्रचार-प्रसार अभी भी पूर्ण रूप नहीं हो पा रहा है । कठिन प्रश्न यह है कि डिजिटल मुद्रा का विनियमन किस तरह सुचारु रूप से हो और इसे लेकर लोगों में भ्रांतियां है उसे कैसे दूर किया जाए।

डिजिटल मुद्रा का विनियमन में महत्वपूर्ण योगदान हमारा केंद्रीय बैंक है। बजट सत्र 2022 में भारत के वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की घोषणा की गयी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घोषणा भारतीय मुद्रा विनियमन में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाएगा। डिजिटल करेंसी भी अन्य मुद्रा के तरह केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी किया जाएगा और इसकी भी महता धारित मुद्रा के ही तरह होगा।

वर्तमान में पिछले पांच साल का लेखा करे तो डिजिटल भुगतान का चलन भारत में बहुत तेजी से फैला है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका प्रचार-प्रसारबहुत तेजी से हो रहा है। 2016 तक डिजिटल माध्यम से भुगतान केवल 17 ट्रिलियन तक था लेकिन मार्च 2022 तक 30 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर डिजिटल विनियमन अपनी नयी बुलंदियों को छू रहा है।

पहले जहां छोटे-छोटे भुगतान में धारित मुद्रा का बोलबाला था लेकिन वर्तमान में नये पेमेंट गेटवे के माध्यम से डिजिटल विनिमयन के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अभी आबादी का अधिकांश हिस्सा धारित मुद्रा का उपयोग करने पर मजबूर है। इसके लिए बहुत सी चुनौतियां सम्मिलित है।

भारत की अधिकांश आबादी नए डिजिटल माध्यम से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। 2014 से पहले अधिकांश आबादी की पहुंच बैंक तक नहीं थी. बैंकों तक पहुँच होने के बाद अधिकांश लोग बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से अवगत हुए। डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के सुलभता के कारण लोग डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए प्रेरित हुए। पीओएस (POS) मशीन एवं क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान दैनिक उपयोग में लाने लगे। लेकिन अभी भी अधिकांश पारंपरिक दुकानों में नए डिजिटल विनियमन के बजाए धारित मुद्रा में करना बेहतर समझते हैं। उनका इस माध्यम को उपयोग न करने का तर्क धोखाधड़ी एवं इसके बारे में गलत धारणाएं है। यदि उन्हें डिजिटल विनियमन को लेकर जागरूकता एवं फायदे के प्रति आश्वस्त किया जाए तो इसमें महत्वपूर्ण सुधार आ सकता है।

भारतीय आबादी का अधिकांश हिस्सा धारित मुद्रा के रूप में बचत करने में विश्वास रखते है। विशेषकर महिलाएं एवं बुजुर्ग इस माध्यम से बचत करने के लिए ज्यादा आश्वस्त होती है। इसका प्रमुख कारण उनका निजी जीवन में अत्यधिक व्यस्त होना एवं नए-नए धोखाधड़ी के कारण इसके प्रति निराशा करता है। आजकल ऑनलाइन धोखेबाड़ी निरंतर नए रूप ले रहा है। जानकार व्यक्ति भी इसे अपनाने से घबराते है। इसमें यदि सुरक्षात्मक कड़ी जोड़ दिया तो डिजिटल विनियमन का प्रसार और तेजी से हो सकता है।

आजादी के पचहतर वर्षों के बाद भी अधिकांश आबादी में उत्कृष्ट साक्षारता में बहुत कमी है। जब तक लोग उत्कृष्टता की साक्षर नहीं होंगे तब तक डिजिटल विनियमन का लक्ष्य पूरा ही नहीं कर सकते है। दूसरा साक्षरता के साथ-साथ लोगों के अंदर वित्तीय सुरक्षा के प्रति आश्वात होना भी आवश्यक है। जबतक लोग डिजिटल माध्यम से होने वाले ठगी या धोखाधड़ी के प्रति भयभीत रहेंगे तब तक डिजिटल विनियमन के लिए यह राह के रोड़ा साबित होते रहेगा। इसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन ठगी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी इसमें एक सुरक्षात्मक माहौल बनाने में सहायक होगा। इस तरह डिजिटल विनियमन के लिए महत्वपूर्ण रूप से नए मूर्त में साकार किया जा सकता है।

*****

चंदन सिंह

पदनाम:- वरिष्ठ सहायक
संस्था का नाम:- सैक/ इसरो
मोबाइल नं. :- 7016696755
ई-मेल:- cksingh@sac.isro.gov.in

सारांश - विश्व डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा का संचालन और तौर-तरिके में भी बदलाव हो रहें है। वस्तुओं-सेवाओं की लेन-देन का ज्यादातर भुगतान का माध्यम कैश, चेक में या बैंक के अन्य फाइनेंसियल्स टुल्स जैसे एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS) में है। वहीं आजकल जेब में वोलेट हो या न हों मोबाईल में युपीआई के माध्यम से तुरंत भुगतान कर सकते है अथात् हम आज प्रतिदिन लेन-देन के लिए डिजीटल तरीके से भुगतान कर रहें है जैसे- पेटीएम, फोन-पे, गुगल-पे, अमेजन-पे और अन्य बैंक के अनेक युपीआई (UPI) एवं आईएमपीएस के मदद से इत्यादि। भारत विश्व में सबसे तेजी सी डिजिटल पेमेंट करनेवाला देश बन चुका है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने हमारे दिनचर्या के लेन-देन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है जो की कैश-लैस अर्थव्यवस्था में तेजी ला रहा है। आरबीआई (RBI) के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल 3 ट्रिलीयन डॉलर ट्रांजेक्सन डिजिटल मोड में किया गया जो कुल ट्रांजेक्सन का 40% है, और यह 2026 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके आगे अगले चरण में सीबीडीसी(CBDC) का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाएगी. बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंटस (BIS) द्वारा 2021 के अनुसार 186 प्रतिशत देशों के बैंक सीबीडीसी को अपनाने की तैयारी में हैं वहीं लगभग 15 प्रतिशत देश इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे है। भारत वित वर्ष यानि 2022-23 में डिजिटल रूपया लांच करेगा। क्रिप्टोकरेंसी को डेफी (DeFi) यानी विकेंद्रीकृत वित (Decentralized finance) आधारित डिजिटल करेंसी होने के कारण बिचौलिए जैसे ब्रोकरेज एक्सचेंज, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड सेवा प्रदाता के कमीशन लगभग 3 फीसदी होता है जो 100 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था के अरबों डॉलर के बराबर हुई बचत के रूप में होगी जिससे मुद्रा चलन और सुलभ एवं सस्ता होगा। लेकिन इसके

दुष्प्रभाव भी दूरगामी हो सकते हैं जैसे यह पेरिस पर्यावरण सम्मेलन के तय किए गए लक्ष्य को साकार करने में बाधा पहुंचा सकती है. COP 26 का लक्ष्य जीरो 2050 तक जीरो कार्बन से है लेकिन ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो या एनएफटी के ट्रांजेक्सन से अत्यधिक मात्रा में उर्जा की आवश्यकता होती है परिणामस्वरूप कार्बन का उत्सर्जन भी अत्यधिक होता है।

वर्तमान परिपेक्ष्य -

वित्त मंत्री ने इसी वर्ष 2022 का बजट पेश करते हुए एलान किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2022-23 में डिजटल रुपया का शुभारंभ करेगा। यह सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी (CBDC) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई एक डिजिटल मुद्रा होगी। यह ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर आधारित होगा। जो की क्रिप्टोकरेंसी का भी वैकबोन है। सीबीडीसी (CBDC) किसी देश का लीगल टेंडर है जिस तरह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी होती है उसी प्रकार से डिजिटल मुद्रा भी किसी देश के मौद्रीक प्राधिकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिकारिक मुद्रा का एक इलेट्रॉनिक या डिजिटल टोकन है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) द्वारा 2021 के अनुसार 86 प्रतिशत देशों के बैंक सोबीडीसी को अपनाने की तैयारी में है वही लगभग 15 प्रतिशत देश इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरु की गई सीबीडीसी भारत को फिएट करेंसी भारतीय रुपया (INR) जैसी होगी और इसे भौतिक मुद्रा से विनिमय में किया जा सकेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार यह एक इलेक्ट्रानिक मुद्रा होगी। इसके अलावा 2022 के बजट में बिटकॉइन (क्रिप्टोकरेंसी) जैसी वर्चुअल करेंसी से होने वाले मुनाफे पर फ्लैट 30% टैक्स की भी घोषणा की गई थी। गौरतलब है की भारत सरकार इसका संचालन एवं विनियमन करने की अमल पर विचार कर रही है। हम विभिन्न डिजिटल मुद्राओं के वैश्विक प्रारूप एवं विनियमन संबंधी चर्चा करेंगे।

बिटकॉइन (Bitcoin) सबसे पहला क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) है जसे सतोसी नाकोमोतो ने 2008-09 में बनाया था. 2010 में 1 बिटकॉइन (Bitcoin) की कीमत महज 0.06 अमेरीकी डॉलर से भी कम थी, लेकिन जब एक Bitcoin की कीमत 30 लाख रुपये है, जो कि उच्चतम स्तर लगभग 45 लाख को छू चुका था। यह ब्लॉकचेन प्रोद्यौगिकी (Blockchain || Technology) की वजह से हो पाया है। ये एक डिजिटल करेंसी है इसे केवल ऑनलाईन माध्यम से ही वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह एक विकेंद्रिकृत मुद्रा है जिसका मतलब है कि इसपर सरकार या किसी संस्थान का कोई भी नियंत्रण नहीं है.

ब्लॉकचेन एक प्रकार का माझा डेटाबेस है जो एक प्रकार से सामान्य से भिन्न होता है एक सामान्य डेटाबेस डाटा को प्रत्यक्ष तौर पर संग्रहित करता है जबकि ब्लॉकचेन के तहत डाटा को ब्लॉक में संग्रहित किया जाता है जो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं जैसे ही नया डाटा आता है इसे एक ब्लॉक में दर्ज कर लिया जाता है जब एक बार ब्लॉक डाटा से भर जाता है तो इसे पिछले ब्लॉक से सलग्न कर दिया जाता है जो डाटा का कालानुक्रमिक कम में एक साथ लिंक बना देता है। अतः इसके प्लेटफार्म पर जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो चेन मैं जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर पर दिखाई देता है एक अलग प्रकार के डिजिटल असेट नॉनफिजबल टोकन अर्थात् एनएफटी को पहली बार मई 2014 में केवल मैककॉय (Kevin McCoy) बनाया गया था। यह इथेरियम (Ethereum) ब्लॉकचेन तकनीक के साथ काम करता है और उसका मालीकाना हक यानी एक खास व्यति के पास ही है। इसी मालिकाना हक को नॉनफिजबल टोकन या एनएफटी कहा जाता है

आईएमएफ के अनुसार लगभग 90 देश सीबीडीसी (CBDC) की तरफ अपनाने को विचार कर रहे हैं जैसे बहामास में सैंडडॉलर (Sand Dollar) के नाम से, स्वीडन में रिक्सबैंक ने हाल ही इसके प्रद्यौगिकी पर विचार किया है । चीन में रौन्मबी (Renminbi) के ई-सीएनवाई (e-CNY) के नाम से शुभारंभ किया गया है। डेफी (Defi) यानी विकेंद्रीकृत वित (Decentralized finance) आधारित डिजिटल करेंसी होने के कारण बिचौलिए जैसे ब्रोकरेज एक्सचेंज, क्रेडिट/डेबिट कार्ड सेवा प्रदाता के कमीशन लगभग 3 फीसदी होता है जो 100 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था के अरबों डॉलर के बराबर हुई बचत होगी आम आदमी को सीधा लाभ होगा। ट्यूनिशिया ने 2015 में ही ई-दिनार (dinar) का संचालन किया था। इसी तरह कई और देश ने इसे ट्रायल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अतः डिजिटल मुद्रा एक वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए वरदान है और यह विश्व को एक यूनिफॉर्म मुद्रा के माध्यम से जोड़ने की राह पर निकल गई है। कई देशों ने डिजिटल मुद्रा अपनाने को और तेजी से कार्य आरंभ कर दिया है जैसे प्रोजेक्ट यूबीआई (Project UBI) सिंगापुर प्रोजेक्ट ई सीएनवाई (Project e-CNY) चीन प्रोजेक्ट स्टेला (Project Stella), जापान प्रोजेक्ट चैकींग, कम्बोडिया, प्रोजेक्ट पनवर (Project Punbar) जास्ट्रेलिया, प्रोजेक्ट ईथानोन (हॉकी), प्रॉजेक्ट लाईन-रॉक (थाईलैंड) इत्यादि।

विनियमन-:

भारत के संसद में India's Cryptocurrency and Regulation of Official

Digital Currency Bill 2021 पेश किया गया है जिसे आरबीआई का विनियमन की आवश्यक कार्रवाई हेतु एक्सपर्ट कमेटी को भेजा गया जिसे आरबीआई ने 2023 तक इसके शुभारंभ की पेशकश की है और ऐसा माना जा रहा है कि यह ज्यादा सुरक्षित, तेज लेन-देन, सस्ता एवं पारदर्शी होगा । हाल ही में रूस ने किप्टी को जनवरी 2022 में चैन कर दिया था और फरवरी 2022 में इसे ट्रायल के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई और इसे डिजिटल रूबल नाम दिया गया और यूएसए एवं यूरोपियन संघ ने रूस के ऊपर कई प्रत्यारोप लगाए। हाल ही में चल रहे रूस – यूक्रेन युद्ध को लेकर इसमें स्विफ्ट (Swift) प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से अमेरिका ने रूस को बैन कर दिया इसकी वजह से सीबीडीसी (CBDC) यानी डिजिटल करेंसी का महत्व और बढ़ गया है । वही यूक्रेन ने रक्षा संबंधी खरीद की मंजूरी के लिए क्रिप्टो को आधार बना लिया है । हाल ही में ब्लॉकचेन एवं क्रिप्टो परिषद ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि दो करोड़ भारतीय निवेशक ने करीब 53 अरब डालर करीब 15 प्लेटफार्म के माध्यम से निवेश किया है और इसके वैश्विक स्तर पर बाजार पूजी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है ।

डीजीटल मुद्रा के टोकन आधारित इस्तेमाल को हम इस प्रकार समझ सकते हैं ।

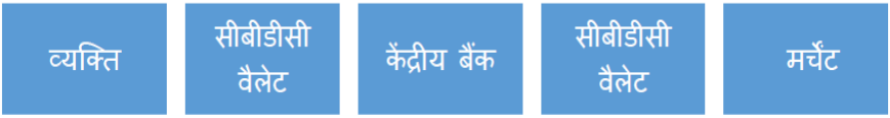

पेमेंट की शुरुआत - सीबीडीसी टोकेन भेजना - सैटलमेंट- सीबीडीसी टोकेन पाना- पेमेंट की जानकारी पाना

चुनौतियां:-

क्रिप्टो करेंसी को जारी रखने का काम विकेंद्रीकृत होता है यह एक वितरित लेजर प्रणाली के जरिए काम करती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है । इसका संचालन एक एल्गोरिथ्म द्वारा होता है । किप्टो करेंसी का महत्व निर्धारण मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है इस व्यवस्था को भारी-भरकम डाटा बैंक की आवश्यकता होती है जो काफी ऊर्जा उत्सर्जन वाले होते हैं । वाणिज्यिक व्यवस्था को भी सभी तरह के लेन-देन डिजिटल करने होंगे ताकि सरकार भौद्रिक स्थानांतरण की निगरानी कर सके और कर संबंधी, धन शोधन कर और अवैध गतिविधियों का

पता लगा सकें। इसके परिचालन से मौद्रिक नीति और मुद्रा बाजार परिचालन में सुधार होगा। चीन से इससे वित्तीय स्वयंत्ता हासिल करने चाहते है और अमेरिकी डॉलर को लेकर जोखिम कम करना चाहते है डिजिटल करेंसी सॉवरिन नियंत्रण को न्यूनतम नुकसान के साथ मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का बेहतरीन रास्ता साबित हो सकता है। चीन के वित्तीय बाजार का आकार 45 लाख करोड़ डॉलर है। जिसमें से 4.2 लाख अमरिकी डॉलर में है।

सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है जो केंद्रिय बैंक आरबीआई द्वारा जारी की जाएगी या फिएट मुद्रा के ही जैसी होगी और इसका भी किया जा सकेगा लेकिन आरबीआई के एक्ट में कुछ संशोधन किए जाएंगे जैसे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसे बैंक नोट जारी करने का प्रावधान है- खंड -24, बैंक नोट के प्रारूप खंड-25 लीगल टेंडर के प्रावधान- खंड 26. The Coinage Act-2011, FEMA 1999, Information Act-2000 आदि।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2013 में क्रिप्टों के खरीदफरोब पर रोक लगा दी थी फिर उसने 2017 मै भी रोक लगा दी थी। 2018 में भारत सरकार ने इसके विनियम संबंधी समीति वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में बनाई थी। मार्च 2020 में उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई को रोक हटाने को कहा था और न्यायमूर्ति नरीमन बोस और वी रामासुब्रमन्यम ने 180 पृष्ठ की न्याय पास की और कहा गया था कि आरबीआई ने अभी तक वर्चुअल मुद्रा के परिपेक्ष्य में कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं और न ही इन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तिय संस्थानों को इसके बारे में अवगत कराया है। फिर 2021 में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रीपरिषद समीति किप्टो एवं डिजिटल मुद्रा के संबंधित प्रस्ताव को विचार करने हेतु विभिन्न एजेंसियों से डाटा प्राप्त किया गया और तपश्चात 2022-23 के में क्रिप्टो के स्थानान्तर पर 30% कर का प्रस्ताव पास किया गया और स्थानांतर के संदर्भ में 1% कर लगाया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा प्रींटिंग में 9 करोड़ व्यय होता है।

*****

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा
वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत में आयोजित हिंदी दिवस समारोह-2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में समिति को श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु 'ख' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। समिति की ओर से यह पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा के अध्यक्ष एवं मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) श्री दिनेश पंत और सदस्य सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा एवं संसदीय समिति) श्री पुनीत कुमार मिश्र ने प्राप्त किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा द्वारा
राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन

दिनांक 18 जुलाई, 2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वडोदरा के संयोजन में केवड़िया, गुजरात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई के अंतर्गत कार्यरत सभी नगर समितियों के लिए **"डिजिटल मुद्रा"** विषय पर हिन्दी माध्यम से राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में नराकास (बैंक), वडोदरा के सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों सहित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, मुंबई के अंतर्गत कार्यरत नगर समितियों के कुल 85 सदस्यों ने प्रतिभागिता की। इस अवसर पर डॉ. सुस्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक (का.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मुंबई विशेष रूप से उपस्थित थीं।